चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | संयुक्तांक | 02 जनवरी– 15 जनवरी 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

कश्मीर कश्मीरियों को सौंपना चाहिए

कमल मोरारका

मैं 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच श्रीनगर के दौरे पर था. इस दौरे के पीछे विचार ये था कि ख़ुद वहां जाकर अपनी आंखों से देखा जाए कि हालात क्या हैं. वहां हो क्या रहा है. किन लोगों ने कश्मीर की जनता को इतना अधिक क्रोधित कर दिया है? मैं वहां के अलगाववादी नेताओं से मिलने में अधिक इच्छुक था. मैं मिला भी. लेकिन, इस मौक़े का फ़ायदा मैंने वहां के समाज के विभिन्न हिस्से के लोगों से मिलने के लिए भी उठाया. मैं संक्षेप में याद कर के आपको ये बताता हूं कि मैंने वहां क्या देखा, क्या बातें की और वहां क्या-क्या घटनाएं घटी हैं.

हुर्रियत नेताओं से मेरी मुलाक़ात

मैं अलगाववादी माने जाने वाले नेताओं में सबसे वरिष्ठ नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिला. गिलानी एक अनुभवी नेता हैं. वह काफी मृदुभाषी आदमी हैं और वह अपने घर तक ही सीमित हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें बाहर निकलने नहीं देती है. यहां तक कि उन्हें नमाज़ के लिए मस्जिद जाने की भी अनुमति नहीं है. लेकिन वह काफ़ी दृढ़संकल्पित हैं. वे इस बात को ले कर काफ़ी स्पष्ट हैं कि जब तक भारत और पाकिस्तान बैठ कर बातचीत नहीं करते हैं, तब तक कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा. उनके समूह की मांग निश्चित रूप से जनमत संग्रह है, जो कश्मीर का एक लंबे समय से लंबित मुद्दा है. लेकिन उनके व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो दिखाता हो कि वह कश्मीर में आम लोगों के लिए व्यवधान या समस्या चाहते हैं. तथ्य यह है कि कुछ दिन पहले उन्होंने पर्यटकों से आह्वान किया है कि पर्यटक बड़ी संख्या में कश्मीर आएं. इस बात के भी सबूत हैं कि कोई भी पर्यटकों को हानि नहीं पहुंचाता है. हिंसक कार्रवाई नाराज़ युवाओं और अर्धसैनिक बलों के बीच ही होती है.

इसके बाद, मैंने मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़, जो हुर्रियत के एक और वरिष्ठ नेता हैं, से मुलाक़ात की. इस मुलाक़ात का परिणाम भी कमोबेश वैसा ही रहा, लेकिन वह बातचीत शुरू किए जाने को लेकर अधिक उत्सुक नज़र आए. वह इस बात से भी काफ़ी ख़ुश नज़र आए कि कम से कम सिविल सोसाइटी कश्मीर में रुचि ले रही है. उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि हमें अपनी तरफ से भारत सरकार को यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि कुछ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है. मैंने मुस्लिम कांफ्रेंस के प्रोफेसर अब्दुल ग़नी बट से भी मुलाक़ात की. वे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं. हालांकि, उनकी पार्टी चुनावी तौर पर एक प्रमुख पार्टी नहीं है, लेकिन ईमानदारी और मूल्यों को ले कर उनकी प्रतिष्ठा बरक़रार है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंसा कहीं नहीं ले जाती है. उनका मानना है कि दिल्ली को चाहिए कि वो श्रीनगर के संपर्क में रहे, बातचीत करे.

मैंने मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ से मुलाक़ात की. इस मुलाक़ात का परिणाम भी कमोबेश वैसा ही रहा, लेकिन वह बातचीत शुरू किए जाने को लेकर अधिक उत्सुक नज़र आए. वह इस बात से भी काफ़ी ख़ुश नज़र आए कि कम से कम सिविल सोसाइटी कश्मीर में रुचि ले रही है.

प्रोफेसर बट हमारे जैसे सिविल सोसाइटी समूह के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं. फिर, हमने नईम ख़ान, जो हुर्रियत के वरिष्ठ सदस्य हैं और जो लंबे समय से भूमिगत हैं, से मुलाक़ात की. उन्होंने भी यही माना कि तब तक कुछ भी नतीजा नहीं आएगा, जब तक दोनों पक्ष बैठ कर बातचीत नहीं करते हैं. अच्छी बात ये है कि इन सभी लोगों में एक सकारात्मक नोट था. कोई भी वास्तव में नकारात्मक नहीं था और गुत्थी को उलझाए रखना नहीं चाहता.

छात्रों, वकीलों और व्यापारियों की सोच अलग है

फिर हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों से मिले, जो वास्तव में कोई आवाज़ नहीं हैं, क्योंकि ख़ुद न्यायपालिका वहां अपने आदेश को कार्यान्वित करवा पाने में सक्षम नहीं है. इन सदस्यों ने एक उदाहरण के जरिए मुझे बताया कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि श्री गिलानी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं. 2009 में फ़ैसला सुनाया गया था और अभी तक पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की है. ज़ाहिर है, यह अदालत की अवमानना का एक स्पष्ट उदाहरण है. लेकिन यही वहां की न्यायपालिका की स्थिति है. पूरे भारत के या कहें कि दुनिया भर के वकील पढ़े-लिखे होते हैं, अच्छी तरह से तथ्यों से वाक़िफ़ होते हैं और उनकी बात भी काफ़ी तर्कसंगत होती है. कश्मीर के किसी भी हिस्से से वे संबंधित हो सकते हैं, कुछ नेशनल कांफ्रेंस, कुछ पीडीपी के हो सकते हैं, कुछ कांग्रेस के हो सकते हैं, लेकिन जहां तक बातचीत का सवाल है, वो पूरी तरह से अराजनैतिक था.

कुछ छात्र मुझसे मिलने आए. जैसा कि हर जगह होता है, यहां भी छात्रों के एक अलग विचार हैं. कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि क्यों हर कोई ये सोचता है कि हम पाकिस्तान या स्वतंत्रता चाहते हैं. हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे साथ उचित तरीक़े से व्यवहार करे. क्यों आप समस्या को और अधिक ख़राब कर रहे हैं? बुरहान वानी के मामले में हर कोई इस बात से सहमत हैं कि यह एक सहज घटना थी. निश्चित रूप से हुर्रियत या किसी अन्य के द्वारा शुरू नहीं किया गया था. यह ऐसा उत्प्रेरक बन गया था, जिसने पहले से ही जमा गुस्से को और भड़का दिया और उस युवक की हत्या ने हालात को नियंत्रण से बाहर कर दिया. हां, यह सही है कि उसके बाद हुर्रियत ने कैलेंडर जारी किया, ताकि हड़ताल में अनुशासन लाया जा सके. एक ऐसी हड़ताल जहां छह महीने सभी दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग अपनी आजीविका खो रहे हैं, स्कूलों-कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है और यह सब बिना किसी भय के स्वेच्छा से होता है. यह एक बड़ा संकेत है, जो बताता है कि हवा किस दिशा में बह रही है.

मैं नहीं जानता कि वो कौन हैं, जो कश्मीर की ज़मीनी हक़ीक़त के बारे में दिल्ली में सरकार को सूचित करते हैं. लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार को बेहतर तरीक़े से सूचित किये जाने की ज़रूरत है. बेशक, सर्दी के मौसम ने इस गुस्से को थोड़ा कम कर दिया है और बताया है कि आप सालों तक इस तरह का एक आंदोलन नहीं कर सकते. छह महीने तक वहां रहत है, लेकिन यह मानना है कि शांति वापस आ गई है, झूठी बात होगी. सन्नाटा, शांति नहीं है. सर्दियों के समाप्त होने के बाद, जब सरकार फिर से श्रीनगर आ जाती है, गतिविधि फिर से शुरू होती है, मैं नहीं जानता कि क्या होगा.

मैंने व्यापारियों के एक समूह से भी मुलाक़ात की. वे फिर से अपने व्यापार को शुरू करने में अत्यधिक रुचि ले रहे थे. मुख्य बात यह है कि इनमें से किसी ने भी हुर्रियत नेताओं के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोला. न ही उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी के ख़िलाफ़ बोला. वे ऐसे चिंतित नागरिक हैं जो सामान्य जीवन चाहते हैं. सामान्य जीवन की वापसी चाहते हैं. असल में मैंने ही उनसे आग्रह किया था कि वे एक लाइन लें, लेकिन सिवाय ये कहने के कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ चर्चा करनी चाहिए, यह एक त्रिपक्षीय चर्चा हो सकती है, वे कोई लाइन नहीं ले सके. वे चाहते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला निकले जिससे श्रीनगर और कश्मीर के अन्य भागों में सामान्य शांतिपूर्ण जीवन की वापसी हो सके.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के नारे खोखले हैं : गिलानी P-4

हम नहीं चाहते कि बच्चे बंदूक़ उठाएं : मीरवाइज़ P-5

अंदर सुलगती आग ज्यादा ख़तरनाक होती है : बट P-6

कश्मीर कश्मीरियों को सौंपना चाहिए

पृष्ठ 1 का शेष

अलगाव की भावना पैदा क्यों होती है

इन सभी लोगों से मुलाक़ात करने के बाद, सवाल है कि इन सब को जोड़ने वाला कॉमन धागा क्या है? दरअसल, आज के युवा जिनमें गुस्सा है, उन्हें कश्मीर के इतिहास का पता नहीं है. लेकिन, मैं क्या कहूं, यहां तो बड़ी उम्र के भी ऐसे लोग हैं, जिनके पास कश्मीर के इतिहास का अपना संस्करण है और वही बताने की कोशिश कर रहे हैं. यहां तक कि अब शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीर के निर्विवाद नेता थे, उनके बारे में भी अलग कहानियां सुनाई जा रही हैं. लोग यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि क्या शेख अब्दुल्ला निर्विवाद नेता थे? यह कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी बात नहीं है. भाजपा ने हमेशा यही किया है और जवाहर लाल नेहरू आदि को दोषी मानती है या जानबूझ कर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है. तथ्य यह है कि शेख अब्दुल्ला एक सुधारवादी थे, वह जमींदारी के ख़िलाफ़ थे. वह जानते थे कि महाराजा के अधीन हिंदू ज़मींदार थे और मुसलमान उनके जोतदार थे. उन्होंने इसमें सुधार किया, संतुलन लाए. बहरहाल, मुझे लगता है कि भारत सरकार को सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, इसे सक्रिय होना चाहिए. उस वक्त किसी के साथ भी कोई बात करने का मतलब नहीं है जब सामान्य नागरिक स्वतंत्रता और मानवधिकार छीन लिए गए हों. ऐसे में जब आप श्रीनगर में धरना नहीं दे सकते, शांतिपूर्ण धरना नहीं कर सकते, आप एक हॉल में बैठक नहीं कर सकते, इससे तो अधिनायकवाद और तानाशाही के संकेत मिल रहे हैं. यह आगे लोगों को अलगाव की ओर धकेलेगा.

मेरे लिए सबसे बड़ा झटका सामान्य लोगों के बीच अलगाव की भावना थी. समस्या ये है कि भारत सरकार शांति के समय भी कड़े कानून का सहारा ले रही है, जिसकी असल में ज़रूरत नहीं है. क्या होगा यदि आप गिलानी को श्रीनगर में घूमने की इजाजत दे देते हैं? क्या होगा यदि शब्बीर शाह को जेल में नहीं रखा जाता है? उन्हें आजाद करने का मतलब ये नहीं है कि कश्मीर भारत से आजाद हो जाएगा. बिल्कुल नहीं! वहां सेना पाकिस्तानी सीमा पर खड़ी है. वह रहेगी भी, कोई इस पर सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन सामान्य नागरिक अधिकार, मानव अधिकार बहाल किया जाना चाहिए. इतना ही नहीं है, वहां इसे ले कर भी नाराजगी है कि अनुच्छेद 370, जिसे कश्मीरियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लागू किया गया था और जिसे मजबूत बनाने की ज़रूरत थी, उसे और कमज़ोर किया जा रहा है. 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर

लिया गया था और 1975 में जब वे फिर से मुख्यमंत्री बने, इस बाईस साल के बीच लगभग सभी कानूनों को ऐसा बनाया गया, जो 370 को औपचारिक बना कर रख देने वाले थे. कोई भी ये तर्क दे सकता है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद, शम्सुहीन, जी एम सादिक और सैयद मीर कासिम के समय उन प्रस्तावों को विधानसभाओं से पारित किया गया था. ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मौजूदा विधान सभा क्यों नहीं उन प्रस्तावों को रद्द कर सकती है? फ़ारूक़ अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की लंबे समय तक सरकारें रही हैं. वे प्रस्ताव ला सकते थे और कह सकते थे कि उस वक्त जो प्रस्ताव लाए गए थे, उन्हें हम खत्म करते हैं. वे कह सकते थे कि हम अपना क़ानून लागू करेंगे, हमें भारत के क़ानूनों को यहां लागू करने की ज़रूरत नहीं है.

लेकिन ये सब कानूनी और तकनीकी मामले हैं. जमीनी हक़ीक़त ये है कि कश्मीर के लोग खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आर्थिक मसलों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय दिया, इससे वे गुस्सा हैं. वे भारतीय स्टेट बैंक से ऋण चाहते हैं. यह तर्कसंगत है. ऋण कुछ कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन अलगाव की भावना मनोवैज्ञानिक है. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को व्यापारियों और बैंकों के बीच संतुलन लाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त होना चाहिए. यहां के लोग आरोप लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी भारत बनाम कश्मीर कार्ड खेल रही है. यह सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केवल एक क़ानून की व्याख्या कर रही है, लेकिन जब भारत सरकार भारत और कश्मीर के बीच इस दीवार को खड़ी करती है, तो मुझे डर है कि अलगाव की ये भावना दूर नहीं होगी. अगर आज यह भावना जारी रहती है तो कल पांच या दस साल बाद भी समाधान नहीं निकलेगा. कश्मीर के लोग केंद्र सरकार द्वारा दिए गए भाषणों जिसमें टेररिस्ट मनी, एटीएम में कोई कतार नहीं है, से सहमत नहीं हैं. वहां एटीएम में इसलिए कतार नहीं है क्योंकि सर्दियों के मौसम आने से पहले लोग स्वाभाविक तौर पर घर में दो से तीन महीनों का खाद्य भंडारण कर लेते हैं. इसलिए वहां एटीएम में कोई कतार नहीं है. इसलिए, वे भारत के अन्य भागों की तरह नहीं हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उन्हें तकलीफ़ नहीं दी है. विमुद्रीकरण से वे गहरे तक प्रभावित हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मुंबई प्रभावित हुआ है.

अब हम यहां से कहां जायेंगे? मेरे हिसाब से अगर सरकार केवल सुरक्षा नेटवर्क के माध्यम से कश्मीर को देखना चाहती है, या राष्ट्रीय सुरक्षा, सलाहकार, सेना, गृह मंत्रालय के नज़रिए से देखना चाहती है तो समस्या है. कश्मीरियों को अगर विदेश जाना है तो उन्हें भारतीय पासपोर्ट ही चाहिए, इस तरह वे क़ानूनी तौर पर भारत का

मेरे लिए सबसे बड़ा झटका सामान्य लोगों के बीच अलगाव की भावना थी. समस्या ये है कि भारत सरकार शांति के समय भी कड़े क़ानून का सहारा ले रही है, जिसकी असल में ज़रूरत नहीं है. क्या होगा यदि आप गिलानी को श्रीनगर में घूमने की इजाज़त दे देते हैं? क्या होगा यदि शब्बीर शाह को जेल में नहीं रखा जाता है? उन्हें आज़ाद करने का मतलब ये नहीं है कि कश्मीर भारत से आज़ाद हो जाएगा.

ही हिस्सा हैं. लेकिन उनके दिमाग़ और दिल भारत के साथ नहीं हैं. क्यूं? क्योंकि उनके मन में यह भावना बार-बार आती है कि हम जन्म से कश्मीरी हैं और बिहार या केरल या तमिलनाडु से आया हुआ एक सैनिक हमसे हर कुछ किलोमीटर बाद हमसे हमारी पहचान (आईडी) पूछता है. ये सेना के जवान कश्मीर से नहीं हैं और हमसे कश्मीर की आईडी मांगते हैं. यानी, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के नेटवर्क को कम किया जा सकता है. यह कैसे करना है, यह मुश्किल है. नियंत्रण रेखा पर सेना हो तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि तब सेना दो देशों के बीच होगी न कि कश्मीर के भीतर. सशस्त्र बलों और वर्दीधारी लोगों की संख्या को कम किया जाना चाहिए. इसे हम धीरे-धीरे कम कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं और पाते हैं कि हिंसा नहीं हो रही है तो इसमें क्या समस्या है? कश्मीर में अभी कुल 178 आतंकवादी हैं. सरकार कहती है कि अगले छह महीनों में इस संख्या में वृद्धि हो सकती है. 178 बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि आतंकवादी, आतंकवादी होते हैं. वे किसी के घर में छुप सकते हैं और बाद में तबाही मचा सकते हैं. यह एक जटिल मुद्दा है. लेकिन यह जितना मनोवैज्ञानिक है उतना ही तार्किक भी.

जनमत संग्रह तब तक नहीं संभव है जब तक भारत और पाकिस्तान इस बात से सहमत न हों. इसलिए, इसे अलग ही रखें. लेकिन, दिल्ली या मुंबई या चेन्नई या किसी अन्य जगह के लोग जो सामान्य जीवन जीते हैं, वही सामान्य जीवन कश्मीर के लोगों को भी दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए. 1983-84 के बाद और 1989 के चुनाव जिसमें कश्मीरी लोग धांधली किए जाने की बात करते हैं. तब से तक़रीबन पिछले तीस वर्षों में नागरिक स्वतंत्रता या समानता की झलक नहीं देखने को मिल रही है. पुलिस सर्वोच्च है और सेना सर्वोच्च है. क्रोध अब और अधिक बढ़ गया है क्योंकि अब नया पैलेट गन आ गया है. छात्रों द्वारा पत्थर फेंके जाने पर उन पर पैलेट गन चलाया गया जिससे लोग अंधे हुए. इससे निश्चित रूप से भारत भर के लोगों के बीच एक अच्छा सन्देश नहीं गया. बेशक क़ानून और व्यवस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी समस्या के हल के लिए आप अनुचित तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते. आप यह बोल कर कि विमुद्रीकरण से समस्या खत्म हो गई क्योंकि अब उन्हें पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं, मज़ाक़ नहीं उड़ा सकते. ऐसा बोलना ही बचकाना है.

कश्मीर की सरकार कश्मीर के लिए कश्मीरियों द्वारा चुनी गई हो

वैसे अभी शांति का लाभ लेने का समय है. यह वक्त है जब सरकार को चाहिए कि लोगों को धीरे-धीरे सभा, राजनीतिक बैठकें आदि करने की इजाज़त देना शुरू करे. मैं मुंबई में राजनीतिक बैठक का आयोजन कर सकता हूं और कह सकता हूं कि महाराष्ट्र केवल महाराष्ट्रीयन के लिए हैं, अन्य को यहां से चले जाना चाहिए. यह एंटी नेशनल तो नहीं है. यह मेरा चरम विचार हो सकता है. आप इससे सहमत न हो. लेकिन यह बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में इसकी अनुमति नहीं है. कश्मीर हमेशा एक विशेष राज्य रहा है और आर्टिकल 370 उसकी रक्षा करता है. पाकिस्तान, कश्मीर पर अपने अधिकार का दावा कर रहा है. कश्मीर में थोड़ी-बहुत राजनीतिक गतिविधि की अनुमति देने में कोई बुराई नहीं है. जब तक एक ऐसा समय आता है जब आप पूरी तरह से एकीकृत हो जाएं, तब तक आर्टिकल 370 को मज़बूत बनाने की ज़रूरत है. जैसा कि भाजपा 370 को खत्म करने की धमकी देती है और जैसा कि मोदी के शपथ लेते (शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 44-45
02 जनवरी- 15 जनवरी 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378
पृष्ठ-20++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त क़ानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कश्मीर कश्मीरियों को सौंपना चाहिए

पृष्ठ 2 का शेष

ही उनके पीएमओ के मंत्री ने कहा था कि 370 को ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसा करने से हालत और बिगड़ेंगे. यह सबसे मूर्खतापूर्ण, अनुचित, ग़लत बयान था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे एक व्यक्ति की तरफ़ से आया था. बेशक उसके बाद ऐसा नहीं किया गया. कश्मीर में जब आप पीडीपी के साथ सरकार बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने आर्टिकल 370 को स्वीकार कर लिया है. इसी तरह काम होना चाहिए. सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन देश के संविधान में प्रतिस्थापित स्थिति को बदला नहीं जा सकता है. क्या आज एक सरकार आ कर यह कह सकती है कि कुछ समय के लिए भारत कश्मीर को भूल जाए? नहीं. ऐसा नहीं हो सकता. हरेक नागरिक को अनुच्छेद 14, 19 से अधिकार मिला हुआ है और अदालतों के पास उचित प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार है. राजद्रोह, अगर कोई भारत के ख़िलाफ़ टिप्पणी करता है, और वह टिप्पणी इतनी संवेदनशील है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है. क्यों? हां, अगर आपके भाषण से हिंसा भड़कती है, तो निश्चित तौर पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ़ भाषण देने भर से नहीं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी को वो बात भी कहने का अधिकार है, जो आपको पसंद नहीं है. अगर सभी लोग आपकी प्रशंसा में ही बोलें तो फिर इसका मतलब है कि अभिव्यक्ति की ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है. स्वतंत्रता वह है कि अगर कोई ऐसी बात करे जो आपको पसंद नहीं है. अगर कोई आपके ख़िलाफ़ ख़राब टिप्पणी भी कर सके और आप उसे ऐसा करने का अधिकार देते हैं, तभी सचमुच उसे अभिव्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है. पश्चिमी लोकतंत्र में हम इसे देखते हैं, क्या हम भारत में भी ऐसा देखते हैं?

संसद के भीतर सी अन्नादुरई, उस समय मद्रास राज्य से द्रमुक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने भारत से मद्रास राज्य को छूट दिए जाने के लिए एक भाषण दिया था. उन्होंने मद्रास राज्य के लिए अलग झंडा, अलग नाम, अलग संविधान आदि की मांग की थी. एक घंटे का उनका भाषण राज्यसभा में हुआ. किसी ने उनके भाषण को बाधित नहीं किया. उन दिनों में एक स्वस्थ बहस की परंपरा थी. उसके बाद 12 सदस्यों ने श्री अन्नादुरई के तर्क को ग़लत बताया, भ्रामक बताया. उन्हें समझाया कि कैसे उनकी ये मांग भारत के हितों के ख़िलाफ़ है और ख़ुद यह तमिलों के हितों के ख़िलाफ़ भी है. फिर क्या हुआ? चुनाव हुए, तमिल सत्ता में आए. 1967 में सत्ता में आए और तब से पिछले 50 साल से सत्ता में हैं. वे भारत के अभिन्न अंग बने हुए हैं. उन्होंने अलग होने की बात नहीं की. वास्तव में अगर आप सूचकांकों को देखें तो तमिलनाडु विकसित राज्यों में से एक है. आज यह औद्योगिक और अन्य रूप से विकसित है. ऐसा क्यों हुआ? तमिलनाडु के लोगों को लगता है कि राज्य में अब उनकी सरकार, उनके द्वारा चुने गए लोग राज्य चला रहे हैं. यह दिल्ली से गाइडेड नहीं होती. पहले जब कांग्रेस थी, तब दिल्ली से गाइडेड होती थी. लेकिन कश्मीर में यह भावना नहीं है. केवल एक बार, 1983 में जब फ़ारूक़ अब्दुल्ला चुनाव जीते, तब लोगों को लगा कि वे इंदिरा गांधी और कांग्रेस के अधीन नहीं हैं. उनकी अपनी चुनी हुई सरकार है. यह एक साल तक चली. जगमोहन राज्यपाल थे, आधी रात को साज़िश के तहत दलबदल हुई, कांग्रेस ने जीएम शाह को मुख्यमंत्री बना दिया. अब्दुल्ला की सरकार गिर गई. दुर्भाग्यवश पहली बार सांप्रदायिक दंगा तभी कश्मीर में हुआ. कश्मीर कभी सांप्रदायिक नहीं रहा है, एक मज़बूत हिंदू और एक मज़बूत मुस्लिम आबादी के बावजूद. क्योंकि वहां सूफ़ी इस्लाम है, वहाबी इस्लाम नहीं है. वास्तव में धर्म कश्मीर में मुद्दा है ही नहीं. इसके उलट कश्मीर को ले कर धार्मिक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं. बेशक वे मुसलमान हैं, जैसे अरब के लोग मुसलमान हैं, दुबई में मुसलमान हैं फिर भी वहां बिना किसी समस्या के हिन्दू काम करते हैं. धर्म जब तक निजी जीवन का विषय है, कोई समस्या नहीं है और कश्मीर में यह कोई मुद्दा नहीं है. ठीक है कि जम्मू में अधिक हिंदू हैं लेकिन जम्मू के कुछ जिलों में ठीक ठाक संख्या में मुसलमान भी हैं. कश्मीर एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है. वहां हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं. महाराजा रंजीत सिंह ने वहां शासन किया, हरि सिंह का वहां शासन था. दुर्भाग्य से भारत, कश्मीर को सेना, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस के ज़रिए नियंत्रित करना चाहता है.

अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों के या हुर्रियत के लोग समझते हैं कि आप हमेशा के लिए हड़ताल नहीं कर सकते. वे यह भी समझते हैं कि छह महीने का समय एक बड़ी अवधि है और वे ख़ुश हैं कि इस हड़ताल में एक गैप (अंतराल) आया है. लेकिन वे इस बात से भी आशंकित हैं और ये नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा क्योंकि मूल सवाल अभी भी अनुत्तरित ही है.

भारत के दूसरे राज्य की तरह ही वहां भी क़ानून और व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन ये प्रमुख निर्णायक नहीं हो सकते. दुर्भाग्य से कश्मीर में प्रबल धारणा यह है कि वर्तमान में दिल्ली सरकार केवल सुरक्षा कर्मियों की सलाह से ही चलती है और फ़ैसले लेती है. यह धारणा ख़त्म होनी चाहिए. इसे और अधिक राजनीतिक होना चाहिए. गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बार-बार श्रीनगर की यात्रा करनी चाहिए. वे एक राजनीतिक आदमी हैं, चुनाव लड़ते हैं, वह चीजों को समझते हैं. उन्हें कश्मीरी समाज से लगातार मिल कर बातचीत करते रहना चाहिए. जाहिर है, बिना किसी पूर्वाग्रह के वे एक बेहतर पोजीशन ले सकते हैं. भारत के गृह मंत्री को इस बात पर सहमत होने की ज़रूरत नहीं है कि कश्मीर एक खुला सवाल है. भारत के भीतर रहते हुए भी कश्मीर के लिए अपार संभावनाएं है. क्यों श्रीनगर के नागरिकों पर प्रतिबंध होने चाहिए. कश्मीरी लोगों को यह एहसास ज़रूर होना चाहिए कि वे उनके द्वारा शासित हो रहे हैं, जिसे उन्होंने चुना है. शासन करने वाले हमारे और हमारे जैसे ही लोग हैं. ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं, जो चाहते हैं कि छात्र पढ़ाई कर सकें, बीमार का इलाज़ हो सके, व्यापार ठीक से चले, पर्यटक आएं. ये सही है. लेकिन एक पर्यटक अख़बार में ख़ून-ख़राबे की खबर पढ़ कर क्यों कश्मीर जाएगा? कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगा. इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? हुर्रियत नेताओं को दोषी ठहराना एक बात है. वे अपना काम कर रहे हैं. लेकिन, श्रीनगर की सरकार आपकी है, भाजपा और पीडीपी की है. दिल्ली की सरकार आपके (भाजपा) पास है. आप देश चलाने की अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं. देश का हर कोना सुशासन, शालीनता, मानव जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ चले, ये आपकी ज़िम्मेवारी है.

मैं फ़ारूक़ अब्दुल्ला, कांग्रेस के सैफ़ुद्दीन सोज, सीपीएम के तारिगामी और कांग्रेस अध्यक्ष जीएम मीर से भी मिला. राजनीतिक दल राजनीतिक दल होते हैं और इनमें से किसी का भी कठोर विचार नहीं है. कोई भी जनमत संग्रह की बात नहीं करता, क्योंकि उनका कामकाज भारतीय चुनावी क़ानूनों से चलता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से सभी चाहते थे कि प्रयासों को जारी रखना चाहिए. हर कोई चाहता है कि आग ठंडी हो, लेकिन किसने आग लगाई, नहीं मालूम. वे यह भी नहीं जानते हैं कि कौन इस आग को ठंडा कर सकता है. लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि लोगों के बीच संपर्क बढ़े. यह कुछ हद तक सही भी है कि सूचना का अभाव है. इसलिए वे चाहते हैं कि भारत से ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएं. लेकिन मेरे हिसाब से कश्मीर की चाबी केंद्र सरकार के पास है. जब तक सरकार सुरक्षा उपायों में ढील नहीं देती, सामान्य जनजीवन बहाल नहीं करती, चीज़ें नहीं सुधरेंगी.

शब्बीर शाह एक पुलिस स्टेशन में हैं, जिसे एक उप जेल ही बना दिया गया है. हमें वहां जा कर उनसे मिलने का मौका मिला. एसएचओ पहले तो अनिच्छुक था और हमें अनुमति नहीं दी गई, लेकिन बाद में संतोष भारतीय ने कुछ फोन कॉल किए और फिर हमें उनसे मिलने की अनुमति प्रदान की गई. बेशक, एक बार अनुमति मिलने के बाद एसएचओ ने हमारे लिए चाय भी भिजवाई. हमने शाह के साथ एक घंटे बात की. एक अच्छी बैठक हुई. इस मुलाक़ात का अहम हिस्सा ये रहा कि शब्बीर शाह ने गुस्सा नहीं दिखाया. शाह ख़ुद इस बात से अचंभित हैं कि सरकार को उन्हें 29 साल से बार-बार और पिछले 40 महीनों से लगातार कैद में रख कर क्या मिल रहा है? वह हुर्रियत का हिस्सा हैं और पूर्व में प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर के समय किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं. चन्द्रशेखर सरकार ने लोगों के साथ संपर्क किए थे, बैक चैनल डिस्कशन हुआ था.

कश्मीर समस्या की चाबी केंद्र के पास है

अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों के या हुर्रियत के लोग समझते हैं कि आप हमेशा के लिए हड़ताल नहीं रख सकते. वे यह भी समझते हैं कि छह महीने का समय एक बड़ी अवधि है और वे ख़ुश हैं कि इस हड़ताल में एक गैप (अंतराल) आया है. लेकिन वे इस बात से भी आशंकित हैं और ये नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि मूल सवाल अभी भी अनुत्तरित ही है. ऐसे में लोगों का गुस्सा फिर सतह पर आ सकता है. बेशक पाकिस्तान की भूमिका है, लेकिन हम अपने देश में घटने वाली घटना के लिए सिर्फ़ पाकिस्तान को ही दोष नहीं दे सकते हैं. क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने ही लोगों के दिलों को जीत नहीं सकते हैं. मैं नहीं समझता कि यह भारत जैसे एक बड़े देश के लिए स्वीकार्य चीज़ है. आज ज़रूरत इस बात की है कि कश्मीर को और अधिक अधिकार दिए जाएं, 370 को और मज़बूत बनाएं. तब पाकिस्तान क्या कहेगा? और जो लोग आज जनमत संग्रह की बात करते हैं, उसमें धर्म एक कारक है. जनमत संग्रह धर्म के बिना किए जाने की बात थी, लेकिन अब यह मुश्किल है. आज के इतने अधिक सांप्रदायिकीकरण की हालत में जनमत संग्रह एक विकल्प नहीं है. पाकिस्तान भी समझता है कि वहां जनमत संग्रह नहीं होगा. नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह हो जाएगी. प्रस्ताव यह था कि उसे एक सॉफ्ट बॉर्डर बना दिया जाए, लेकिन लोगों को यह सब समझ नहीं आता. वे इसे ले कर भी संदेह करते हैं.

अब, जो भी कहना और करना है, भारत सरकार को करना है. भारत एक बड़ा देश है. कश्मीर देश का एक बहुत छोटा हिस्सा है. कश्मीर की आबादी भारत के बाक़ी हिस्सों की तुलना में क्या है? यदि हम इतनी कम जनसंख्या के मन में विश्वास नहीं जगा सकते अपने शासन के बारे में, अपने संविधान के बारे में, तो फिर मैं समझता हूं कि इसका बहुत बुरा असर होगा. आप कह सकते हैं कि कुछ शरारती तत्व ये सब कर रहे हैं. वे हर जगह हैं. मुंबई में और दिल्ली में भी आपराधिक कृत्य होते हैं. लेकिन इससे पूरा का पूरा राज्य प्रभावित नहीं होता. जाहिर है, कश्मीर में मतदाताओं के मन पर अधिक प्रभाव है. इस बात का कोई जवाब नहीं है कि सरकार की प्रतिक्रिया इतनी ख़राब क्यों है? शायद इसकी वजह अर्धसैनिक बलों द्वारा ताक़त का इस्तेमाल भी है, जो अक्सर होता रहता है. इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं.

ऐसे मामले आज ही नहीं, अकबर के समय में भी थे. यह सेनाओं का सामान्य व्यवहार है. लेकिन सभ्य राज्य में हमें इसे ना कहना चाहिए. एक और शिकायत है कि सेना के ख़िलाफ़ पुलिस आमतौर पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है. अब, ऐसे में लोग क्या महसूस करेंगे? जंगलराज और क़ानून के शासन के बीच फिर क्या अंतर रहेगा? प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, जांच कराई जानी चाहिए. दस में से दो दोषी पाए जाएंगे. इससे एक औसत आदमी के मन में विश्वास पैदा होगा. मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या कहूं? या तो सरकार को चाहिए कि वो कश्मीर मामलों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाए, जैसा कि एक बार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था, और जॉर्ज फर्नांडीज़ इसके प्रभारी थे, स्वयं गृह मंत्री इस मामले को देखें लेकिन किरण रिजीजू तो बिल्कुल इसके लिए फिट नहीं हैं. इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो चीजों को समझे, जो उदारवादी मानसिकता का हो. आप झंडेवालान (दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय) में जो अनुशासन लागू करते हैं, वही अनुशासन कश्मीर में लागू नहीं कर सकते हैं. कश्मीर एक समग्र राज्य है. वास्तव में यह भारत का गौरव है. यह दुनिया को दिखाने लायक एक जगह है कि देखिए हम कैसे सद्भावना के साथ रहते हैं. हालांकि, हमने इस सद्भावना को खत्म करने की कोशिश की है. बेशक कश्मीरी पंडितों का वहां से निकलना एक बदनुमा दाग है, कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी. उनकी वापसी की बात होती है, लेकिन वे वापस जाने का जोखिम क्यों लें. मुझे आशा है कि एक दिन आएगा और धीरे-धीरे वे अपने घरों को वापस जाएंगे और समग्र कश्मीर की तस्वीर हमारे सामने होगी. आज़ादी के बाद, 1980 तक, यानी 35 साल तक ऐसी कोई समस्या नहीं थी. जनमत संग्रह का भी मुद्दा था, पाकिस्तान भी मुद्दा था, लेकिन कश्मीर के लोगों के बीच सद्भावना बनी रही. हमें उसी स्थिति को पाने की कोशिश करनी चाहिए. देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है? ■

feedback@chauthiduniya.com

इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के नारे खोखले हैं

सैयद अली शाह गिलानी

हम बेरहम शिकंजे में कसे जा चुके हैं. सिविल सोसाइटी को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है. जम्मू और कश्मीर में जो घटनाएं घट रही हैं, उसकी सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही है. यह बहुत बड़ी त्रासदी है. हमने हड़ताल में पांच दिन की छूट का ऐलान किया, लोगों ने उसमें साथ दिया. इसके पीछे यही मंशा थी कि हड़ताल शुरू हुए अब छह महीने होने वाले हैं, अब लोगों को राहत मिल जानी चाहिए. जहां तक हमारे बुनियादी मसले के संबंध हैं, भारत के फ़ौजी शिकंजे से आज़ादी हासिल करने का, वो जारी रहेगा. उसकी सूरतें और शक्लें बदलती रहेंगी. हमारी क़ौम ने जो महान क़ुर्बानियां दी हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है. चाहे भारत यहां कितना भी सरमाया ख़र्च करे, ताक़त ख़र्च करे, लेकिन हम अपने स्टैंड पर डटे रहेंगे. हम अपने क़ौम से कहते हैं कि हमें ईमानदार बनना चाहिए, हमें इंसान का दोस्त बनना चाहिए. इसलिए आप देख रहे हैं यहां जम्मू कश्मीर में किसी हिन्दू भाई को कोई नुक़सान नहीं पहुंच रहा है. हम ख़ुदा परस्त हैं इसलिए हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा. भारत बहुत बड़ा मुल्क है उसके पास पैसा है, बड़ी फ़ौज है और यहां कई ऐसे लोग हैं जो उसके जबरी क़ब्ज़े का समर्थन भी करते हैं. उनके दिलों में भी कोई कसक नहीं है जो इंसान का दुख देख कर उसमें कोई तब्दीली आ जाए. इसके बावजूद ऐसा होता है. ये चीज़ें होती रहती हैं, हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है.

कश्मीर एक विवादास्पद टेरीटरी है

हम 47 से लेकर मुसलसल देखते आए हैं. उससे पहले भी हम सौ साल तक डोगरा शाही के शिकंजे में रहे हैं. उस दौर में भी हमने मज़ारें देखी हैं, सख्तियां देखी हैं. हिन्दुस्तान जो जम्हूरियत के दावे कर रहा है, वो खोखली है. उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए थे, उससे बिल्कुल मुकर गए. हमारा जो बुनियादी और पैदाइशी हक़ है, राइट टू सेल्फ-डिटरमिनेशन, उसका उन्होंने वादा किया है. 18 क़रारदादों को पास किए हैं. उन पर दस्तख़त किए हैं. उनको तसलीम किया है, पाकिस्तान ने भी और आलमी बिरादरी इसकी गवाह है, लेकिन उस पर वो अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं. सिर्फ ताकत का नशा है. मसले को आसान करने का यही रास्ता है कि हिन्दुस्तान रियलिटी को समझे. वह समझे कि जम्मू और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है. जम्मू और कश्मीर के लोगों को ये हक़ मिलना चाहिए कि वे अपने भविष्य का फ़ैसला कर सकें कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या कोई और ऑप्शन चुनते हैं. भारत यहां नरमी का रवैया अख्तियार करे. यहां की वास्तविक मांग को स्वीकार करे. सब कुछ हिन्दुस्तान के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है. हमने बार-बार कहा है कि जम्मू-कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, मुसलमान हैं, चाहे हिन्दू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे ईसाई हैं, उनको हक़ दिया जाए कि वे अपने भाग्य का फ़ैसला करें. अगर मेजॉरिटी का फैसला यही हो कि हम हिन्दुस्तान के साथ रहेंगे, तो हम तसलीम करेंगे. हम लोगों का फ़ैसला तसलीम करेंगे. यही हल है और कोई हल नहीं है.

इन्हें कुर्सी से मतलब है, कश्मीर से नहीं

जो ये हिंदनवाज़ पार्टियां हैं, इनके रंग और इनके बयानात बदलते रहते हैं. इनका असल मक़सद कुर्सी है. फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है, उसमें भी यही मक़सद है कि हमें किसी न किसी तरह कुर्सी मिल जाए. अगर वो सिंसियर हैं, तो उनको चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लेना चाहिए. वो कहते हैं कि हम हुर्रियत के साथ हैं. हुर्रियत आगे बढ़े, हम उनके पीछे-पीछे चलेंगे. अगर वो इसमें सिंसियर हैं, तो उन्हें किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ. 1996 में जब यहां मुकम्मल बायकॉट था, तो इसी शख़्स ने कहा कि अगर सिर्फ दो फीसद वोट पड़ेंगे, हम चुनाव में हिस्सा लेंगे. इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर वज़ीर-ए-आला बने. इनको सिर्फ़ इक्तेदार के साथ दिलचस्पी है. अवाम के साथ कोई इनकी हमदर्दी नहीं है. क़ुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं. इस बार सौ जवान शहीद किए गए. मैं अक्सर जवानों की बात करता हूं. ऐसे दर्दनाक वाक़यात जो हैं, वो तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं. अब इन पार्टियों को मौक़ा देने का सवाल नहीं पैदा होता है. अगर हमारे कॉज़ के लिए उनके मन में सिंसियरिटी है तो वे आगे आ कर किसी भी चुनाव में हिस्सा न लें. ये सारा सूरतेहाल जो है, वो ऐसे ही लोगों की लाई हुई है. 1947 में जम्मू में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी. 81 फ़ीसदी. ऐलान किया गया कि सारे जम्मू शहर में जमा हो जाओ. पाकिस्तान बना है, हम तुमको गाड़ियों में भरकर पाकिस्तान भेज देंगे. उनके साथ फरेब किया गया और जब जम्मू आ गए तो वहां उनका कत्लेआम किया गया. शेख़ अब्दुल्ला अपनी आंखों से पांच लाख मुसलमानों का ख़ून बहते देखते रहे. इस्तीफ़ा नहीं दिया. एक आंसू भी नहीं बहाया. उसी अब्दुल्ला की ये तारीफ़ कर रहे हैं. आगामी चुनाव के बायकॉट का हमने फ़ैसला किया है. अभी जो हमारा इंजीनियर शहीद हुआ, उसके जनाज़े में मैंने तक़रीर की फोन पर. मैंने एलान किया कि आने वाले इलेक्शन, चाहे पंचायत का हो या श्रीनगर का हो या अनंतनाग का हो, उसका बायकॉट किया जाए. कुछ लोगों का कहना है कि हम इलेक्शन में हिस्सा लें. मैं 15 साल तक इलेक्शन में रहा. असेंबली में रहा 15 साल. तीन बार मुझे सोपोर कॉन्स्टीट्यूएंसी से वोट मिला. मैंने असेंबली में काम किया. हमने इसका भी तजुर्बा किया है. मैंने तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अपने 15 साल असेंबली में काम किया.

> मेरा मानना है कि हालात तो वैसे ही हैं. पहले भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता था. अभी भी कहीं धरना देते हैं तो वहां पुलिस आती है, फ़ौज आती है, लाठीचार्ज किया जाता है, सड़कों पर बैठने नहीं दिया जाता है. सूरते हाल ज्यों की त्यों है. अगर सिविल सोसाइटी कुछ कर सकती है तो उन्हें चाहिए कि वो पहले हिंदुस्तान के लोगों में जागरूकता पैदा करे कि कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है. इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के जो नारे दे रहा है, वे खोखले नारे हैं.

8 जुलाई के बाद तो लोग ही आए न सड़कों पर. वो कोई जंग नहीं थी. किसी के हाथ में डंडा नहीं था, किसी के हाथ में कोई पैलेट गन नहीं था. किसी के हाथ में कोई ग्रेनेड नहीं था. उनका कत्ल किया गया. उन पर गोलियां चलाई गईं. उन पर पैलेट गन चलाए गए. देखना तो यही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? अगर पहले से ही बुरहान की

शहादत पर वहां दो लाख लोग जमा हो चुके थे. 40 बार उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी गई और फिर यहां से और लाखों की तादाद में वहां पहुंचते तो क्या फ़र्क़ पड़ता. लेकिन लोगों को नहीं आने देते हैं सड़कों पर. जहां तक जलसे, जुलूस व विरोध प्रदर्शन का सवाल है वो तो दूर की बात है. यहां तो मज़हबी कार्यक्रम करने की भी इजाज़त नहीं है. 12 दिसम्बर को ईद मिलादुन-नबी थी. हमने अपने यहां कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें यासीन मालिक, मीरवाइज़ और दूसरे बोलने वालों के साथ तक़रीबन 200 लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन उस कार्यक्रम को करने की इजाज़त नहीं दी गई. यानी एक बंद कमरे में एक धार्मिक कार्यक्रम करने पर बताया गया कि कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी. दरअसल, यह लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की फ़ौज, यहां की पुलिस और भारत की सरकार कितना ज़ुल्म कर रही है. यहां भारत का लोकतंत्र कहां है?

क़सूर उनका है जो ख़ामोश रहते हैं

वाजपेयी साहब का नाम अक्सर लिया जाता है कि कश्मीर पर उन्होंने बड़ा एहसान किया. क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया. उन्होंने अपनी एक तक़रीर में कहा था कश्मीरियत और इंसानियत वगैरह. लेकिन क्या उन्होंने इंसानियत का एहतराम किया? हम भी तो इंसान हैं और फिर मुसलमान हैं. हमें मुसलमान होने पर फ़ख़्र है. वाजपेयी जी ने अगर कहा कि हम इंसानियत के दायरे में कश्मीर का फ़ैसला करेंगे, तो हम भी इंसान हैं न. तो वाजपेयी के दौर में हमें हमारा हक़ मिलना चाहिए था. दरअसल ये कहने की बातें हैं इस पर अमल नहीं हो रहा है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ उसी दौर में कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए भारत आये थे, चार सूत्री फॉर्मूला लेकर. मैंने उस फॉर्मूले का विरोध किया था. यहां हमारे कुछ नेताओं ने उसका समर्थन किया था. दरअसल वो फॉर्मूला हमारे बुनियादी स्टैंड से बिल्कुल अलग था, जिसमें हम आत्मनिर्णय (सेल्फ डिटरमिनेशन) की मांग कर रहे हैं. भारत को इस मसले को हल करने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है. भारत के प्रधानमंत्री ने, यहां क़त्ल हुए लोगों या पेलेट गनों से ज़ख्मी लोगों के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है. कोई अफ़सोस नहीं जताया. एक विचारक था. उसे पूछा गया कि समाज में जो फ़सादात हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है. उसका जवाब था कि ये जो फ़साद करने वाले हैं, उनका क़सूर नहीं है. ये उन लोगों का कसूर है जो ख़ामोश रहते हैं. भारत में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो मानवता प्रेमी हैं, लेकिन सामने नहीं आते. जब तक आप लोगों को रोकेंगे नहीं, उनपर डंडे नहीं बरसाएंगे, उनपर गोलियां नहीं चलाएंगे तब तक वे पत्थर नहीं फेंकेंगे. अब पत्थर फेंकने वालों को ही मुजरिम बनाया जा रहा है. उन्हें ही जेलों में भेजा जा रहा है. जो क़ातिल हैं, जिन्होंने पेलेट गन से हमारे लोगों की आंखें ख़राब कीं, उनको कोई कुछ नहीं कहता. ज़ख्मियों को कोई नहीं पूछता. इससे बढ़ कर और ज़ुल्म क्या हो सकता है. अब यह सवाल है कि हम भारत के ख़िलाफ़, जिस तरह गांधी जी ने सिविल नाफ़रमानी को हथियार बनाया था, क्या हम वैसा कर सकते हैं. इसका जवाब है कि अगर अंग्रेज़ हाकिम होते तो हम ये कर सकते थे, लेकिन यह भारत का राज है, जहां चारदीवारी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, सड़कों पर निकलने की इजाज़त कहां से मिलेगी?

सिविल सोसाइटी हमारी बात हिन्दुस्तान के लोगों तक पहुंचाए

कश्मीर में पिछले पांच महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा था. ये सवाल किया जाता है कि पांच महीने के पहले के जो हालात थे, क्या वहां तक वापस जाया जा सकता है? मेरा मानना है कि हालात तो वैसे ही हैं. पहले भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता था. अभी भी कहीं धरना देते हैं तो वहां पुलिस आती है, फ़ौज आती है, लाठी चार्ज किया जाता है, सड़कों पर बैठने नहीं दिया जाता है. सूरते हाल ज्यों की त्यों है. अगर सिविल सोसाइटी कुछ कर सकती है तो उन्हें चाहिए कि वो पहले हिंदुस्तान के लोगों में जागरूकता पैदा करे कि कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है. इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के जो नारे दे रहा है, ये खोखले नारे हैं. ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. सिविल सोसाइटी हम पर एहसान करे कि वे भारत में जागरूकता पैदा करे. लोगों को बताए कि भारत ने हमसे एक वादा किया था. कश्मीर के लोग उस वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं. पी चिदम्बरम ने 2010 में यह माना कि कश्मीर प्रॉब्लम इज़ अ ब्रोकन प्रॉमिसेज़. यानी हमने कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किये थे, हमने तोड़ दिए. ये बातें अगर हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाई जाएं, सिविल सोसाइटी के ज़रिए तो उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा. बुरहान के बड़े भाई का क़त्ल हुआ था. अब पुलिस ने यह मान लिया है कि वह कोई मिलिटेंट नहीं था या हिज़बुल मुजाहिदीन का कोई कमांडर नहीं था. उन्होंने आदेश दिया कि इसका हर्जाना दिया जाना चाहिए. जम्मू में इस आदेश के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुआ. हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं. उन लोगों तक, जिनके सीनों में दिल है, उन तक अगर हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी पहुंचने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान के लोगों में ये नरमी आ जाएगी और वे हक़ीक़त को समझने का मौक़ा पाएंगे.

हमारी तंज़ीम का संविधान तय करेगा विरासत

अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी विरासत कौन संभालेगा. इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि हमारी तंज़ीम का एक संविधान बना हुआ है. संविधान के मुताबिक़ कोई उसका मेम्बर बनता है और काम करता है तो वह किसी भी पद पर जा सकता है. मेरे दो बेटे हैं. उनमें से कोई भी हमारी पार्टी का मेम्बर नहीं बना है. इसलिए इसका कोई अंदेशा नहीं रखना चाहिए कि वे ही मेरी विरासत संभालेंगे. अगर वे मेम्बर बन जाते हैं और उनमें सलाहियत है और सारे मेम्बर्स चाहेंगे तो उनको अपना नेता चुन सकते हैं, अपने वोट के जरिए. लेकिन, सबसे पहली ज़रूरत यह है कि वे तहरीक के मेम्बर बनें. नसीम तो सरकारी नौकरी में हैं. वे मेम्बर नहीं बन सकते. लेकिन, नईम बन सकते हैं. यदि वे पार्टी के संविधान की शर्तों को पूरा करते हुए मेम्बर बनते हैं तो ठीक है. मेरे दोनों बेटे मेरी दो आंखों की तरह हैं. एक का मिजाज़ नर्म है और एक का गर्म है. एक का मानना है कि हमारी तहरीक में सब्र किया जाए लेकिन दूसरे का कहना है कि हमें अपने स्टैंड पर क़ायम रहना चाहिए. ■

-लेखक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (जी) के चेयरमैन हैं.

feedback@chauthiduniya.com

हम नहीं चाहते बच्चे बंदूक़ उठाएं

हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कश्मीर मसले पर गवर्नमेंट क्या कहती है? एक मसला हमारे लिए ये भी है कि हिन्दुस्तान की अवाम तक अपनी बात रखने का कोई ज़रिया नहीं है. हो सकता है इसमें हमारी भी थोड़ी कोताही हो, लेकिन वहां तक सही बात पहुंचनी ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा माहौल बन गया है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उन्हें ये लगता है कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है, स्पॉन्सर्ड है या पैसे के बल पर हो रहा है.

मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़

कश्मीर महज़ सड़क, बिजली, पानी और कुर्सी का मसला नहीं है. कश्मीर के लोग यहां पर जॉब्स और इंसेंटिव्स मांग रहे हैं, लेकिन बार-बार डायरेक्शन दिया जा रहा है कि यहां का यूथ बेरोज़गार है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है. सबसे दुखद स्थिति ये है कि इतना सब होने के बाद भी समस्या को कोई समझने वाला नहीं है. फिलहाल, केंद्र में जो सरकार है, वह समस्या को सुलझाने में ज्यादा रुचि नहीं रखती है. अब दूसरा डिस्कोर्स इन्होंने शुरू कर दिया है. हर चीज को ये नेशनिलज्म के दायरे में ले आते हैं. ये ठीक नहीं है.

सरकार की ज़िम्मेवारी क्या है

हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कश्मीर मसले पर गवर्नमेंट क्या कहती है? एक मसला हमारे लिए ये भी है कि हिन्दुस्तान की अवाम तक अपनी बात रखने का कोई ज़रिया नहीं है. हो सकता है इसमें हमारी भी थोड़ी कोताही हो, लेकिन वहां तक सही बात पहुंचनी ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा माहौल बन गया है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उन्हें ये लगता है कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है, स्पॉन्सर्ड है या पैसे के बल पर हो रहा है. इंडियन पब्लिक ऑपिनियन हर मामले में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, चाहे सिविल सोसाइटीज हों, कॉरपोरेट या फिर वॉलीवुड को ही देख लें. हर एक मसले पर वे अपनी राय रखते हैं और इसके लिए वो गवर्नमेंट को भी फेस वैल्यू पर नहीं लेते. लेकिन कश्मीर की बात आती है, तो पता नहीं क्या हो जाता है? जब बार-बार आप ये कहते हैं कि यह सब स्पॉन्सर्ड है तो इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है, कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर भी वे हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, फिर चाहे वो सुरक्षा बलों का इस्तेमाल हो, पैलेट्स हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो या फिर यहां के यूथ को गिरफ्तार किया जाना हो. ऐसा नहीं है कि कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए हमने सलाह नहीं दी है. 2006 में, 2007 में कई बार सलाह दी और लिखित में भी दी है. हुर्रियत की बातचीत भी हुई. वाजपेयी जी की हुकूमत थी. उसके बाद मनमोहन सिंह साहब आए. हम एक-दो बार उनसे भी मिले. कुछ विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वे यहां फायर फाइटिंग करने तब आते हैं, जब यहां पर आग लगी होती है. जब यहां पर हालात बेहतर होते हैं और एक बेहतर माहौल बन सकता है, तब वे कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं. बदक़िस्मती से कह सकते हैं कि यहां जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें युवा पीढ़ी को युद्ध की स्थिति की ओर धकेला जा रहा है. एक बार फिर वे हिंसा की तरफ़ बढ़ते दिख रहे हैं. वे बंदूक़ उठा रहे हैं. पिछले चार-पांच महीनों में, यहां जो भी एनकाउंटर्स हुए हैं, उनमें अधिकतर में कश्मीरी लड़के मरे हैं. इनमें अधिकतर पढ़े-लिखे हैं. कोई बीटेक छोड़ कर, कोई ग्रेजुएशन छोड़कर आ गया. इस स्थिति को जब तक समझा नहीं जाएगा और जब तक एक संदर्भ में इसके हल निकालने की कोशिश नहीं की जाएगी, हालात में सुधार मुश्किल है. अभी हालात ये हैं कि यहां पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आता है, होम मिनिस्टर आते हैं, वे सब तो सीधे-सीधे हुर्रियत का नाम भी नहीं लेते, स्टेक होल्डर्स कहते हैं.

स्ट्रेटजी वास्तविकता पर आधारित हो

अगर आप चाहते हैं कि यहां स्कूल कॉलेज और इकोनॉमी भी चले, तो आपको जो रीयल पॉलिटिकल इश्यू है, उसको भी आगे लाना होगा, लेकिन वे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं. इस माइंडसेड को बदलने की ज़रूरत है. आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी जो वास्तविकता पर आधारित हो. जब मोदी की सरकार आई, तब हमें उम्मीद थी कि वे वाजपेयी की नीति को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, हमारी एक पोजिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पोजिशन है. पाकिस्तान भी एक पार्टी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि अचानक कोई ब्रेक-थ्रू नहीं हो सकता. हम एक प्रोसेस की बात करते हैं कि यह कैसा होना चाहिए, फिलहाल सॉल्युशन की बात न करें. उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि त्रिपक्षीय बातचीत हो, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर भी एक पक्ष हों. ठीक है, हम एक टेबुल पर नहीं बैठ सकते, लेकिन त्रिपक्षीय बातचीत तो शुरू कर सकते हैं. इंडिया-पाकिस्तान भी बात करें, इंडिया-कश्मीर भी बात करें, साथ ही कश्मीरियों को आप पाकिस्तान भी जाने दें. वो एक सिलसिला चला था. हम मुज़फ्फराबाद जाकर मुशर्रफ़ से मिले, वहां से वापस आए फिर वाजपेयी जी से बात हुई. लेकिन फिर 2007 के बाद, कांग्रेस के आठ-दस साल के दौरान तो कुछ हुआ ही नहीं. चिदंबरम साहब भी बड़े-बड़े आर्टिकल लिखते हैं आजकल, लेकिन जब वे खुद सरकार में थे, तब कुछ नहीं किया. हमारी बदक़िस्मती है कि हमारे यहां जो पार्टियां हैं, वे भी कोई स्टैंड नहीं लेती हैं. अगर इन्होंने कोई स्टैंड लिया होता, तो आज हालात कुछ और होते. बहुत सारी चीजों को सेफगार्ड किया जा सकता था. हमने भी कोशिश की, जाएं पहले बात करें. लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं चंडीगढ़ गया, चेन्नई गया, कोलकाता गया, जहां-जहां गया तो वहां पर हल्ला-गुल्ला कर दिया भाजपा वालों ने. बात ही नहीं हो सकी. यह महत्वपूर्ण है कि कम से कम बातचीत तो हो. अराउंड द टेबुल बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हमारा भी एक प्वाइंट ऑफ व्यू सुना जाए, कोई अपनी भी बात कहे, शायद उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन ये है कि अब वो स्पेस भी नहीं लग रहा है. कम से कम डिस्कशन, डिस्कोर्स तो हो, जिसमें कि बात हो. हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी और रीजनल मीडिया को इस बारे में बात करनी होगी और सही बात.

अभी तो पैलेट को भी बैन करने के लिए तैयार नहीं हैं. इस माहौल में क्या गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव हो सकता है, जिसका यहां के लोग वेलकम करें? दोनों ट्रैक्स पर हमें कोशिश करनी होगी. एक तो ये भी है कि अगर हम पीपुल टू पीपुल इनिशिएटिव करें, वो भी चलता रहे. दूसरा ये है कि हमारे पास एक मैकेनिज्म था. इंडिया-पाकिस्तान के बीच क्रॉस एलओसी ट्रेड भी हो रहा है, डिवाइडेड फैमिलीज़ मिल रही हैं. उनको भी अगर मज़बूत किया जाए, तो उसमें हम भी अपना रोल अदा कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं समझती कि पाकिस्तान एक रिएलिटी है. आप उसको नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. कश्मीर के प्रॉब्लम में पाकिस्तान एक पार्टी है और उसे हमने नहीं बनाया. आपने खुद बनाया है. शिमला और बाकी एग्रीमेंट्स के द्वारा. पाकिस्तान में भी बहुत लोग कहते हैं कि बीच का रास्ता अख्तियार किया जाए. हम दो-चार बार पाकिस्तान गए इन दस-पंद्रह सालों में. वहां का एक मेजोरिटी तबका जिनसे हम मिले, चाहे वो बेनजीर की पार्टी हो, इमरान खान की पार्टी हो, नवाज़ शरीफ की पार्टी हो, हर कोई ये कहता है कि इसका आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकाला जाए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा. कुछ बेसिक चीज़ें जैसे ह्यूमन राइट्स, अफस्पा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट आदि को आहिस्ता-आहिस्ता फेरबदल करना पड़ेगा. कोई न कोई ऐसा मैसेज तो जाना चाहिए ग्राउंड पर. लेकिन अभी तो ये है कि कोई सिलसिला ही नहीं है. ऐसे होस्टाइल बयान आते हैं, चाहे उनके होम मिनिस्टर साहब हों या परिकर साहब हों.

अगर आप चाहते हैं कि यहां स्कूल-कॉलेज और इकोनॉमी भी चले, तो आपको जो रीयल पॉलिटिकल इश्यू है, उसको भी आगे लाना होगा, लेकिन वे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं. इस माइंडसेड को बदलने की ज़रूरत है. आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी जो वास्तविकता पर आधारित हो. जब मोदी की सरकार आई, तब हमें उम्मीद थी कि वे वाजपेयी की नीति को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

हल के लिए बातचीत होनी चाहिए

आहिस्ता-आहिस्ता हालात भी पटरी पर आएंगे. हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हड़तालों का सिलसिला थमे. कोई नहीं चाहता कि ये छोटे-बड़े बच्चे बंदूक़ की तरफ़ जाएं या बंदूक़ उठाएं. यहां का कश्मीरी कितना भी बंदूक़ उठाए, बंदूक़ से कुछ होने वाला नहीं है. लेकिन ये है कि इतना गुस्सा है यहां पर ग्राउंड में कि हमसब के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है. इसके हल के लिए यहां पर बातचीत होनी चाहिए. हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे कॉलेजेज़ हैं, वहां डिबेट हों, डिस्कशन्स हों. लेकिन अभी यहां पर आपने बैन लगा दिया है. जब तक आप यहां के बच्चों को स्पेस नहीं देंगे, यहां के पढ़े-लिखे लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक हल नहीं निकलेगा. हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलें, आपस में बात करें, लेकिन मिलने ही नहीं दे रहे हैं. गिलानी साहब को बंद कर दिया. अब जाते हैं तो दरवाज़ों से बाहर निकलने नहीं देते. ये एक अजीब सिचुएशन है. अगर आप चाहते हैं कि हालात बेहतर हों तो हमें बात तो करने दें, मिलने दें वहां पर. ये सिलसिला अजीबोगरीब है. यासीन साहब को भी इन्होंने कन्फाइंड कर दिया. ज्यादा ही ज्यादती वगैरह की. 6 महीनों में वे बीमार भी हो गए. हाथ में इंफेक्शन हो गया, हाथ भी कटने वाला था. ट्रीटमेंट में भी डिले कर दिया गया.

हुर्रियत ने कैलेंडर के हवाले से जो भी स्टैंड लिए चाहे वो रिलैक्शेसन हो या कुछ और उसे सबने फॉलो किया. उन्होंने भी जिन्हें मिलिटेंसी कहा जाता है. ये ठीक है कि वो अपना चलाते रहे वहां से, लेकिन पब्लिक डोमेन में वे न तो कोई ऐसा बयान देते हैं ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं कि हम लीडरशिप को ओवरटेक करना चाहते हैं या कोई नैरेशन देना चाहते हैं. उन्होंने फॉलो ही किया है इस ज्वाइंट लीडरशिप के प्रोग्राम को. अलबत्ता ये ज़रूर है कि साउथ कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, उसका ग्राफ थोड़ा सा बढ़ गया है. उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह तो हो गई है. लेकिन ये जो छोटे-छोटे लड़के जा रहे हैं, वो उस लिहाज से उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हैं, क्योंकि न तो बेचारे ट्रेंड हैं और न ही उनके पास कोई ऐसा अनुभव है. लेकिन यह एक इमोशनल आउटबर्स्ट है कि बंदूक़ उठा के आज़ादी ली जा सकती है. ऐसा भी नहीं है कि वो पाकिस्तान गए और ट्रेनिंग करके आ गए. यह एक डिफरेंट मिलिटेंसी है. मेरा मानना है कि यहां पर ऐसा कोई मिलिटेंट डिस्कोर्स डोमिनेट नहीं करेगा. ये तो चलता रहेगा छिटपुट वगैरह होते रहेंगे. कल यहां इंसिडेंट हुआ, कल वहां, परसों वहां ये तो चलेगा. लेकिन मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान के लेवल पर भी ये भी देखना है कि वहां पर चेंजेज़ हुए हैं. नए जनरल वगैरह आए हैं. आईएसआई के भी. उनका क्या रुख रहता है, यह देखना पड़ेगा. मैं डॉन में पढ़ रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से डायलॉग के ट्रैक को रिवाइव किया जाए. लेकिन देखना पड़ेगा कि इंडिया-पाकिस्तान कैसे क़दम बढ़ाते हैं? उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा. यह भी देखना पड़ेगा कि मिलिटेंसी के हवाले से क्या पॉलिसी रहती है.

जहां तक महबूबा जी की बात है तो उन्हें ग्राउंड लेवल पर अपनी पोजिशन री-स्टैबलिश करनी पड़ेगी. उनका अपना तो कोई एजेंडा नज़र ही नहीं आ रहा है अब. एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था उन्होंने, पर उस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है. यहां की सरकार बीजेपी के हवाले से ही चल रही है. लेकिन उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा. हमें पता नहीं कि मोदी मानेंगे या नहीं. वैसे बीजेपी को भी पता है कि वे यहां कमज़ोर हो गए हैं इस वक्त. ऐसा न हो कि फिर से एक सारा का सारा डिस्टर्बेंस हो जाए. अपनी साख बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इनको. उन्होंने खुद भी कहा है कि हमें थोड़ा टाइम दें, हम कुछ करेंगे. पता नहीं वे क्या करेंगे? पता नहीं कैसे महबूबा यहां के लोगों को कन्विंस कर पाएंगी? लेकिन शुरुआत तो करें. हालांकि ये भी अब अप्रैल के बाद ही हो पाएगा. उसके बाद इन्हें देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या सिचुएशन रहती है? हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता हालात को ठीक किया जाए. ये तो चलता रहेगा ऑन द ग्राउंड. एक सिचुएशन तो है, वो चेंज होगी नहीं. लेकिन देखना चाहिए कि इसके साथ इकोनॉमिक्स का भी मसला जुड़ा है. ट्रेड-टूरिज्म वगैरह भी प्रभावित हुआ है.■

– लेखक ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एम) के चेयरमैन हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अंदर सुलगती आग ज्यादा ख़तरनाक होती है

मैंने शोर की बात की. कभी ये सतह पर होती है, कभी सतह के नीचे. कभी ये इतनी नीचे होती है कि आप समझते हैं, अब तो अमन है. फिर आप अचानक देखते हैं कि ये तो शोर मचा रहे हैं, क्या तूफ़ान आ गया है. यानी, ये अमन नहीं था. ये जो आग अंदर सुलगती रहती है, ये ज्यादा ख़तरनाक होती है. मैं सोचता हूं कि अगर आप शांति और नॉर्मल समझते हैं तो आप गलत हैं. कभी शांति और नॉर्मल मत समझना. दिल में अमन चाहिए. घर में अमन चाहिए. जब ये दो चीज़ें सुनिश्चित हो जाती है तो शांति आती है. डंडे से शांति नहीं आती है. भारत की सिविल सोसाइटी यानी आप जैसे लोग जो कर सकते हैं वो यह कि भारत पर दबाव डालिए, पाकिस्तान पर दबाव डालिए कि वो बातचीत करे. फिर कुछ करने के लिए बाक़ी नहीं रहेगा.

प्रोफेसर अब्दुल ग़नी बट

पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह है कि कश्मीर का शोर अक्सर सुनाई देता है, 70 साल रहस्यमई ढंग से सुनाई देता है. ये शोर क्यों उठता है, कहां गलती हो गई? मुझे तो ग़लती भारत की दिखाई देती है. कश्मीर में मौसम सर्द होता है इसके बावजूद यहां के लोगों में गर्मजोशी रही है. भारत यहां लोकतंत्र के शोर के साथ यहां आया. हम उस शोर के साथ कैसी प्रतिक्रिया देते, ये समस्या को समझने की बुनियाद है. भारत लोकतांत्रिक शोर मचाता रहा है. मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे, जैसे ही क़बायलियों को खदेड़ दिया जाता है, भारत जनमत संग्रह करवाएगा. लोग भारत के साथ रहना चाहें तो भारत के साथ रहें, पकिस्तान के साथ जाना हो तो पाकिस्तान के साथ जाएं. यह पहला शोर था. दूसरा शोर कागज़ पर हुआ. विलय की संधि के दिन गवर्नर जनरल ने लिखा कि भारत सरकार की पॉलिसी जो है, वह यह है कि जहां किसी रियासत का भविष्य को लेकर झगड़ा होगा तो उसका फैसला जनमत संग्रह से होगा. एक और शोर एक बहुत ज़बर्दस्त आदमी ने मचाया. जवाहरलाल नेहरू ने. एक कश्मीरी कश्मीर के दिल लाल चौक में शोर मचा रहा था, यदि जम्मू और कश्मीर के लोग पाकिस्तान में विलय को चुनते हैं तो मुझे इसकी तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं इसे रोकूंगा नहीं. यह मेरा वादा है, कश्मीर के लोगों से और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से. कश्मीर के लोगों को जब लगा कि उनके साथ किया गया वादा तोड़ दिया गया तो कश्मीर में शोर शुरू हो गया. भारत ने दिन के उजाले में अपने वादे को तोड़ा. मैं उस के विस्तार में नहीं जाना चाहता. कश्मीर की सामूहिक रूह को गहरा ज़ख्म लगा है, जिसे आपको ठीक करना है.

समस्या को समझने की ज़रूरत है

भारत को गुलमर्ग या पहलगांव नहीं जाना है, बल्कि कश्मीर के ज़ख्मी दिल के अंदर जाना पड़ेगा. क्योंकि भारत ने कश्मीर का दिल दुखाया है, उसके रूह को दर्द दिया है. अब तक जो इलाज किया भी, तो पेट का किया गया. जिसका नतीजा यह निकला कि यह गैप फैलता गया. हालात इतने ख़राब नहीं होते. बहरहाल हमें समस्या को समझना है. हम इसे कैसे समझेंगे और हमें क्या करना चाहिए. मेरा मानना है कि कश्मीर की समस्या सबके नियंत्रण से निकल चुकी है. अब यह ना तो हिंदुस्तान के हाथों में है, ना ही पाकिस्तान के हाथों में और ना ही कश्मीरियों के हाथों में. अगर आप भावनात्मक रूप से देखेंगे तो चीन के हाथ में भी नहीं है. किसी ने मुझ से पूछा कि आख़िर चीन का झंडा क्यों लहराया जा रहा है. जो बच्चा सड़क पर झंडा लहरा है उसकी उम्र क्या है. मुझे विश्वास है कि वो मुझसे उम्र में बड़ा है. मुझसे अधिक परिपक्व है. भारत के लिए कश्मीर समुद्र में एक बूंद की तरह है. भारत एक विशाल देश है. लेकिन कश्मीर बहुत छोटा है और कई हिस्सों में बंटा है. जम्मू, लद्दाख, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, हुर्रियत, फिर एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप. लिहाजा भारत और कश्मीर में कोई तुलना नहीं है. लेकिन फिर क्या मिला आपको. क्या मिला हमें बांटकर. भारत एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल मुल्क है, कश्मीर उसके सामने कुछ भी नहीं. क्या लड़ाई, क्या झगड़ा कर सकते हैं कश्मीर के लोग. कश्मीरी केवल यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपने हमारा ये हश्र कर दिया, फिर भी हम आपसे मज़बूत हैं. हम आपके जुर्मों का जवाब दे सकते हैं. कश्मीरी तो एक मच्छर के समान हैं और हिंदुस्तान विशाल हाथी है. ये मच्छर कोई डंक मारे तो हाथी को पता भी नहीं चलेगा. लेकिन हां कश्मीरी मच्छर ऐसे डंक नहीं मारते हैं, ये नाक के अंदर घुसकर मारता है.

एकमात्र रास्ता बातचीत है

मेरा मानना है कि अब एकमात्र रास्ता है और वह है बातचीत. अगर बातचीत शुरू होती है तो आप कल से ही कश्मीर में बदलाव महसूस कर सकते हैं. मेरे तीन सवाल हैं. क्या यहां के शोर को हम रेगुलर डायलॉग एक्सरसाइज में नहीं बदल सकते? कश्मीर जो पूरे साउथ एशिया में हलचल का कारण बनता जा रहा है, क्या उसे बातचीत से नहीं सुलझा सकते? दूसरा सवाल, क्या हम उन रास्तों पर दोबारा नहीं चल सकते जिन्हें ग़लतियों ने तोड़ दिया? जिस रास्ते पर अटल जी चले थे, जिसपर मनमोहन सिंह ने भी चलने की कोशिश की, क्या उस रास्ते पर दोबारा क़दम नहीं बढ़ाया जा सकता? हमने भारत पाकिस्तान को कई बार नज़दीक आते और फिर दूर जाते देखा है. ये बात करने के लिए एक साथ आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं. क्या संबंधों पर पड़े बर्फ को आपसी बातचीत से पिघलाया नहीं जा सकता है? एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये कि धीरे-धीरे कश्मीर का जंग साउथ एशिया का जंग बनता जा रहा है. यह और भी भयानक रूप लेता जा रहा है. लेकिन भारत-पाकिस्तान में जंग नहीं होगी. दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों जंग कर ही नहीं सकते. लेकिन युद्ध की स्थिति का बने रहना ज्यादा ख़तरनाक है.

हम चुनाव प्रक्रिया में यकीन नहीं रखते. यहां तक कि यूनाइटेड नेशन्स ने भी माना है और ये प्रस्ताव पास किया है कि कश्मीर का विकल्प चुनाव नहीं हो सकता है. लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार को चलाने के लिए चुनाव कराना चाहिए. एक तो ये है और दूसरी, मेरी राय है कि चुनाव में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सवाल है कि चुनाव किस काम के लिए हो? आप कहेंगे शासन के लिए. लेकिन ये शासन किसके द्वारा हो? आप कहेंगे कि वो लोग शासन करेंगे जो चुन कर आते हैं, विधायक बनते हैं. लेकिन, भाजपा तो जम्मू से चुन कर आती है.

मैं समझता हूं कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक सब कंटीनेंटल रिलेशन को बढ़ावा देना चाहिए. उसके बाद अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कि हम कश्मीर के लोगों के बीच जाते हैं चुनाव के लिए. फिर इसके बाद जो भी जीते, जो सरकार बनाए, वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगा. लेकिन, मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान को पहले ये काम करना होगा. हमें शायद नए ढंग से सोचना पड़ेगा. नए विचार की बात करेंगे तो इन चीजों को भूलना पड़ेगा. इस भूलने के अमल में चुनाव को भी रखें. चुनाव अभी नहीं, कश्मीर के लोगों के लिए यह भविष्य की बात हो सकती है. इसलिए, अगर हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाना है तो भारत और पाकिस्तान को साथ लाना होगा, इस मसले से जोड़ना होगा और शुरुआत कश्मीर से करनी होगी.

मेरे ख्याल से इसके लिए पहले प्रयास भी हुए हैं. मुझे अटल जी और मुशर्रफ़ से बात करने का मौका मिला है. उन्होंने प्रयास किए थे. उन्होंने दुख से कहा था कि प्रोफेसर इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा. दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई ज़रूरी नहीं कि लड़ कर सुलझाएं. मित्रता के साथ सुलझाएं. शायर भी थे अटल जी. फिर जनरल साहब (मुशर्रफ़) को ले लीजिए. वो तो फौजी थे, इसलिए उनकी बात सीधी चलती थी. उसमें कोई टेढ़ापन नहीं था. कोई लड़ाई नहीं होगी. कोई किसी को पछाड़ नहीं सकता है. हिंदुस्तान हमको नहीं पछाड़ सकता. हम हिंदुस्तान को नहीं पछाड़ सकते हैं. अब हमें एक साथ रहने का ढंग सीखना पड़ेगा. करगिल के बाद अब जो बात करता है, वो कहता है कि अब हिंदुस्तान-पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहना सीखना पड़ेगा. तीसरी बात भी उन्होंने कही कि इसमें हमारी कोशिश है कि हमने ये जो प्रोसेस शुरू किया है, अब आप लोगों को बड़ी मार खानी पड़ी है, आप लोगों की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी मार खानी पड़ी है. वो बात सच्ची है. कश्मीर पर ही दो-तीन बार लड़ाइयां हुईं. इसलिए हम चाहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा ख़याल रखा जाए. ये तो हम दोनों का फ़ैसला है कि आपका हम बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे. शायद पूरा ख्याल नहीं रखा जा सके. लेकिन बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे. ये तो ऐसे ही चलेगा न. ऐसे नहीं चलेगा जैसे अभी राम माधव कह रहे थे.

डंडे से शांति नहीं आती है

कश्मीर और श्रीनगर की स्थिति जो दिल्ली समझ रही है कि शांति आ गई है, नॉर्मल सिचुएशन आ गया है, ये बिल्कुल गलत है. यहां न शांति है न नॉर्मलसी है. मैं तो कहूंगा कि शोर है, कल तक सतह पर थी, आज नीचे है. कश्मीर में एक कहावत है- कुएं में कुत्ता गिरा था, कुएं से पानी तो निकाला नहीं जा सकता. पानी तो गंदा हो गया. वो मौलवी साहब के पास चले गए. मौलवी साहब ने गांव के लोगों से कहा कि आप 40 बाल्टी पानी निकाल कर पी लीजिए. तो उन्होंने 40 बाल्टी पानी निकाल लिए. दूसरे दिन फिर मौलवी साहब के पास गए. मौलवी साहब ने सोचा कि शायद 40 बाल्टी निकाले होंगे, लेकिन इनकी तसल्ली नहीं होगी, और 40 निकालें. तीसरे दिन भी कहा कि और 40 निकालें. चौथे दिन मौलवी साहब की अक़ल जागी तो उन्होंने कहा कि अच्छा कुत्ते को निकाला था. उन्होंने कहा कि नहीं. कुत्ते को निकालना है. क्या समझते हैं आप? कुत्ते को निकालना है. पानी खुद साफ़ हो जाएगा. आप तो पानी निकालते हैं, कुत्ते को तो वहीं रखे हुए हैं.

मैंने शोर की बात की. कभी ये सतह पर होती है, कभी सतह के नीचे. कभी ये इतनी नीचे होती है कि आप समझते हैं कि अब तो अमन है. फिर आप अचानक देखते हैं कि ये तो शोर मचा रहे हैं, क्या तूफ़ान आ गया है. यानी, ये अमन नहीं था. ये जो आग अंदर सुलगती रहती है, ये ज्यादा ख़तरनाक होती है. मैं सोचता हूं कि अगर आप शांति और नॉर्मल समझते हैं, तो आप ग़लत है. कभी शांति और नॉर्मल मत समझना. दिल में अमन चाहिए. घर में अमन चाहिए. जब ये दो चीज़ें सुनिश्चित हो जाती हैं, तो शांति आती है. डंडे से शांति नहीं आती है. भारत की सिविल सोसाइटी यानी आप जैसे लोग जो कर सकते हैं वो यह कि भारत पर दबाव डालिए, पाकिस्तान पर दबाव डालिए कि वो बातचीत करे. फिर कुछ करने के लिए बाक़ी नहीं रहेगा. सिर्फ़ एक बार दबाव डालिए. ■

-लेखक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन और अभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं.)

भारत को गुलमर्ग या पहलगांव नहीं जाना है, बल्कि कश्मीर के ज़ख्मी दिल के अंदर जाना पड़ेगा. क्योंकि भारत ने कश्मीर का दिल दुखाया है, उसके रूह को दर्द दिया है. अब तक जो इलाज किया भी, तो पेट का किया गया. जिसका नतीजा यह निकला कि यह गैप फैलता गया. हालात इतने ख़राब नहीं होते. बहरहाल हमें समस्या को समझना है. हम इसे कैसे समझेंगे और हमें क्या करना चाहिए. मेरा मानना है कि कश्मीर की समस्या सबके नियंत्रण से निकल चुकी है. अब यह ना तो हिंदुस्तान के हाथों में है, ना ही पाकिस्तान के हाथों में और ना ही कश्मीरियों के हाथों में. अगर आप भावनात्मक रूप से देखेंगे तो चीन के हाथ में भी नहीं है. किसी ने मुझसे पूछा कि आख़िर चीन का झंडा क्यों लहराया जा रहा है?

लोगों को दबा कर बात नहीं मनवा सकते

बातचीत ही एकमात्र रास्ता है

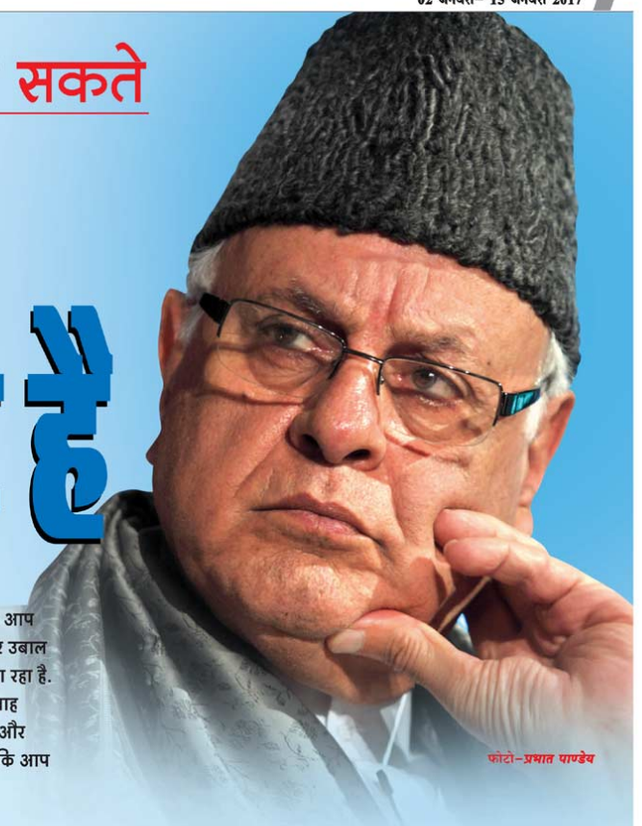

फोटो–प्रभात पाण्डेय

हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि कश्मीर को वे जितना दबाएंगे उतना उसका ओपोजिट रिएक्शन होगा. लोगों को आप मार काट कर, उन्हें दबाकर अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं. मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि यहां अंदर ही अंदर उबाल है और ईद से पहले कुछ होने वाला है. बुरहान वानी तो सिर्फ़ एक चिंगारी थी. असली कारण तो वही है, जो चला आ रहा है. मैं तो यही कहूंगा कि जो हो गया, सो हो गया, अब आगे की बात सोची जाय. मुल्क को बचाना है या मुल्क को तबाह करना है, यह अब दिल्ली को सोचना है. एक बड़ी समस्या यह है कि कोई भी बात कर रहा है तो उसपर एंटीनेशनल और पाकिस्तानी का लेवल लगा देते हैं. अब ज़रूरत है कि इन जख्मों पर मरहम लगाया जाए. लोगों को लगना चाहिए कि आप उनके दुश्मन नहीं हैं. जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लीजिए कश्मीर शांत नहीं होगा.

फ़ारूक़ अब्दुल्ला

कश्मीर मसले पर बात करते वक्त दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को समझना चाहिए कि पड़ोसी को नज़रअंदाज़ कर के आगे नहीं बढ़ सकते. अटल जी ने कहा था, दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी तो नहीं बदल सकते. उसके साथ आपको हर वक्त डील करना है. वो भी जानते हैं कि वो आपका कश्मीर नहीं ले सकते और आप भी जानते हैं कि आप उनका कश्मीर नहीं ले सकते. तो फिर झगड़ा किस बात का? वे क्यों नहीं आगे आ कर स्टेकहोल्डर्स से बात करते हैं? गिलानी अपनी लाइन से हटेंगे नहीं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप उनकी लाइन को समझते रहिए, लेकिन दूसरों के साथ भी बात कीजिए. जहां तक जनमत संग्रह की बात है तो मेरा मानना है कि यह अभी संभव नहीं है. जनमत संग्रह किस बात पर हो? क्या पाकिस्तान पीओके और उत्तरी क्षेत्र से अपनी फ़ौज निकालेगा? सवाल इस बात का है कि उनको भी तो दिमाग ठीक करना चाहिए. बात करने से ही कोई रास्ता निकलेगा. अगर बात करने के बग़ैर रास्ता निकलना होता, तो वाजपेयी क्यों बात शुरू करते. आप पहले ही कह देंगे कि बात संभव ही नहीं है, तब तो यह मसला ऐसे ही रह जाएगा. बात शुरू तो हो. हो सकता है कि 10 मुद्दों पर एक राय नहीं बने लेकिन एक–दो मुद्दों पर तो बात हो सकती है. रास्ता तो ऐसे ही निकलेगा.

आज तो कश्मीर में महबूबा कुछ नहीं हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री किसी को मुआवज़ा दे और सहयोगी पार्टी शोर मचाने लगे. महबूबा ने बुरहान के भाई को मुआवज़ा दे दिया, उसपर भी भाजपा ने हल्ला मचा दिया. एक हैं राम माधव. इन्होंने तो कश्मीर का बेड़ा ग़र्क़ कर दिया, अब हिंदुस्तान को भी जलाकर ही छोड़ेंगे. इस तरह से आप कश्मीर को हल नहीं कर सकते बल्कि मसला और उलझता जाएगा. हमारी मुसीबत ये है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं. वे हिंदुस्तान को समझ ही नहीं पा रहे हैं. बच्चों को गिरफ्तार कर अंदर कर के आप कश्मीर समस्या का समाधान नहीं कर सकते. एक ही रास्ता है कि इस पार और उस पार दोनों तरफ़ ऑटोनोमी मिले और बॉर्डर को सॉफ्ट किया जाए.

जितना दबाएंगे उतना ही ओपोजिट रिएक्शन होगा

आज तो कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि यहां कोई हुकूमत ही नहीं है. 10–12 हज़ार से ज्यादा बच्चे और बूढ़े जेलों में बंद हैं. क्या 70 साल का बूढ़ा पत्थर मारेगा? लेकिन उन्हें भी जेल में बंद रखा गया है. उनकी तो ये मंशा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बंद करो. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी बंदूक़ और पत्थर उठाई है? सरकार भी आज उसी ख़ून–ख़राबे में शामिल हो गई जो 90 के दशक में शुरू हुआ था. इसलिए मैंने अपने पार्टी वर्कर्स से कहा कि हुर्रियत के साथ खड़े हो जाओ, जो होगा हम सबका होगा. ये तो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया? असल में दिल्ली ने हमें हमेशा बांटा है. दिल्ली ने कश्मीर में हमेशा बांटो और शासन करो की नीति अपनाई है. हमें यहां के लोगों से बात करके, उन्हें विश्वास में लेकर कदम बढ़ाना चाहिए. सबकी ओपिनियन अलग–अलग हो सकती है. सबकी अपनी परेशानियां भी हैं. उमर फ़ारूक़ की अपनी मुश्किलें हैं. यासीन मलिक केवल आज़ादी के मसले पर आपसे बात कर सकते हैं. लेकिन वे रेबेल नहीं हैं. कश्मीर को लेकर हमें एक तरह से बात कर के मसले को आगे बढ़ाना होगा.

हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि कश्मीर को वे जितना दबाएंगे उतना उसका ओपोजिट रिएक्शन होगा. लोगों को आप मार काट कर, उन्हें दबाकर अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं. मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि यहां अंदर ही अंदर उबाल है और ईद से पहले कुछ होने वाला है. बुरहान वानी तो सिर्फ़ एक चिंगारी थी. असली कारण तो वही है, जो चला आ रहा है. मैं तो यही कहूंगा कि जो हो गया, सो हो गया, अब आगे की बात सोची जाय. मुल्क को बचाना है या मुल्क को तबाह करना है, यह अब दिल्ली को सोचना है. एक बड़ी समस्या यह है कि कोई भी बात कर रहा है तो उसपर एंटीनेशनल और पाकिस्तानी का लेवल लगा देते हैं. अब ज़रूरत है कि इन ज़ख्मों पर मरहम लगाया जाए. लोगों को लगना चाहिए कि आप उनके दुश्मन नहीं हैं. जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लीजिए कश्मीर शांत नहीं होगा.

वे लोग समझते हैं कि अब स्कूल भी खुल जाएंगे, अब ट्रैफिक भी चल रहा है. वे नहीं समझ रहे कि जाड़े के बाद ये सब फिर से शुरू हो जाएगा. फिर आप क्या करोगे? कहा जा रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद यहां पैसा आना बंद हो गया इसलिए मिलिटेंसी ख़त्म हो गई. बेवकूफ़ हैं वे लोग जो ऐसा कह रहे हैं. अगर यहां इतनी ब्लैक मनी थी तो फिर लोग लाइन में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं. ब्लैक मनी को जमा कराने के लिए तो लोगों को लाइन में लगना चाहिए था न. आज यहां बैंकों को लूटा जा रहा है. जब काला पैसा ही होता तो बैंकों को क्यों लूटते? बताइए कहां है ब्लैक मनी? जहां ब्लैक मनी है, जहां ब्लैक मनी की एक समानांतर इकोनोमी चल रही है, उसे तो ये पकड़ नहीं पा रहे. वैसे भी हमारे लोग पहाड़ों पर रहते हैं, वहां कोई बैंक नहीं है, कोई एटीएम नहीं है. हमारे यहां ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होता है. आप कुछ भी नहीं कर सकते. अगर एटीएम से पैसे निकालते भी हैं, तो सिर्फ़ दो हज़ार रुपये ही मिलेंगे. आप कहते हैं कि अब मोबाइल इस्तेमाल करो. मेरे पास फोन है, मैं इस्तेमाल करता हूं. लेकिन उसके लिए हज़ारों रुपए का फोन कौन लेगा. यहां तो वैसे भी साधारण मोबाइल नहीं चलता. एयरटेल कनेक्टिविटी के लिए कई सारे नियम–क़ानून हैं. अब जियो आया है. जियो का तो टावर ही नहीं है. दूसरों से टावर उधार लिया है.

बॉर्डर को सॉफ्ट किया जाए

आज तो कश्मीर में महबूबा कुछ नहीं हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री किसी को मुआवज़ा दे और सहयोगी पार्टी शोर मचाने लगे. महबूबा ने बुरहान के भाई को मुआवज़ा दे दिया, उसपर भी भाजपा ने हल्ला मचा दिया. एक हैं राम माधव. इन्होंने तो कश्मीर का बेड़ा ग़र्क़ कर दिया, अब हिंदुस्तान को भी जलाकर ही छोड़ेंगे. इस तरह से आप कश्मीर को हल नहीं कर सकते बल्कि मसला और उलझता जाएगा. हमारी मुसीबत ये है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान का बेड़ा ग़र्क़ करना चाहते हैं. वे हिंदुस्तान को समझ ही नहीं पा रहे हैं. बच्चों को गिरफ्तार कर अंदर कर के आप कश्मीर समस्या का समाधान नहीं कर सकते. एक ही रास्ता है कि इस पार और उस पार दोनों तरफ़ ऑटोनोमी मिले और बॉर्डर को सॉफ्ट किया जाए. जब यशवंत सिन्हा आए तो एक आशा जगी कि इन लोगों में कोई है जो कश्मीर की भलाई सोच रहा है. वे देख रहे हैं कि यहां जो हो रहा है वह गलत हो रहा है. हमें भी लगा कि वे कश्मीर मसले का रास्ता ढूंढना चाहते हैं. अबकी बार जब वे दूसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए तो ये हुआ कि इस बार वे बारामूला भी जा सके, अनंतनाग भी जा सके. वे सभी स्टेक होल्डर्स और सभी लोगों से मिले. वे हममें भी एक आशा जगा गए. लेकिन अफ़सोस कि प्रधानमंत्री तो यशवंत सिन्हा को सुनना नहीं चाहते हैं. तीन पत्रकार आए, उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने सही तरह से कश्मीर की समस्या को रखा. जो पार्लियामेंट्री डेलिगेशन आया था, उन्हें गृह मंत्री के मार्फ़त आना चाहिए था, तब हो सकता है कि ये उनसे बात करते. तब नौबत नहीं आती कि ये दरवाज़ा नहीं खोलते. भाजपा कह रही है कि अब इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते. अभी तक तो आप इन्हें रिकॉग्नाइज करते थे और अब अचानक इन्हें साइड कर दिए. आज तक तो आप आईबी के जरिए पैसा देते रहे हैं इनको. मैं जानता हूं न. मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए भी आईबी के जरिए पैसे पहुंचाए जाते थे.

बिना शर्त बातचीत हो

मैं हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा हूं. हम बातचीत के माध्यम से किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जब बात ही नहीं होगी तो फिर मसला तो वहीं का वहीं रह जाएगा. यहां के लोग क्या सोचते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है. आप जब तक लोगों के हक में कोई काम नहीं करेंगे, उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, आप उनका समर्थन नहीं ले सकते. आप अपना राष्ट्रीय हित देखिए लेकिन वह यहां के लोगों की जान की क़ीमत पर तो नहीं हो सकती. मोदी जी जो समझते हैं कि आहिस्ता–आहिस्ता ये सब ठीक हो जाएगा, तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा, जैसे सरकार करना चाह रही है. ये अपने टर्म–कंडीशंस पर बात करना चाहते हैं. ये इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं. ये सोच रहे हैं कि परिस्थितियां इनके अनुरूप बनेंगी. लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता न. एक ग़लतफ़हमी इंदिरा गांधी ने पाल रखी थी. उन्होंने सोचा था कि शेख अब्दुल्ला बहुद जल्दी मर जाएगा और हम मनमाने ढंग से इसका रास्ता निकाल लेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इंदिरा को तो पता भी था कि अगर एक बार आग लग जाएगी कश्मीर में, तो उसे बुझाना मुश्किल होगा. नरसिम्हा राव ने संसद में कहा था, जहां तक ऑटोनॉमी की बात है, स्काई इज द लिमिट लेकिन आजादी नहीं. हमने कहा, हम तो आज़ादी मांगे ही नहीं. मैंने कहा कि अगर हमारी मांग में कुछ भी संविधान के विरुद्ध है, तो बताइए. मोदी जालंधर और अमृतसर में तक़रीर करते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान का सारा पानी रोकने वाले हैं और जिन नदियों का उन्होंने नाम लिया वे हैं, सतलज, रावी और व्यास. जो निस्संदेह भारत के हैं. साथ ही झेलम, सिंध और चिनाब ये भी हमारे ही हैं. मुझे तो शर्म महसूस हुई कि प्रधानमंत्री ने इंडस वाटर ट्रीटी को समझा ही नहीं है. हम तो चिनाब पर बांध भी नहीं बना सकते हैं, जब तक उनके इंजीनियर नहीं आते और नहीं देखते. पूरे कश्मीर को सर्वाइव करना पड़ेगा.■

–लेखक नेशनल कांफ्रेंस के चेयरमैन हैं

सलाहियत है, लेकिन दिल की कमी है

मोहम्मद युसूफ तारीगामी

हमारी पार्टी ने फ़ैसला किया था कि अगर थोड़ी सी जानकारी मिल जाए कि हमारी तरफ से कहां-कहां जाना मुमकिन हो तो हम भी अपनी तरफ़ से जा कर बातचीत करें. कई इंटेलेक्चुअल ग्रुप केसाथ मेरी बात हुई. दो-तीन मीटिंग्स हुई. मैं महाराष्ट्र भी गया था. मैंने कोलकाता में भी कहा था कि अब हमें आपसे सुनने की ज़रूरत है. हमने बहुत कुछ सुनाने की कोशिश की कश्मीर में. कभी नाराज़ हो गए, कभी राज़ी हो गए. कभी गले मिले. लेकिन आज तक कहीं भी इसका एंड रिजल्ट (अंतिम परिणाम) नजर नहीं आता है. नाराज़गी का इज़हार करते हुए लोगों ने बंदूकें भी उठाईं. पत्थर भी उठाए. फिर बैठ भी गए, चुप भी हो गए. मर भी गए, जेल भी गए. लेकिन, हाकिम लोग सुनते नहीं. कम से कम सिविल सोसाइटी के लोग ही हमारी बात सुनें और हमारी सिफ़ारिश करें.

लोग हम सबसे नाराज़ हैं

हमारी बात को कोई तो सुने. यहां (कश्मीर में) करना कुछ नहीं है. यहां कुछ होगा भी नहीं. अगर कुछ करना है तो वह अथॉरिटी को सोचना है. अथॉरिटी अगर मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचती है, तो कश्मीर की भलाई भी उसी में है. मैं यह कहीं भी महसूस नहीं करता कि कश्मीर को आइसोलेशन में देखा जाए. यहां बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. कभी डराने की बातें, कभी धमकाने की बातें. कभी मायूसी की बातें, कभी नाराज़गी की बातें. कुल मिला कर ये है कि लोग मायूस हैं, नाराज़ हैं और कोई रास्ता चाहते हैं. गिलानी साहब अलग कुछ कहेंगे, फ़ारूक़ साहब कुछ कहेंगे. हम तुम्हारे साथ, तुम हमारे साथ. लेकिन सच तो ये है कि लोग हम सब से नाराज़ हैं. उस वक्त (पहले) लोग सिर्फ हमसे नाराज़ थे, दिल्ली से नाराज़ थे, मेनस्ट्रीम से नाराज़ थे, आज हम सबसे नाराज़ हैं. मैं आज ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि हमारी पहचान हिन्दुस्तान के साथ है. फ़ारूक़ साहब कुछ भी कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी कहें, एक हिस्ट्री (इतिहास) है. इतनी जल्दी आप उस पहचान को बदल नहीं सकते. कोई कहे कि सप्रेशन में कश्मीर का फ्यूचर है, मैं नहीं मानता हूं.

हमें वही काम करना होगा, जिसे हम अवाम के लिए ठीक समझते हैं, जिसे हम हल समझते हैं. बाक़ी, तो क़ौमें मिट गई हैं, जब आपस में टकराव हुआ. कभी कंफ्रंटेशन के नाम पर, कभी वार में छोटी-छोटी कौमें मिट गईं इतिहास से. ये यहां भी हो सकता है. यहां भी हो रहा है. यहां की लीडरशीप में बशरियत की कमी है, लेकिन यहां की ज़िम्मेदारियां कम हैं. यहां का सारा काम आपके सामने है. मुल्क के पॉलिटिकल क्लास, ख़ास कर वो सेक्शन जिनके हाथ में लगाम है, वहां से मैं मायूस हूं. यहां की बड़ी आबादी, भारत सरकार से कोई भी इनिशिएटिव, कुछ भी इनिशिएटिव चाहती है. यहां के लोग बाहर से आए सिविल सोसाएटी के लोगों से बेधड़क मिलते हैं. लोग चाहते हैं कि सिविल सोसायटी के लोग उनके दिल की बात करते, दुनिया को बताते, ये जानते हुए भी कि आप अथॉरिटी नहीं हैं. लेकिन लोग यह जान कर सिविल सोसाएटी के मेंबर्स का इस्तक़बाल करते हैं कि वे उनके दर्द-ए-दिल को महसूस करते हैं, समझते हैं. ये इज़हार क्या है? लोग कहीं से एक छोटी सी कोशिश होती भी देखते हैं, तो उधर दौड़ पड़ते हैं. इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हक़ीक़त का सामना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं, ऐसे लोग सभी जगह हैं. ऐसे लोगों को कल फ्रीडम भी दे दें तो भी कल को आपस में टकराव होगा. लेकिन, जिन लोगों के पास सब करने के लिए है, वहां से मुझे मायूसी नज़र आती है.

तहरीक चलाने के लिए लीडरशिप में सलाहियत की कमी है

अगस्त के महीने में जम्मू में हमारे वित्त मंत्री का भाषण था. उनके साथ पीएमओ के मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह भी थे. उन्होंने कहा कि कश्मीर में हज़ार की संख्या में लोग पुलिस थानों, आर्मी कैंप में आते हैं, हमला करने के लिए, तो इसके बदले गोली तो चलेगी ही. मैंने वहीं से अपनी बात शुरू की और कहा कि ये लोग यह जान कर ही आते हैं कि वहां गोली चलेगी. गोली अगर जवाब होता तो वह चलती रहेगी. बहुत सारे मुल्कों में चलती आई है, चलती रही है, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं. मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क में ऐसा हो, मेरी रियासत में ऐसा हो. उसी भाषण में डॉ. जितेन्द्र ने भी कहा था कि हम कोटली में झंडा फहराएंगे. मैंने कहा कि ये डॉक्टर रहे हैं, मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मेरे भी डॉक्टर रहे हैं. मैं अभी भी पेशेंट हूं, लेकिन ये अब डॉक्टर नहीं रहे. मैंने कहा कि आप जब गोलियों की बारिश में झंडा फहराने के लिए लाल चौक पर आए, मुरली मनोहर जोशी साहब के साथ. लेकिन, मैं ये ख़बर दे देता हूं कि वो जगह आपने जहां झंडा फहराया था, वो जगह आज सुर्ख़ हो रही है इस देश में झंडा के लिए. उस भाषण में इन नेताओं ने दुनियाभर की बात की, लेकिन कश्मीर के दर्द

अगस्त के महीने में जम्मू में हमारे वित्त मंत्री का भाषण था. उनके साथ पीएमओ के मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह भी थे. उन्होंने कहा कि कश्मीर में हज़ार की संख्या में लोग पुलिस थानों, आर्मी कैंप में आते हैं, हमला करने के लिए, तो इसके बदले गोली तो चलेगी ही. मैंने वहीं से अपनी बात शुरू की और कहा कि ये लोग यह जान कर ही आते हैं कि वहां गोली चलेगी. गोली अगर जवाब होती तो वह चलती रहेगी. बहुत सारे मुल्कों में चलती आई है, चलती रही है लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं.

के बारे में दो लफ्ज भी नहीं कहे.

मैं नहीं जानता कि आज हमारा देश किस तरह से चल रहा है. कश्मीर में पिछले 4-5 महीनों में जो हुआ, ऐसा लगता है बाक़ी देश के लिए कुछ हुआ ही नहीं है. हमारी बदक़िस्मती ये है कि लीडरशिप भी इस बात को नहीं समझती है. यदि, लीडरशिप सलाहियत वाली हो जो अवामी तहरीक को चलाए, उसमें कमी है. कितना चलना है, कितना खींचना है किसी चीज को. कश्मीर बार-बार राजनीतिक-आर्थिक तौर पर अलग-थलग पड़ जाता है. कश्मीर की तिजारत को भारी नुकसान हुआ है. टूरिज्म यहां की मुख्य तिजारत (व्यापार) है. उसका हाल खराब हो गया है. कौन यहां इस ठंड में आएगा घूमने के लिए. बाकी , एग्रीकल्चर, हॉर्टीकल्चर का भी ज्यादा ध्यान नहीं रखा जा सका. मार्केटिंग ठीक तरीके से नहीं हुई. उसका भी भारी नुक़सान हुआ है.

मैं समझता हूं कि ये एक अवसर था, लीडरशिप अगर इस वक्त आगे आती तो उम्मीद की जा सकती थी कि कल तक जिनलोगों ने बातचीत के लिए दरवाज़े बंद किए थे, वो दरवाज़ा खोलते. लेकिन, उस अवसर का इस्तेमाल करने के लिए दिल चाहिए. मैं ये नहीं कहूंगा कि सलाहियत नहीं है. इतने बड़े मुल्क को चलाने वाले में कुछ तो सलाहियत होगी ही. मैं नहीं कहूंगा कि क्षमता नहीं है. इतना झूठ पर झूठ, मुल्क चलता रहा है. सलाहियत है, लेकिन दिल की कमी है. इससे पूरे मुल्क का नुक़सान है. हम सब का नुक़सान है.

कोशिशें जारी रहनी चाहिए

डीमोनेटाइज़ेशन का सवाल जो भी हो, अच्छा या बुरा, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं तो संसद की वजह से हैं और आप संसद में बोलते नहीं हैं. अपोज़ीशन अगर आपको चार गालियां देता तो वहीं पर देता. आप कहते हैं कि अपोज़ीशन बोलने नहीं देता. ठीक है, तो फिर दुनिया देखती कि अपोज़ीशन आपको कैसे नहीं बोलने दे रहा है. वैसे, प्राइम मिनिस्टर को बोलने से कोई नहीं रोकता. प्राइम मिनिस्टर के भाषण के बीच आमतौर पर संसद में कोई भी व्यवधान पैदा नहीं करता है. अगर अपोज़ीशन व्यवधान भी पैदा करता तो दुनिया देखती कि इतने बड़े कद के प्रधानमंत्री को अपोज़ीशन ने कैसे नहीं बोलने दिया. अगर लोग उनके बोलने में रुकावट डालते तो इल्ज़ाम अपोज़ीशन पर आता. लोग कहते कि प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं लेकिन अपोज़ीशन कुछ बोलने नहीं दे रहा है. लेकिन, प्रधानमंत्री ने संसद की परवाह ही नहीं की. घंटों टेलीविजन पर बोलते रहे. जिस संसद ने उन्हें इतना बड़ा ओहदा दिया है, प्राइम मिनिस्टर होने की इज्ज़त बख्शी है, उसकी ही परवाह नहीं की. इसका मतलब है कि वो संस्थाओं के महत्व को कम समझ रहे हैं. उसे कमतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यह देश के भविष्य के लिए चिंतानजक है. इस तरह का अहंकार देखते हुए इस बात की गुंजाइश कम नजर आती है कि वे कश्मीर का दर्द समझें. इस तरह के अहंकारपूर्ण मनोवृत्ति में कश्मीर एक छोटी सी जगह है, तो फिर इनकी बात को क्यों सुने. उल्टे, ये सोच हो सकती है कि इन्हें सबक सिखाया जाए. ऐसा मुझे लग रहा है. मैं ग़लत हो सकता हूं. मेरी गुज़ारिश है कि कोशिशें जारी रहनी चाहिए. ऐसा लगता है कि इतने बड़े देश में कुछ लोग हैं, जो दर्द को बांटना चाहते हैं. मेरे ख्याल में ये भी बड़ी बात है. सिविल सोसाइटी के लोग हमसे मिलने आते हैं, ये अच्छी बात है. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव इससे निकल ही आए. लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि उम्मीद बनी रहे. मैं समझता हूं कि ये बात ही सबसे महत्वपूर्ण है.■

लेखक सीपीआई (एम) के नेता और जम्मू-कश्मीर विधान सभा के सदस्य हैं.

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीर के हालात को लेकर कमल मोरारका की साफ़गोई

हारून रेशी

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कमल मोरारका को श्रीनगर की यात्रा के दौरान यहां के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर से जो सराहना मिली, उससे एक बार फिर यह बात साबित हुई कि कश्मीरी जनता और उनके नेतृत्व को विश्वास है कि भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कश्मीर के प्रति भारतीय राज्य से अलग, बल्कि जनाभिमुख नज़रिया रखते हैं. भारतीय विद्वानों और सिविल सोसायटी पर कश्मीरियों के विश्वास को उस समय और बल मिला, जब कमल मोरारका ने अपनी तीन दिवसीय यात्रा के समापन पर श्रीनगर में अपनी प्रेस कांफ्रेंस में बिना किसी लाग-लपेट के कश्मीर के प्रति भारत सरकार के व्यवहार को ग़लत बताया. कमल मोरारका ने कहा कि वह कश्मीर में सिविल लिबर्टी और मूल अधिकारों के अभाव को देखकर हिल गये हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले का हल तो बाद में होगा, पहले कश्मीरियों को वे मूल अधिकार तो दे दो, जो उन्हें भारतीय संविधान प्रदान कर रहा है. हालांकि संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर को शेष राज्यों के मुक़ाबले में अधिक अधिकार प्राप्त हैं. लेकिन व्यावहारिक रूप से यहां के बाशिंदों को इतने अधिकार भी प्राप्त नहीं, जितने किसी अन्य राज्य के बाशिंदों को प्राप्त हैं. कमल मोरारका ने अपनी तीन दिवसीय कश्मीर यात्रा के दौरान कश्मीर के जिन उल्लेखनीय व्यक्तियों और नेताओं से भेंट और वार्ता की, उनमें सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़, नईम अहमद ख़ां, प्रो.अब्दुल गनी बट, शब्बीर अहमद शाह, डॉक्टर फ़ारूक़ अब्दुल्ला, सैफ़ुद्दीन सोज़, गुलाम अहमद मीर, इंजीनियर रशीद, युसूफ तारीगामी आदि शामिल हैं. इसके अलावा इन्होंने कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक टीम, सिविल सोसायटी, ट्रेडर्स और स्टूडेंट्स के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों और कई आम लोगों से कश्मीर के वर्तमान हालात और समस्याओं पर खुलकर बातचीत की.

उल्लेखनीय है कि कश्मीर के राजनीतिक गलियारों और अवाम के बीच एक आम धारणा है कि कश्मीर में पिछले तीन दशकों के हिंसक हालात के दौरान भारत सरकार कई बार महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्तियों को आग बुझाने के अमल के लिए प्रयोग करते हुए उन्हें कश्मीर भेजती रही है. वे लोग यहां जनता को यह विश्वास दिलाने का काम करने के लिए आते थे कि वे वापस जाकर भारत सरकार को कश्मीर समस्या हल करने पर सहमत कराएंगे. लेकिन बाद में साबित हो जाता था कि दिल्ली की ओर से भेजे जाने वाले ये लोग अपनी विश्वसनीयता का प्रयोग कर दरअसल कश्मीरी नेताओं और यहां की जनता को छलते रहे हैं. परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों ने, जिनके नामों की सूची लंबी है, कश्मीर में अपनी विश्वसनीयता ही खो दी. यही वजह है कि कश्मीर को कुछ राजनीतिक विश्लेषक, विश्वसनीय व्यक्तियों के विश्वास का क़ब्रिस्तान क़रार दे रहे हैं. लेकिन कमल मोरारका को इस लिहाज़ से एक विश्वास योग्य व्यक्ति कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में ही स्पष्ट कर दिया कि वह न ही भारत सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां आये हैं और न ही इस बात की कोई ज़मानत दे सकते हैं कि उनकी बातों पर केंद्र सरकार कोई अमल करेगी. उन्होंने कहा कि वह केवल एक इंसान, दोस्त और नागरिक की हैसियत से घाटी आए हैं और वापस जाकर अपने जैसे लोगों को यहां सच्ची और आंखों देखी स्थिति से अवगत कराएंगे. यानी कमल मोरारका ने इन तमाम संभावनाओं को ख़त्म कर दिया, जिनके कारण भविष्य में कोई यह कह सकता था कि उन्होंने नई दिल्ली के इशारे पर कश्मीरी लीडरशिप या जनता को छलने की कोशिश की. कमल मोरारका को श्रीनगर में हाथों-हाथ लिए जाने के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि उन्हें यहां प्रसिद्ध पत्रकार और चौथी दुनिया के चीफ़ एडिटर संतोष भारतीय लेकर आए थे. अपनी तीन दिवसीय यात्रा में हालात का जायज़ा लेने के बाद जब संतोष भारतीय वापस गए, तो उन्होंने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा की पोल खोल कर रख दी. उन्होंने वापस जाकर भारतीय प्रधानमंत्री के नाम एक खुले ख़त में कश्मीर के हालात व घटनाओं का भरपूर उल्लेख किया. उन्होंने अपने विभिन्न लेखों में इस झूठ से पर्दा उठाया, जो भारतीय मीडिया कश्मीर के बारे में फैला रहा था. उन्होंने कहा कि यह ग़लत है कि कश्मीर में पथराव की वजह से सुरक्षा बलों के हज़ारों जवान घायल हुए हैं.

यह ग़लत है कि कश्मीर में लड़के पांच-पांच सौ रुपये के बदले सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं. यह कहना भी ग़लत है कि कश्मीरी जनता स्वभाविक रूप से हिंसावादी है और यह कि कश्मीर में जारी आन्दोलन महज़ एक गिरोह की पैदावार है और इसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है. संतोष भारतीय ने अपने क़लम के द्वारा न केवल कश्मीर की ज़मीनी हालात को अपने देश की जनता के सामने रखा, बल्कि झूठे प्रोप्रेगेंडा से पर्दा हटाने की कोशिश भी की. वह ख़ुद कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक पत्रकार का असल किरदार अदा किया. एक पत्रकार का बुनियादी काम यही तो है कि वह सच्चाई बयान करे. मैंने कोई असाधारण काम नहीं किया बल्कि अपने पवित्र पेशे के साथ न्याय करने की कोशिश की है.

शब्बीर अहमद शाह, जो जेल में हैं, ने मुलाक़ात के दौरान उन्हें बताया कि वह जेल में रहकर कश्मीर से संबंधित उनके हर लेख को पढ़ चुके हैं. नईम ख़ान ने कहा कि भारत में बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं, जो कश्मीर के बारे में सच लिखते और कहते रहे हैं, आप वक़ीनन उनमें से एक हैं. सिविल सोसायटी और ट्रेडर्स के प्रतिनिधियों ने भी अपनी मुलाक़ातों में उनका धन्यवाद किया.■

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली एग्रीमेंट कश्मीर मसले के समाधान का फॉर्मूला

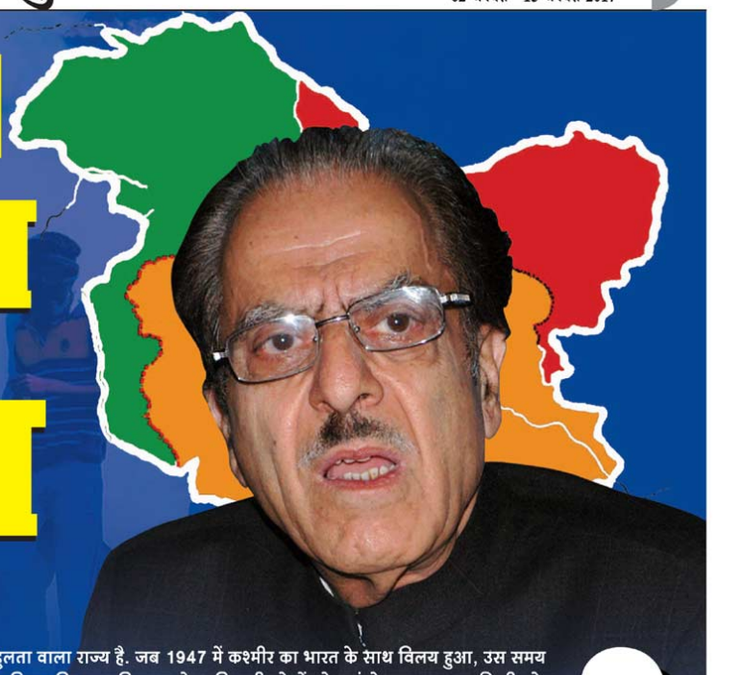

कश्मीर (मैं कश्मीर कहता हूं, जम्मू और लद्दाख का नाम जान-बूझकर नहीं लेता), मुस्लिम बहुलता वाला राज्य है. जब 1947 में कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ, उस समय यहां 98 प्रतिशत मुसलमान थे. कश्मीर के लोगों ने जान-बूझकर एक धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ विलय किया. पाकिस्तान ने आदिवासी लोगों को यहां भेजकर यलग़ार की थी. शेख़ अब्दुल्ला सोच ही रहे थे कि हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ भी बात करनी पड़े, उससे पहले ही 20-22 अक्टूबर को यलग़ार कर दी. इससे और ख़टास पैदा हो गई. यहां के लोग शेख़ अब्दुल्ला के साथ रहे. इन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ एक शर्तिया विलय किया. शर्तें तो पहले महाराजा हरि सिंह ने रखी थीं, क्योंकि इन्होंने शिकायत की (विलय के दस्तावेज़ में यह है) कि मैंने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किया था. इसे भारत-पाकिस्तान दोनों ने मान भी लिया था. मैं आज़ाद रहना चाहता था, इसीलिए यह एग्रीमेंट किया था.

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़

कश्मीर में पिछले पांच महीने से जारी हड़ताल का उदाहरण शायद ही इतिहास में कहीं मिले. इस हड़ताल के कारण पब्लिक व प्राइवेट इंटरप्राइज़ेज़, ट्रांसपोर्ट, शैक्षणिक संस्थान, प्राइमरी क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब बंद हैं. पूरा जीवन अस्त-व्यस्त है. हालांकि क़रीब एक महीने से यहां पत्थरबाज़ी नहीं हुई है. लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर और किरण रिजीजू इसे नोटबंदी से जोड़कर देखते हैं. इनका कहना है कि नोटबंदी के कारण हवाला का पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए पत्थरबाज़ी बंद हो गई है. यह बिल्कुल ग़लत है, क्योंकि हुर्रियत की लीडरशिप ने और दूसरे लोगों ने भी पत्थरबाज़ी बंद करने की बात कही थी. इन दोनों मंत्रियों को कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है. यहां के लोग भी हड़ताल को लेकर अन्दर से ख़ुश नहीं हैं. हुर्रियत के तीनों नेताओं, गिलानी साहब, मीरवाइज़ और यासीन मलिक ने एक बयान दिया कि हमें चिंता है, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हमारा प्रतिरोधी आन्दोलन जारी रहना चाहिए. लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद यह हड़ताल ख़त्म हो जाए. क्योंकि हुर्रियत भी सोचेगी कि यह हड़ताल लंबी चली है और इस कारण से कश्मीर के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है, लेकिन कश्मीर का संघर्ष जारी रहेगा. लेकिन इसका क्या रूप होगा? क्या यह लोकतांत्रिक तरीक़े से होगा? अगर मोदी जी का ख्याल है कि वे डेवलपमेंट का नाम लेकर समस्या का हल कर लेंगे तो यह उनकी ग़लत धारणा है. कश्मीर की समस्या को राजनीतिक समस्या समझकर हल करना पड़ेगा. यह भारत की मजबूरी है कि पाकिस्तान इस विवाद में शामिल है. जो लोग आंख बंद कर कहते हैं कि पाकिस्तान का इसमें क्या हक़ है? उनको न तो कश्मीर के इतिहास का ज्ञान है और न इस विवाद की जानकारी. कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में शामिल है. इस विवाद को भारत ही संयुक्त राष्ट्र में ले गया था. इस विवाद में तीन पक्ष हैं, कश्मीर के लोग, भारत और पाकिस्तान. भारत अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को यह बताने में सफल रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवाद के कारण और वहां के कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स के कारण भारत को तकलीफ़ है.

नेहरू की नीयत ख़राब नहीं थी

कश्मीर (मैं कश्मीर कहता हूं, जम्मू और लद्दाख का नाम जानबूझकर नहीं लेता), मुस्लिम बहुलता वाला राज्य है. जब 1947 में कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ, उस समय यहां 98 प्रतिशत मुसलमान थे. कश्मीर के लोगों ने जान-बूझकर एक धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ विलय किया. पाकिस्तान ने आदिवासी लोगों को यहां भेजकर यलग़ार की थी. शेख़ अब्दुल्ला सोच ही रहे थे कि हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ भी बात करनी पड़े, उससे पहले ही 20-22 अक्टूबर को यलग़ार कर दी. इससे और ख़टास पैदा हो गई. यहां के लोग शेख़ अब्दुल्ला के साथ रहे. इन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ एक शर्तिया विलय किया. शर्तें तो पहले महाराजा हरि सिंह ने रखी थीं, क्योंकि इन्होंने शिकायत की (विलय के दस्तावेज़ में यह है) कि मैंने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किया था. इसे भारत-पाकिस्तान दोनों ने मान भी लिया था. मैं आज़ाद रहना चाहता था, इसीलिए यह एग्रीमेंट किया था. बहरहाल, अब पाकिस्तान ने चढ़ाई की है, सेना की मदद दे दो. उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि संचार, रक्षा और विदेश मामले आप फिलहाल ले लीजिए और सेना भेज दीजिए. शेख़ साहब ने इनका नैतिक समर्थन किया. इस नैतिक समर्थन में सबसे बड़ी सफलता शेख़ साहब की हुई थी (इनकी अपनी पार्टी भी नहीं जानती होगी यह). जब दिल्ली में इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने नेहरू को कहा कि महाराजा हरि सिंह ने जो किया है, यह ठीक है. लेकिन जब माउंटबेटन ने स्वीकार किया, तो महाराजा को चिट्ठी लिखी कि हम जनमत संग्रह करेंगे. शेख़ साहब ने पहली फ़ुर्सत में जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया कि आप मेरे लोगों के सामने यह कहिए. 13 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू यहां आए और यहां से बारामूला गए. वापसी में लाल चौक में बहुत बड़ा जलसा हुआ. नेहरू कुर्सी के बजाय टेबल पर चढ़ गये. इनके साथ इंदिरा गांधी और रफ़ी अहमद किदवई भी थे. वहां नेहरू ने कहा कि जनमत संग्रह होगा और अगर कश्मीर के लोग (यह लिखित में है) हमारे ख़िलाफ़ भी वोट दे देंगे तो हम स्वीकार करेंगे. फिर धीरे-धीरे नेहरू ने जनमत से इंकार किया. इसके अंतरराष्ट्रीय कारण हैं. लेकिन इसकी तफ्सील में जाने की ज़रूरत नहीं.

शेख़ अब्दुल्ला ने सोच-समझकर कॉन्सटीट्यूएंट असेंबली को बता दिया था कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने कहा था कि आज़ादी असंभव है. हम पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद दो राष्ट्रीय विचारधाराओं पर आधारित है. दो राष्ट्रीय विचारधाराओं को शेख़ साहब ने युवावस्था के दिनों में ही मोहम्मद अली जिन्ना के सामने ख़ारिज कर दिया था. इनका कहना था कि हमारे साथ जम्मू के हिन्दू भी हैं, लद्दाख के बौद्ध भी हैं, हमारा संयुक्त प्लेटफॉर्म है और मेरी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस है. हम इन दो राष्ट्रीय विचारधाराओं को स्वीकार नहीं कर सकते. शेख़ साहब ने एक बड़ी अक्लमंदी की, उन्होंने सोचा कि महाराजा हरि सिंह के तीन सब्जेक्ट विदेशी मामले, रक्षा और संचार से थोड़ी समस्या होगी, लेकिन असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा होना चाहिए, चुनाव आयोग का दायरा होना चाहिए. इसलिए कॉन्सटीट्यूएंट असेंबली में नेशनल कांफ्रेंस से कहा कि हम दिल्ली से यह एग्रीमेंट करने वाले हैं कि इन चार सब्जेक्ट्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल फ्लैग के साथ हमारा झंडा भी साथ रहे और हमारा कांस्टीट्यूशन रहे. कश्मीर की गृह संप्रभुता को सफलता के रूप में प्रस्तुत किया. जब यह मसौदा मंज़ूर हुआ, तो सभी सदस्य नारे लगाते हुए शेख़ साहब के घर तक गये, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जो लोकसभा में भाषण दिया, इसमें लफ्फाज़ी थी और लोकसभा के रिकॉर्ड में एग्रीमेंट को नहीं रखा गया. यह बात मेरे अलावा भारत में कोई नहीं

आज़ादी का आंदोलन कश्मीरियों ने अलग से लड़ा था. यहां कांग्रेस पार्टी नहीं थी. नेशनल कांफ्रेंस ने डोगरा सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी. लगभग चार सौ वर्षों की गुलामी की ज़िन्दगी में कश्मीरियों ने डोगरा, मुग़लों, पठानों और सिखों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी. इस बात का उल्लेख मौलाना सईद ने अपनी किताब में किया है. कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू की नीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन वह पराजित हो गये थे. संसद के अन्दर और बाहर इन पर हिन्दू सांप्रदायिकता का दबाव था. लिहाज़ा उन्होंने संसद के अन्दर और बाहर कहा कि यह एक अस्थायी क्लॉज है और आर्टिकल 370 को बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा.

बताएगा, केवल मेरे पास इसकी ऑथेंटिक कॉपी है. संसद हैरान हो गई, जब 1995 में मैंने इसकी कॉपी मांगी तो. शेख़ साहब खुले दिल के थे, इन्होंने लोगों से कहा कि यही मुझसे हो सका. लिहाज़ा दिल्ली की मेहरबानी से ऑटोनोमी को कम करते रहे. इसमें जवाहरलाल नेहरू की नीयत ख़राब नहीं थी. लेकिन हिन्दू महासभा और छोटे दिमाग के लोगों ने भारत को भी परेशानी में डाल दिया और पाकिस्तान को भी परेशानी में डाल दिया. कश्मीर के लोगों को तो मुसीबत है ही. जिस ज़माने में शेख़ साहब को शाबाशी देनी चाहिए थी, उस ज़माने में श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और कश्मीर में प्रजा परिषद ने इनको दुश्मन की तरह पेश किया. यहां तक कि पूर्व आईबी चीफ़ मलिक ने अपनी किताब में लिखा है कि सरदार पटेल ने इनसे कहा कि शेख़ अब्दुल्ला हिन्दुओं के दुश्मन हैं और नेहरू को इन्हें लेकर भ्रम है.

आज़ादी का आंदोलन कश्मीरियों ने अलग से लड़ा था. यहां कांग्रेस पार्टी नहीं थी. नेशनल कांफ्रेंस ने डोगरा सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी. लगभग चार सौ वर्षों की गुलामी की जिन्दगी में कश्मीरियों ने डोगरा के ख़िलाफ़, मुग़लों के ख़िलाफ़, पठानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी. इस बात का उल्लेख मौलाना सईद ने अपनी किताब में किया है. कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू की नीयत ख़राब नहीं थी, लेकिन वह पराजित हो गए थे. संसद के अन्दर और बाहर इन पर हिन्दू सांप्रदायिकता का दबाव था. लिहाज़ा इन्होंने संसद के अन्दर और बाहर कहा कि यह एक अस्थायी क्लॉज है और आर्टिकल 370 को बाद में ख़त्म कर दिया जाएगा. फिर इस लड़ाई में एक ऐसी मंज़िल आई जब जवाहरलाल नेहरू की मंशा के अनुसार शेख़ साहब को गिरफ्तार करके इनकी सरकार को निष्कासित कर दिया गया. अगर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने शेख़ साहब का साथ दिया होता, तो शायद केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती थी. शेख़ साहब ने विलय को, जो नैतिक समर्थन दिया था, वह अस्थायी था, जनमत संग्रह के साथ. लेकिन नेहरू की नीयत बदल गई. भले भाजपा माने या न माने, लेकिन सच तो यह है कि नेहरू की टक्कर का भारत में कोई लीडर न पैदा हुआ है और न होगा. वह मॉडर्न, साफ़-सुथरे और धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण कर रहे थे, लेकिन छोटे दिमाग़ के लोगों ने नेहरू की राह में मुश्किलें पैदा कर दीं और इसलिए नेहरू कश्मीर के साथ इंसाफ़ नहीं कर सके और लंबे अरसे के लिए शेख़ साहब को जेल जाना पड़ा और अपने लोगों ने उनके साथ गद्दारी की.

ज़ख्मी दिल के लिए सड़क, बिजली मायने नहीं रखती

मैं शायद पहला शख़्स हूं, जिसने दिल्ली को इंकार किया कि मैं फ़ारूक़ साहब के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं रह सकता. वर्ना यही देखा कि शेख़ साहब थे तो बेग साहब को, बख्शी साहब को डोरे डालते रहे. फिर बख्शी साहब आये तो दूसरे लोगों को डोरे डाले. फिर सादिक़ साहब आ गये तो सादिक़ साहब को भी डोरे डालते रहे. कहने का मतलब यह है कि इसमें दिल्ली सफल हो गई. मैंने फ़ारूक़ अब्दुल्ला का और नेशनल कांफ्रेंस का संपूर्ण समर्थन किया. एक बार अरुण नेहरू ने मुझसे कहा कि आपका कोई इंटरेस्ट है, तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं. हमने कह दिया कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. फ़ारूक़ अब्दुल्ला के साथ आपके जो भी मतभेद हैं, इन्हें दूर कीजिए. भाजपा एक साम्प्रदायिक पार्टी है. भाजपा के साथ जाने के लिए फ़ारूक़ अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने 100 बार माफी मांगी और कहा कि यह पार्टी ख़राब है. हालांकि फ़ारूक़ अब्दुल्ला कहते रहे कि इन्होंने ऐसा पार्टी के लिए किया, लेकिन पार्टी के लिए नहीं, बल्कि उमर साहब की अकोमोडेशन के लिए किया. आडवाणी जी ने तो यह अपनी किताब में भी लिखा.

दरअसल शेख़ साहब के साथ काफ़ी ग़लत बर्ताव किया गया और इस कारण से भारत को काफ़ी नुक़सान पहुंचा. 9 अगस्त 1953 को लेकर सईद मलिक, जो बड़े पत्रकार हैं, ने एक लेख लिखा, दि डे इंडिया लॉस्ट कश्मीर. मैंने इनसे पूछा कि आप तो वैचारिक रूप से मुफ्ती साहब के साथ थे. फिर आपने यह कैसे लिखा? इन्होंने कहा कि बहुत लिखा, मैंने पढ़ा भी. मेरे ज़हन ने आवाज़ दी कि आख़िर कश्मीर को क्या हो गया है. 9 अगस्त 1953 के बारे में आज के बच्चों ने अपने बाप और दादा से सुना होगा कि शेख़ अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया. यह बात यहां के लोगों की ज़हनियत में रची बसी है. बाद में 1975 में शेख़ साहब छोटी कुर्सी (मुख्यमंत्री) पर बैठे. इस कारण से लोग नाराज़ हो गये. शेख़ अब्दुल्ला का जब निधन हुआ, तो वह एक लोकप्रिय नेता नहीं थे. मैं समझता हूं कि इनको 75 में चीफ़ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था. इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुलाम अहमद ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख़ साहब को उनकी फैमिली ने, दोस्तों ने और ख़ुद दिल्ली ने मजबूर किया और 75 का समझौता हो गया. वह समझौता कश्मीरियों को मंज़ूर नहीं था और इसके बाद तो केंद्र ने काफ़ी ग़लतियां कीं. जिस राष्ट्र की मानसिकता को ज़ख्म लगता है, उसके लिए सड़कें बनाना, बिजली के खंबे लगाना कोई मायने नहीं रखता. क्या मोदी कश्मीर में बख्शी गुलाम मोहम्मद से अधिक डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं. यहां तक कि शेख़ साहब अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बख्शी एक महान निर्माता थे. स्टेट की बात करते थे, लेकिन बख्शी साहब का देहांत हो गया, तो इनको क़ब्र के लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी. ख़ुद बख्शी ख़ानदान के लोग जनाज़े से हट गये थे, लेकिन आम लोगों में से कुछ ने उनके काम को याद किया और मित्रतों के बाद उनको दफ़न किया गया. तो बख्शी को इस्तेमाल किया गया और बाद में उन्हें अविश्वसनीय बनाया गया? दरअसल सादिक़ साहब ने और बख्शी साहब ने दिल्ली एग्रीमेंट को कमज़ोर करने, ऑटोनोमी को छीनने में मदद की.

गेंद भारतीय प्रधानमंत्री के पाले में है

आज मैं कहता हूं कि कश्मीर का भारत के साथ उस समय तक विलय नहीं हो सकता, जब तक संप्रभुता बहाल नहीं होती. कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहता. कश्मीर को यह भी मालूम है कि आज़ादी असंभव है, लेकिन जब तक ऑटोनोमी बहाल नहीं होती, तब तक कश्मीर भारत के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता. 2007 में जब मैं मिनिस्टर था तो सरदार अब्दुल कय्यूम से दिल्ली में मेरी मुलाक़ात हुई. उन्होंने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान में से जम्मू कश्मीर राज्य की सरहदें कोई बदल नहीं सकता. क्योंकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति है. अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है. लेकिन बॉर्डर बदला नहीं जा सकता, तो कम से कम बॉर्डर को ग़ैरज़रूरी तो बनाया ही जा सकता है. जो पांच कश्मीर हैं, गिलगित, बलतिस्तान, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के लिए वीज़ा फ्री कीजिए. वीज़ा के लिए कुछ मैकनिज्म हो और इसके लिए मुशर्रफ़ व मनमोहन फॉर्मूले पर अमल हो.

कश्मीर भारत के साथ रहेगा, क्योंकि कश्मीर ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ विलय किया था. लेकिन अगर आप यहां हिन्दू राष्ट्र चाहते हैं, तो प्रत्येक कश्मीरी इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है. आपको कश्मीर को अपने साथ रखने के लिए कोई फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा. यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसने दो राष्ट्रीय विचारधाराओं को ख़ारिज कर दिया है. अब आप किसी भी राष्ट्र को ताक़त के दम पर अपने साथ नहीं रख सकते हैं. आप पैलेट या वैलेट्स के द्वारा कश्मीर पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकते. आपको हर साल कश्मीर के लोगों के साथ लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा. बिजली सप्लाई कर या सड़क बनवाकर इन्हें ख़ामोश नहीं किया जा सकता. इंसान होने के नाते इनकी ज़रूरत है, लेकिन यहां के लोगों को ताक़त के दम पर ख़ामोश नहीं किया जा सकता. बाद में भी लोगों ने वादे किये. नरसिम्हा राव ने कहा कि स्काई इज द लिमिट, लेकिन सारे वादे झूठे साबित हुए.

भारतीय प्रधानमंत्री मोदी हों या कोई और, अगर वह कश्मीर के साथ इंसाफ़ करेगा तो कश्मीर भारत का हिस्सा हो जायेगा. मैं समझता हूं कि दिल्ली एग्रीमेंट, इसके लिए सबसे दुरुस्त फॉर्मूला है. लिहाज़ा गेंद भारतीय प्रधानमंत्री के पाले में है, लेकिन वह यह मौक़ा चूक जाएंगे. पिछले चार महीने के दौरान जो पूरा कारोबार बन्द रहा, इससे मैं भी ख़ुश नहीं हूं. मुझे लगता है कि लोगों को तकलीफ़ दिये बिना हुर्रियत को अपनी तहरीक जारी रखने के लिए एक नया तरीक़ा अपनाना पड़ेगा. दरअसल हुर्रियत इस समय कश्मीर के गुस्से का प्रतिनिधित्व कर रही है. कोई मेनस्ट्रीम पार्टी इस समय फंक्शन नहीं कर रही है. एक भारतीय कश्मीरी राष्ट्रवादी के नाते मैं समझता हूं कि भारतीय लीडरशिप यह समझेगी कि इस समस्या के हल के लिए कुछ करना चाहिए.■

– लेखक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं.

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आग लगा कर पानी का इंतज़ाम नहीं किया जाता

नोटबंदी के 50 दिन का समय 30 दिसंबर को समाप्त हो गया. आजतक इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कैश की किल्लत कुछ कम हो गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कैश की सख्त कमी है. ये आसानी से कहा जा सकता है कि यह क़दम उठाते हुए जिन नतीजों की उम्मीद की गई होगी, वो उससे बहुत कम हासिल कर पाएंगे. यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो नतीजे निकले, वह लोगों को हुई परेशानी के मुताबिक़ हैं. आपने 87 प्रतिशत करेंसी को वापस ले लिया, जिसकी वजह से देश का हर एक नागरिक प्रभावित हुआ. अगर एक लाख करोड़ रुपए से कम की राशि सिस्टम से बाहर रहती है और सारा पैसा सिस्टम में आ जाता है तो ब्लैकमनी की बहस बेकार हो जाएगी. लंबी अवधि में जीडीपी ऊपर जाती है या नीचे आती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा.

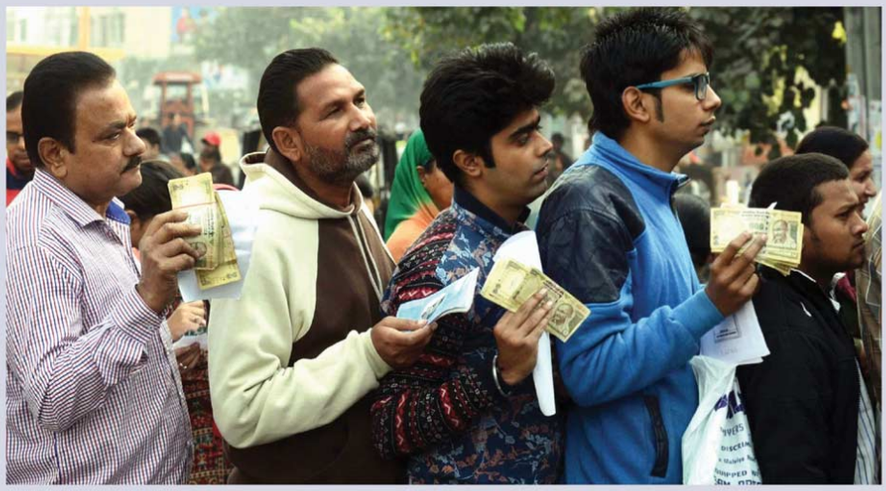

राजनैतिक विमर्श का स्तर नीचे की तरफ़ जा रहा है. प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. लेकिन उनके आरोप-प्रत्यारोप का स्तर बहुत साधारण है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपने आरोपों का खुलासा कर दिया तो भूकंप आ जाएगा. उन्होंने अपने आरोप का ख़ुलासा किया. इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भूकंप की कोई आशंका नहीं है. इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आरोपों को गंभीरता से नहीं लेते हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बेशक चुनाव के लिए पैसे लिए होंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि यह भ्रष्टाचार नहीं है. हर एक राजनीतिक दल औद्योगिक घरानों से पैसे लेता है. आप ये नहीं कह सकते कि हमने पैसे नहीं लिए. अब ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि हमने उनकी कोई मदद नहीं की. लेकिन बदक़िस्मती से पूरा इस्टैब्लिशमेंट, चाहे सरकार, मोदी, बीजेपी या आरएसएस हो, सभी बचकाना और अपरिपक्व व्यवहार कर रहे हैं.

नोटबंदी के 50 दिन का समय 30 दिसंबर को समाप्त हो गया. आजतक इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कैश की किल्लत कुछ कम हो गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कैश की सख्त कमी है. ये आसानी से कहा जा सकता है कि यह कदम उठाते हुए जिन नतीजों की उम्मीद की गई होगी, वो उससे बहुत कम हासिल कर पाएंगे. यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो नतीजे निकले, वह लोगों को हुई परेशानी के मुताबिक़ हैं. आपने 87 प्रतिशत करेंसी को वापस ले लिया, जिसकी वजह से देश का हर एक नागरिक प्रभावित हुआ. अगर एक लाख करोड़ रुपए से कम की राशि सिस्टम से बाहर रहती है और सारा पैसा सिस्टम में आ जाता है तो ब्लैकमनी की बहस बेकार हो जाएगी. लंबी अवधि में जीडीपी ऊपर जाती है या नीचे आती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा. लेकिन ये कहना कि हम ये कदम कैशलेस इकोनॉमी के निर्माण के लिए उठा रहे हैं, ये ऐसा ही है, जैसे पहले आग लगाना और बाद में ये कहना कि हमें इस आग को बुझाने के लिए पानी का बेहतर इंतजाम करना चाहिए. कैशलेस या लेसकैश समाज का लक्ष्य रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी. आपको लोगों को तैयार करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा.

मुझे ख़ुशी होगी, यदि वे ये क़दम अभी उठाना शुरू कर दें. लेकिन इसके नतीजे के लिए दो-तीन साल तक इंतज़ार करना होगा. कई गांव ऐसे हैं, जहां न तो एटीएम है, न बैंक. ग्रामीणों को बैंक तक जाने के लिए 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी होती है. आप ऐसे गांव में कैशलेस सिस्टम स्थापित नहीं कर सकते. शहरी क्षेत्रों में, जहां लोग प्लास्टिक कार्ड, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, इसे लागू किया जा सकता है. लेकिन यहां लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं. बहरहाल, सरकार कैशलेस सिस्टम के लिए आगे बढ़ सकती है और इसको जितना मुमकिन हो, कैशलेस बनाने की कोशिश कर सकती है.

अब राजनीति के दूसरे मुद्दों की तरफ़ लौटते हैं. अभी जो भाव प्रकट किए जा रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि हालिया भाषणबाज़ी, यूपी और पंजाब चुनाव के लिए नहीं, बल्कि देश में मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा करते हैं. बहरहाल ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है. अगर वे सोचते हैं कि उनके उठाए गए कदम लोकप्रिय हैं, तो वे देश को चौंकाते हुए मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर सकते हैं. लेकिन यूपी से आनेवाली रिपोर्ट उनके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है. नोटबंदी के बाद वे अपने लोकसभा क्षेत्र में पहली बार गए. उनके प्रति वहां लोगों का उत्साह पहले जैसा नहीं देखा. उनकी सभा में उतनी भीड़ नहीं आई. हालांकि ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसी पार्टी है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो पैसे के बल पर भीड़ इकट्ठी कर सकती है. लेकिन कुछ महीने पहले जिस तरह का उत्साह दिखता था, वो अब नहीं दिख रहा है.

आठ नवंबर से पहले भले आप मोदी के समर्थन में हों या उनके विरोध में, कोई भी उनका मज़ाक़ नहीं उड़ा रहा था. लेकिन आठ नवंबर के बाद लोग उनका मज़ाक़ उड़ाने लगे. उनका व्यक्तिगत ग्राफ निश्चित रूप से नीचे गया है. बेशक राजनीति में ऐसा होता है. लेकिन उनके नोटबंदी का फैसला, जिसपर मुझे लगता है कि वे रोजाना विचार करते होंगे कि यह सही है या गलत, लेकिन फिलहाल इसपर कुछ भी नहीं किया जा सकता है. मेरे विचार में तीस दिसंबर के बाद भी पर्याप्त संख्या में नोट नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो उन्हें पांच सौ के नोट को फिर से रेगुलराइज करना चाहिए. जितना पैसा आना था, वो सब आ चुका है. इसमें तर्क ये है कि अब एक हज़ार का नोट दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पांच सौ के नोट को लाकर तनाव की स्थिति को तत्काल कम किया जा सकता है. इसके दीर्घकालिक नतीजे क्या निकलते हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा.

प्रधानमंत्री बार-बार यह कह रहे हैं कि विपक्ष पाकिस्तान की मदद कर रहा है. ये समझ से बाहर है कि विपक्ष कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा है. दरअसल, सरकार कश्मीर में पाकिस्तान की सहायता कर रही है. अपने लोगों को हिरासत में लेकर आप जनमत संग्रह और अलगाववादियों की बात कर उनका पक्ष मज़बूत कर रहे हैं. विपक्ष पाकिस्तान की मदद कैसे कर सकता है? पाकिस्तान भी यही बात कह सकता है. नोटबंदी की आलोचना हर कोई कर रहा है. पूरा विपक्ष नोटबंदी की आलोचना कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी एक हो गए हैं. जब चुनाव आएंगे तो अपने-अपने तौर पर चुनाव लड़ेंगे. संसद का सत्र बर्बाद हो गया. इसे बचाया जा सकता था, अगर सरकार दूसरे पक्ष के लोगों से बात कर मेल-मिलाप की कोशिश करती. लेकिन ये सरकार की मंशा नहीं है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें आई थीं. सरकार ने उन्हें नेता विपक्ष का पद नहीं दिया था. उनके व्यवहार से ये लग रहा था कि संसद अगले 50 सालों के लिए चुनी गई है और चुनाव नहीं होंगे. दरअसल जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं. मुझे मालूम नहीं है कि उनके सलाहकार कौन हैं, लेकिन जितनी जल्दी वो राजनीति के तर्क को समझ लेंगे, उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

जनता का ग़ुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है

शुजात बुखारी

अगर आप एक शांतिपूर्ण राजनीतिक संघर्ष भी करते हैं, तो आपको खदेड़ने और दबाने के लिए ताक़त का बेइंतेहा इस्तेमाल किया जाता है. पूरे राज्य को एक विशेष स्थान प्राप्त है, इसके बावजूद राज्य और केंद्र सरकारों की ग़लत कार्यशैली के कारण पूरा राज्य एक नरक में बदल चुका है. हालांकि, सरकार इस बयान को ख़ारिज कर सकती है, इसके बावजूद कश्मीरियों के पक्ष में आवाज़ें बुलन्द होनी शुरू हो गई हैं. लिहाज़ा सिन्हा और उनके दल को कश्मीरी जनता को अतीत की तरह निराश नहीं करना चाहिए, जैसा कि अतीत में यहां केंद्र और राज्य सरकारों ने किया है. इसके बावजूद नई दिल्ली और श्रीनगर को भी इस बदलते हालात को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

कश्मीर में 5 महीनों से जारी विरोध-प्रदर्शन, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और दर्जनों ने अपनी आंखें गंवाई, दिल्ली में स्थापित भाजतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रभावित करने में नाकाम रहा और ये भी बताने में नाकाम रहा कि कश्मीर में किसी प्रकार की राजनीतिक अविश्वसनीयता या अफरा-तफरी का माहौल है. इसके बजाय कश्मीरी जनता की यह कहकर तौहीन की जा रही है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वह एक मानसिक बेचैनी है. इसके लिए आबादी का वह पांच प्रतिशत हिस्सा ज़िम्मेदार है, जिसका संरक्षण पाकिस्तान कर रहा है. इसके साथ ही नई दिल्ली की वह नीति और भी स्पष्ट हो गई, जो उसने कश्मीर समस्या के हवाले से धारण कर रखी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज़ाहिर तौर पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सभी नीतियों के उस्ताद हैं. उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. लेकिन कश्मीर के मामले में वे या तो ज़मीनी परिस्थितियों का मुक़ाबला करने और इसे समझने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं या फिर वे सुरक्षा विशेषज्ञों, सलाहकारों व नौकरशाही की राय से बाहर क़दम रखने के लिए तैयार नहीं हैं. लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाए, तो भी ऐसा महसूस होता है कि कश्मीर समस्या को लेकर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच गहरे मतभेद हैं. प्रधानमंत्री कश्मीर समस्या का कोई आउट आफ द बॉक्स हल तलाश करने के पक्षधर हैं, वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय का नज़रिया है कि कश्मीरियों को अधिक से अधिक थकाया जाए, ताकि वे मजबूर होकर ख़ुद विरोध-प्रदर्शन से पीछे हट जाएं.

यह सच है कि विरोध-प्रदर्शन कुछ कम हुआ है या इसमें पहले जैसा दम-ख़म नहीं रहा है. निरंतर विरोध-प्रदर्शन और हड़तालों से जनता परेशान हो गई थी, जिस कारण हुर्रियत नेतृत्व को हड़ताल वापस लेनी पड़ी. यह सच्चाई अपनी जगह कायम है कि जनता का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है और न ही उनके आक्रोश में कोई कमी आई है. जनता ज़ाहिर तौर पर रोजमर्रा के हालात की तरफ लौट रही है, लेकिन यह भी सच है कि वह किसी बात को भूली नहीं है. यह लावा अभी अंदर ही अंदर सुलग रहा है, जो किसी भी समय फूटकर बाहर निकल सकता है. सरकार की ओर से कश्मीर के हालात की अनदेखी कश्मीर को वर्ष 2017 में भी चैन से नहीं रहने देगा. इस राजनीतिक तिकड़म से उन लोगों के दृष्टिकोण को बल मिलता है, जो कड़ा रुख़ रखते हैं. इसके साथ ही दिल्ली वालों की नीयत का पता भी चलता है, साथ ही यहां एक ख़ुशगवार माहौल बनाने के मकसद को दस क़दम पीछे धकेल देता है.

हालांकि, विकास की समस्या अलग है. पिछले एक दशक के दौरान यहां पर्यटन के क्षेत्र में काफी तेज़ी आई है. पुल बने हैं. सड़कें और अस्पताल भी नए बने होंगे लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर जम्मू-कश्मीर काफ़ी पीछे रह गया है. इस दौरान न केवल जनता के आक्रोश में इज़ाफ़ा हुआ है, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता को भी बड़ा नुक़सान पहुंचा है. इसका प्रत्यक्ष रूप से फायदा अलगाववादियों को हो रहा है. हालांकि, आज इस जगह पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है तो अतीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी.

इधर भारतीय जनमत कश्मीरियों के ख़िलाफ़ नज़र आती है, इसके बावजूद सिविल सोसायटी के स्तर पर कई कोशिशें हुई हैं. उन्होंने न केवल कश्मीरियों के राजनीतिक संघर्ष को माना है, बल्कि उनके दुख-दर्द और परेशानियों को भी खुले तौर पर स्वीकार किया है. भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कुछ जाने-माने चेहरों, जिनमें वजाहत हबीबुल्लाह, भारत भूषण, पूर्व वायस एयर चीफ़ मार्शल (सेवानिवृत्त) कपिल काक और श्रीमती सुशोबा बर्वे भी शामिल हैं, उन्होंने कश्मीर को लेकर एक मुहिम का आगाज़ किया. यशवंत सिन्हा उस व्यावहारिक शांति के सूत्रधार भी माने जाते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 के बाद शुरू हुई थी. सिन्हा ख़ुद को एक आम शहरी कहते हैं, हालांकि उन्होंने भाजपा के साथ अपने संबंध नहीं तोड़े हैं. इस समूह ने हालांकि अभी तक कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, लेकिन वे यथास्थिति को तोड़ने में किसी हद तक सफल हुए हैं. हालांकि मीरवाइज़, उमर फारूक़, सैयद अली गिलानी और मोहम्मद यासीन मलिक ने अगस्त में दिल्ली से आने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से बात करने से इंकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने सिन्हा के नेतृत्व वाले दल का स्वागत किया. सिन्हा और उनके दल ने यह बात कई बार दो-हराई है कि वे किसी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और न ही वे कश्मीरियों को कुछ दे सकते हैं, लेकिन वे कश्मीरियों के संघर्ष को समझकर भारतीय जनमत के एक बड़े तबके को इससे अवगत कराना चाहते हैं. इस दल के अभी तक दो दौरे हो चुके हैं और इन्होंने दक्षिण व उत्तरी कश्मीर में लोगों के कई दलों और समूहों से भेंट की है. हालांकि वे प्रतिबद्ध नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने दौरे और कोशिशें जारी रखकर जनता के बीच संपर्क बनाए रखने का संकल्प स्पष्ट किया है. उनके अलावा एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मोरारका और प्रसिद्ध पत्रकार संतोष भारतीय, जिनके मोदी के नाम खुले ख़त ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था, ने भी हाल में कश्मीर की यात्रा कर कई राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के साथ मुलाक़ातें की हैं. हालांकि संतोष भारतीय के ख़त ने काफ़ी काम किया, इसके बावजूद वे नरेन्द्र मोदी सरकार को अपनी जगह से हिलाने में नाकाम रहे.

सिन्हा और उनकी टीम की कोशिशों को लेकर एक अवामी तबके में निराशा भी पाई जाती है, इसके पर्याप्त कारण भी मौजूद हैं. विशेष रूप से अतीत के हालात. इस प्रकार की कोशिशों और नेताओं के साथ की गई वार्ता और एक ऐसी सरकार को मद्देनज़र रखकर, जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, निराशा का होना कोई अजीब बात नहीं है. इस कारण संदेह बढ़ सकता है क्योंकि भारतीय नेतृत्व की ओर से कश्मीर और कश्मीरियों को नज़रअंदाज़ करने का एक लंबा इतिहास रहा है. इसके बावजूद जनता अभी तक वार्ता में विश्वास रखती है. संयुक्त प्रतिरोधी नेतृत्व, सिविल सोसायटी, बार एसोसिएशन, मीडिया और समाज के सभी तबकों ने नई दिल्ली के किसी भी व्यक्ति या समूह की ओर से शुरू की गई कोशिशों का समर्थन कर अपनी विश्वसनीयता को ही बढ़ाया है. सिन्हा के साथ एक भेंट के दौरान उनसे मिलने वालों ने यह तक कह दिया कि सिन्हा उनके और भारतीय जनमत के बीच एक दूत बनकर काम करें, जिससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि इतना सबकुछ होने के बावजूद कश्मीरी जनता ने वार्ता को लेकर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है. वह अच्छी तरह से समझती है कि अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वार्ता ही एकमात्र रास्ता है. सिन्हा और उनकी पार्टी शायद किसी अंतिम निष्कर्ष पर न पहुंच पाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वे जनता को निराशा के दलदल से बाहर निकालने में ज़रूर सफल हो जाएंगे, जो वार्ता और इस प्रकार की दूसरी कोशिशों पर भरोसा खो चुके थे. इस सिलसिले ने सरकार को सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है. इसके उलट कि वह इसे मानने के लिए तैयार हैं या नहीं. इसके अलावा जिस प्रकार से सिन्हा ने कश्मीर के हालात को पेश किया है, उससे कश्मीरी जनता के नज़रिए को काफ़ी वज़न और बल मिला है. उनके अपने शब्दों में कश्मीर में आम लोगों का कोई अधिकार नहीं हैं और न ही कहीं लोकतंत्र का नामोनिशान है. अगर आप एक शांतिपूर्ण राजनीतिक संघर्ष भी करते हैं, तो आपको खदेड़ने और दबाने के लिए ताक़त का बेइंतेहा इस्तेमाल किया जाता है. पूरे राज्य को एक विशेष स्थान प्राप्त है, इसके बावजूद राज्य और केंद्र सरकारों की ग़लत कार्यशैली के कारण पूरा राज्य एक नरक में बदल चुका है. हालांकि, सरकार इस बयान को ख़ारिज कर सकती है, इसके बावजूद कश्मीरियों के पक्ष में आवाज़ें बुलन्द होनी शुरू हो गई हैं. लिहाज़ा सिन्हा और उनके दल को कश्मीरी जनता को अतीत की तरह निराश नहीं करना चाहिए, जैसा कि अतीत में यहां केंद्र और राज्य सरकारों ने किया है. इसके बावजूद नई दिल्ली और श्रीनगर को भी इस बदलते हालात को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. उन्हें इस परिदृश्य में जनता तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, बशर्ते वो साल 2016 को एक अतीत के रूप में देखना चाहते हैं. हालांकि घावों को भरने में काफ़ी वक़्त लग सकता है, इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी भी दिल्ली पर ही आती है.■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

नोटबंदी का फ़ैसला अर्थव्यवस्था को कई साल पीछे ले गया है

भारत में सरकार जैसे काम कर रही है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए. जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी, उसके बाद पूरे देश में उनके समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी ने एक हवा बना दी थी कि सारी दुनिया में मोदी ने भारत का झंडा बुलंद कर दिया है. देश सारी दुनिया के सामने पहली बार सर उठाकर खड़ा हुआ है. इसका मतलब विदेशी मीडिया ने हमारी इज़्ज़त बढ़ाने के जो कसीदे पढ़े, उन पर भारत को बहुत अभिमान था. ये अलग बात है कि विदेशी मीडिया का नाम जब भारत में लिया जा रहा था, उन दिनों जब हम इसकी सच्चाई तलाशते थे, तो विदेशों के अख़बार वो कसीदे पढ़ते नहीं दिखायी दिए, जिसका दावा हिन्दुस्तान के मीडिया में हो रहा था या जिसका दावा ख़ुद मीडिया कर रहा था. पार्टी अपना गुणगान करे, यह समझ में आता है, लेकिन भारत का मीडिया शुरू की यात्राओं में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को कवर कर रहा था और जिस तरह से यहां लाइव प्रोग्राम दिखाए जा रहे थे, उससे ये छाप पड़ी कि भारत का सिर विदेशों में गर्व से ऊंचा हो गया है.

इसके बाद दो साल बीत गए. प्रधानमंत्री लगातार विदेशों में रहे. ये कहावत आम हो गई कि वो हिन्दुस्तान में दौरा करने आते हैं, उसके बाद फिर विदेश चले जाते हैं. ये जुमला उनके विरोधियों का उड़ाया हो सकता है, पर अफसोस की बात यह है कि इसमें सच्चाई नज़र आती थी. उन दिनों प्रधानमंत्री के पास देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए समय नहीं था. वे जो घोषणाएं करते थे, उन पर कितना अमल हो रहा है इसका भी आकलन करने के लिए शायद उनके पास वक्त नहीं था. आज जब हम उनकी समस्त घोषणाओं को देखते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि किसमें कितना काम हुआ है. सरकार पिछले ढाई साल में प्रधानमंत्री द्वारा की गयी घोषणाओं पर अपना कोई रिपोर्ट कार्ड सामने नहीं ला पाई है. जब हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों की गतिविधियां देखते हैं, तो वो भी हमें गांव में कहीं घूमते हुए नहीं दिखाई देते हैं. व्यक्तिगत बातचीत में अधिकतर सांसदों का कहना है कि हम गांव में जाकर बताएं क्या, दिखाएं क्या? वे प्रधानमंत्री के बार-बार कहने के बावजूद लोगों के गुस्से से डर कर अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में न गए, न जा पा रहे हैं.

और अब अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडी की बात. मूडी ने भारत सरकार से कहा है कि आपने ढाई साल में ऐसा क्या किया है, जिससे हम आपकी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग सुधार दें. दरअसल मूडी एक ऐसी संस्था है, जो हर देश को एक रैंक देती है. इसी रैंक को आधार बनाकर विदेशी निवेशक उस देश में पैसा लगाते हैं. दरअसल, ये बाज़ार का बनाया एक सिस्टम है. अब तो हम भी बाज़ार के एक हिस्से हैं, इसलिए मूडी की रेटिंग का हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है. भारत सरकार ने मूडी से कहा कि वो भारत की रेटिंग सुधारे, क्योंकि ढाई साल में भारत सरकार ने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं. उन्होंने वो सारे काम गिना दिए, जिनका ज़िक्र प्रधानमंत्री मोदी अपनी घोषणाओं में अक्सर करते रहते हैं. मूडी ने जवाब दिया कि आपने ऐसा क्या किया है, शायद आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से हम आपकी रेटिंग सुधारें. इसके पहले फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी ओर से ये कहा कि नोटबंदी अबतक का सबसे ग़लत और अनैतिक फैसला है. इसमें जनता को परेशानी के समंदर में ढकेल दिया है. इससे पहले जब आठ नवंबर को नोटबंदी लागू हुई थी, उसके एक हफ्ते बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के विकास की दर 7.6 प्रतिशत रहने के अंदाज़े पर आकलन दिया था कि ये दर सिर्फ 7 प्रतिशत रह जाएगी.

विदेशों में दूसरी प्रतिक्रियाओं को हम छोड़ दें. अगर हम इन तीन प्रतिक्रियाओं को देखें तो हमें लगता है कि सरकार के समर्थक इन तीनों एजेंसियों पर भारत विरोधी होने का आरोप लगाएंगे और उन्हें देशद्रोही भी घोषित कर देंगे. उन्हें जो करना हो करें, पर हमें एक आंकड़ा समझ में नहीं आया. 14 लाख 60 हज़ार करोड़ की मुद्रा 1000 और 500 रुपये के रूप में भारत के बाजारों में रिज़र्व बैंक ने डाली थी. 15 दिसंबर के आसपास 15.44 लाख करोड़ रुपये भारत सरकार के रिज़र्व बैंक के पास वापस आ चुके थे. इसके बाद रिज़र्व बैंक ने आंकड़ा देना बंद कर दिया, लेकिन जब हमने पता लगाया तो जानकारी मिली कि ये आंकड़ा 17 लाख करोड़ को छू रहा है.

अब जो बात हमें समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि अगर 14 लाख 60 हजार करोड़ रुपए बाज़ार में थे, तो 17 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास वापस कहां से आ गए. जबकि सरकार ने माना था कि सिर्फ़ चार लाख करोड़ रुपये वापस आएंगे, बाक़ी पैसा वापस नहीं आएगा. जो पैसा वापस नहीं आएगा, वो काला धन होगा या आतंकवादियों के क़ब्ज़े वाला धन होगा. अब कैसे इतनी बड़ी मात्रा में पैसा भारत सरकार के पास वापस आ गया. भारत सरकार ने इसका कोई आकलन नहीं रखा कि जो पैसा उनके पास आ रहा है, वो फेक करेंसी है, ब्लैकमनी है या सही पैसा है. हम भारत सरकार के उस बयान का इंतज़ार कर रहे थे कि वह कहेगी कि नहीं रुपये तो 17 लाख करोड़ ही बाज़ार में थे, जो हमारे पास पूरे आ गए. तब सरकार का वो अंदाज़ा कहां गया कि सिर्फ़ चार लाख करोड़ रुपये हमारे पास वापस आएंगे, बाक़ी ब्लैकमनी के रूप में मिल जाएगा. इसका सीधा मतलब ये है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ये सब काहिल हैं. इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को इतनी चोट पहुंचाई है कि जो पैसा वो चाहे 400 करोड़ हो या चार लाख करोड़ हो, जो फेक करेंसी के रूप में था, उस पैसे को भी हमने असली मानकर चलन में ला दिया और वो पैसा हमने लोगों को वापस कर दिया. हम नहीं पहचान पाए कि हम नकली नोट सरकार के ख़ज़ाने में ले रहे हैं. इसे पकड़ने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की. हम उस पैसे को भी नहीं पकड़ पाए, जो पैसा आतंकवादियों के पास होने का संदेह प्रधानमंत्री द्वारा जताया गया था.

यह बोझ भारत की अर्थव्यवस्था को कई साल पीछे ले गया है. यह बोझ देश के लाखों लोगों की नौकरी समाप्त कर गया है. मोटे अंदाज़ के हिसाब से, अगले दो महीने में एक करोड़ से चार करोड़ के बीच शुद्ध बेरोज़गार भारत के सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देंगे. बड़ी-बड़ी कंपनियों ने हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है. जो खुदरा व्यापार में लोग लगे हुए थे, उन्होंने अपने यहां से दैनिक वेतन पर काम करने वाले लोगों को हटा दिया है. अब हम प्रधानमंत्री द्वारा की गयी घोषणा कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं.

अब सरकार कह रही है या शायद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सारी कोशिश नक़ली नोट या आतंकवादियों को या ब्लैकमनी को ख़त्म करने के लिए नहीं थी, ये कैशलेस इकोनॉमी को शुरू करने की थी. अब देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है. जिस देश में बैंकों की संख्या पूरी न हो, उस देश में कैशलेस इकोनॉमी अवश्य सफल होगी. हमारे देश में मोबाइल पर दूसरे मोबाइल से कॉल करने में तीन मिनट की बातचीत में कम से कम तीन बार कॉल कटती है और उपभोक्ता को तीन गुना पैसा देना होता है. जिस देश में मोबाइल सिस्टम ठीक नहीं है, वहां हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं. क्योंकि उसी रूट से वो मशीन, जो कार्ड स्वाइप करती है, वो मशीन बैंक से जुड़ती है, कनेक्शन नहीं हो पाता है. पैंतालीस-पैंतालीस मिनट लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है. मशीन हैंग हो जाती है, लाइन हैंग हो जाती है. इसका अनुभव और बहुतों को होगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव है. पैंतालीस मिनट तक इंतज़ार करने के बाद मैं पेमेंट नहीं कर पाया और सामान छोड़ कर वापस चला आया.

सरकार का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्षमता में शून्यता के आसपास ही है. इसके बावजूद हमने उन सारी कंपनियों को, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करती हैं, उनकी जेबें ज़बरदस्ती भर दीं. इस समय देश

भारत की जनता का ये सौभाग्य है कि उसे अक्सर ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, ऐसे राजनीतिक दल मिलते हैं, जो उसे सपने दिखाते हैं. भारत की जनता उन सपनों को सच मान लेती है. उनके भाग्य में सिर्फ़ सपना देखना होता है. लेकिन सपना सच होने का फ़ायदा देश के पैसे वालों को मिलता है. सारे क़दम बड़े कॉर्पोरेट, बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपतियों के ख़ज़ाने को भरते हैं. जनता के पास, तो जो उसके पास होता है, वो भी खींच के बड़े पैसे वालों की तिजोरी में चला जाता है. ऐसा शुरू से होता आया है. इस बार तो ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीक़े से हुआ है. ऐसे वैज्ञानिक तरीक़े से हुआ है कि जिसकी जेब से निकल गया, जिसे परेशानी हुई, उसे लग रहा है कि उसकी जेब से कम निकला, उसके पड़ोसी की जेब से ज्यादा निकल गया और वे इसी में ख़ुश हैं. अब 50 दिन बीत चुके हैं.

के नागरिकों पर, वो नागरिक जो टैक्स देते हैं, लगभग 49 प्रतिशत टैक्स देना पड़ जाता है. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वालों को इफेक्टिवली पांच प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है. वो पैसा हम सिर्फ़ इसलिए चुकाते हैं, क्योंकि हम सामान ख़रीद रहे हैं. हम सारे टैक्स देते हैं, इसके बाद भी हम ऊपर से लगभग पांच प्रतिशत ट्रांजेक्शन फीस चुकाते हैं. सरकार कैशलेस इकोनॉमी पर जोर दे रही है. अब सरकार ब्लैकमनी और नकली नोट की बात नहीं कर रही, अब सरकार कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रही है. उस देश में जहां चाहे, जिसकी ग़लती से हो, निरक्षरता की संख्या बहुत ज्यादा है. जहां बैंक व एटीएम नहीं पहुंच पाए, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई, जहां सड़क नहीं है, जहां तारें नहीं हैं, उस देश में हम कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. कैशलेस इकोनॉमी दुनिया के कितने देशों में है, अगर सरकार इसे बताए तो बहुत अच्छा.

पर हम शायद उस सपने में जी रहे हैं कि अब हमारे घरों में कैशलेस इकोनॉमी की वजह से रोजगार बढ़ जाएंगे, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, नौकरियां बढ़ जाएंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी. बिजली, सड़क, संचार के साधन, अस्पताल व स्कूल पहुंच जाएंगे. हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ऐसा हो. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसा होता हुआ भी न दिखे तो.

भारत की जनता का ये सौभाग्य है कि उसे अक्सर ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, ऐसे राजनीतिक दल मिलते हैं, जो उसे सपने दिखाते हैं. भारत की जनता उन सपनों को सच मान लेती है. उनके भाग्य में सिर्फ़ सपना देखना होता है. लेकिन सपना सच होने का फ़ायदा देश के पैसे वालों को मिलता है. सारे क़दम बड़े कॉर्पोरेट, बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपतियों के ख़ज़ाने को भरते हैं. जनता के पास, तो जो उसके पास होता है, वो भी खींच के बड़े पैसे वालों की तिजोरी में चला जाता है. ऐसा शुरू से होता आया है. इस बार तो ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हुआ है. ऐसे वैज्ञानिक तरीक़े से हुआ है कि जिसकी जेब से निकल गया, जिसे परेशानी हुई, उसे लग रहा है कि उसकी जेब से कम निकला, उसके पड़ोसी की जेब से ज्यादा निकल गया और वे इसी में ख़ुश है. अब 50 दिन बीत चुके हैं. इन 50 दिनों के बाद और कितने दिन बीतेंगे पता नहीं. मैं अंत में प्रधानमंत्री की इस घोषणा से पूर्णतया सहमत हूं कि जो लाइन में लगे हुए थे, वो चोर और ब्लैकमनी वाले लोग थे. मैं प्रधानमंत्री की इस घोषणा से भी सहमत हूं कि उन सबके एकांउट में, जिनका जनधन एकांउट खोला, उनकी जांच होनी चाहिए कि उनके पास ये पैसा कहां से आया. मैं प्रधानमंत्री की इस घोषणा से भी सहमत हूं कि ये देश बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है और दुनिया की महाशक्ति बनेगा और कैशलेस इकोनॉमी को हम लागू करेंगे. अब मैं अपने लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मेरे इन विश्वासों को सही साबित करे और भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो यश दे, जिस यश के वो भागी हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

कश्मीर के मामले में भारत-पाकिस्तान दोनों झूठ बोल रहे हैं

अपने ताज पर हिंदुस्तान तीर बरसा रहा है

हिन्दुस्तान हमें अपना ताज कहता है, लेकिन क्या ताज के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? ताज पर आप तीरों की बारिश करेंगे, ख़ून बहाएंगे, मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे? आपने तो यहां डेमोक्रेसी का पूरा चेहरा कुरूप कर दिया. हिन्दुस्तानी हमें पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं, तो वह हमें गाली लगता है. क़रीब 80 लाख लोग सड़कों पर हैं. इतना बड़ा आंदोलन है और पूरी कम्युनिटी को आप कहते हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं. ये हमें कट्टर और उग्रवादी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कश्मीर जैसी टॉलरेंट सोसाइटी कहीं है ही नहीं. पूरा हिंदुस्तान जब जल रहा था, 1947 में या उसके बाद भी जब कम्युनल रायट्स हुए, तब भी यहां शांति थी. कश्मीर की तुलना में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह उग्रवाद तेजी से बढ़ रहा है. भले ही वो इस्लाम के नाम पर हो या हिंदुत्व के नाम पर.

नईम अहमद ख़ान

कमल मोरारका जी के नेतृत्व में कश्मीर आया डेलिगेशन, मेरे ख्याल से पहला डेलिगेशन था, जिन्होंने कश्मीर को सही तरह से जानने का प्रयास किया और कश्मीरियों से भी मुलाक़ात की. संतोष भारतीय जी ने एक मीडिया मैन के रूप में यहां की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाया. वो भी बहुत असरकारक रहा. हिन्दुस्तान में सब लोग ख़राब नहीं हैं. कोई तो है, जो हमारी बात हिंदुस्तानियों तक पहुंचाता है. वहां भी कुछ दर्द-ए-दिल वाले लोग हैं, जो महसूस करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादती हुई है. कभी गृह मंत्री रहे चिदंबरम साहब भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन एक चीज़ उन्होंने कही थी कि कश्मीर प्रॉब्लम हिस्ट्री ऑफ ब्रोकेन प्रॉमिसेज़ है. वाजपेयी जी ने भी कोशिश की थी, 10 लाख फौजों को बॉर्डर पर ला खड़ा किया था. लेकिन कश्मीर का मामला तो और भी उलझ गया. आज इनको हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए. आज 21वीं सदी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक और जंग नहीं कर सकते हैं. जब वो जंग करेंगे तो दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे. दिल्ली में बैठे हमारे आज के हुक्मरान कश्मीर मसले को सुप्रीम कोर्ट में हल करना चाहते हैं, दूसरे तरीक़ों से दूसरी जगहों पर हल करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की सॉवर्निटी को लेकर टिप्पणी की है. इससे पहले जम्मू हाई कोर्ट ने भी इसपर कुछ कहा था. मेरा मानना है ये दोनों कमेंट ग़लत हैं. पॉलिटिकल इश्यूज इस तरह से हल नहीं होते हैं.

70 सालों से हमसे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं

आख़िर कश्मीर की समस्या तो हिंदुस्तान की ही पैदा की हुई है. यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्रिएशन है. यूनाइटेड नेशन्स में तो वो गए. हरियत तो गया नहीं. हिंदुस्तान की संसद और पहले प्रधानमंत्री ने कश्मीर से जो वादा किया था, वो हमें नहीं मिला. हिंदुस्तान ने संविधान के दायरे में कश्मीर को जो स्टेटस दिया था, लीगल और कॉन्स्टीट्यूशनल गारंटी दी थी, वे उससे मुकर गए हैं. 2010 के बाद हिंदुस्तान के कुछ लोग यहां आए, तो हमने उनसे भी कहा कि विश्वास बहाली के लिए एक अच्छी पहल होगी कि हमें जो संवैधानिक गारंटी मिली थी, उसे बहाल किया जाए. पिछले 5-6 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, उसे लेकर दोनों मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने हमें जिस तरह से पेश किया, वो प्वाइंट ऑफ व्यू नहीं है. उसका कारण केवल बुरहान वानी नहीं था. उसने ट्रिगर का काम किया. ख़ुदा न करे, लेकिन अगर गिलानी साहब की भी मृत्यु हो जाती तो यही होता. यह हिंदुस्तान का अकेला मुस्लिम बहुल एरिया है और यहां पर राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कश्मीरी हमेशा सतर्क रहते हैं. हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हमारी पहचान के साथ छेड़छाड़ न हो.

आप आज मुझसे और गिलानी साहब से असहमत हो सकते हैं. लेकिन जो हमारा नौजवान सड़क पर है, आप उससे अगले दस साल बाद बात नहीं कर सकते हैं. वो दिल्ली वालों का चेहरा देखना पसंद नहीं करता है. बुरहान के बाद आंदोलन में जब कश्मीरी बच्चों ने जेसीबी पर चढ़कर कैंपों पर धावा बोला, किसने बचाया उनको? कश्मीर में जो पुलिस वाले आज सलामत नज़र आ रहे हैं और हमारे सीनों पर मूंग दल रहे हैं, उनको किसने बचाया? हमने तो लोगों से अपील की कि ऐसा मत करो. हरियत ने पॉजीटिव रोल अदा किया. अगर हमने जले पर तेल छिड़कने का काम किया होता तब तो हालत कुछ और ही होते. पाकिस्तान ने हमें 1947, 1965 और 1971 में बंदूक़ देना चाहा, हमने नहीं लिया और कश्मीरी आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं. अभी यहां के लोगों के पास मानवीय मूल्य बाक़ी हैं, आंखों का लिहाज बाक़ी है. अभी भी हुरियत चाहता है कि हिंदुस्तान से आने वालों को यहां वेलकम किया जाए, लेकिन आने वाले वर्षों में कोई सुनने को तैयार ही नहीं होगा. अभी हिंदुस्तान से जब पार्लियामेंट्री डेलिगेशन आया तो हम मिलना चाहते थे. लेकिन गिलानी साहब पर इतना दबाव था कि हमें दरवाज़ा बंद करना पड़ा. पब्लिक प्रेशर इतना था कि हम मिल नहीं सके. लोगों में आज हिंदुस्तान के ख़िलाफ उबाल इसलिए है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें हमेशा धोखा दिया है. वे 70 सालों से हमसे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं. एक जमाना था, जो भी सिविल सोसाइटी के हिंदुस्तान में बड़े नाम हैं और जो भी एनजीओ हैं, जो भी अख़बार वाले हैं, 90 के दशक में उनका दूसरा घर कश्मीर हुआ करता था. उन्होंने कहा कि आप आजादी की बात करें, लेकिन पाकिस्तान का नारा ना दें, बंदूक़ छोड़ दें, तब हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान आपके साथ है. कश्मीरियों ने तो दोनों चीज़ें छोड़ दीं. पाकिस्तान का स्लोगन भी छोड़ दिया, बंदूक़ भी छोड़ दी. लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ.

लीडरशिप को ज़लील कर रहे हैं

हिंदुस्तान को तो शेख़ अब्दुल्ला के ज़रिए एक मौक़ा भी मिला था. लेकिन उन जैसे बड़े नेता की पोजिशन को आपने छीना, फिर उन्हें जलील किया. उस शेख़ अब्दुल्ला को जिसको लोग पूजते थे. आप भले ही 1975 में फिर उन्हें वापस ले आए, लेकिन वो पोजिशन तो नहीं लौटा सके न, जो उन्होंने खोया, जो कश्मीर ने खोया. जब हिंदुस्तान ने इतने बड़े नेता के साथ ऐसा धोखा किया तो हुरियत वाले क्या बेवकूफ़ हैं कि हम दिल्ली आ जाएं. 2003 से पहले जब हुरियत एक थी तो दिल्ली वाले कहते थे कि ये हुरियत क्या है? इनसे क्या बात करना? लेकिन जब हमारे कुछ आपसी मतभेद हो गए और हुरियत के एक हिस्से का नेतृत्व उमर साहब के पास चला गया, उसके बाद आडवाणी का स्टेटमेंट था कि अब हम हुरियत से बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये कश्मीर की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं. जब हम एक थे, तो बोले नहीं. उन्होंने बातचीत की. लेकिन क्या किया, उमर साहब को ज़लील किया. उमर साहब की हैसियत अब हमारी वजह से वापस आ रही है. ये जेड कैटेगरी में बंदूक़ वालों की वजह से

कश्मीर की हालत को डिमोनेटाइज़ेशन से जोड़ा जा रहा है. यहां तो हमने कोशिश की कि आहिस्ता-आहिस्ता माहौल ठीक हो. तब तो डिमोनेटाइज़ेशन हुआ भी नहीं था जब स्थिति ठीक होने लगी थी. 90 के दशक में आर्मी के लोग यहां से गोल्ड चुराते थे, ज्वेलरी चुराते थे, पैसे चुराते थे. उसके बाद लोगों ने बचा-खुचा पैसा बैंकों में रखना शुरू कर दिया. उससे कश्मीर में बैंकिंग मज़बूत हुई. आज कह रहे हैं कि यहां ब्लैकमनी है. जबकि सबसे ज्यादा ब्लैकमनी अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है. बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स उनके साथ हैं और हमसे कहा जा रहा है कि कश्मीर में हवाला है. हिंदुस्तान में लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घरों में कैश रखते हैं. वहां का पॉलिटिशियन या वहां का कॉर्पोरेट ब्लैकमनी के खेल में शामिल है. अगर इतने बड़े आंदोलन को आप कहते हैं कि कोई मुल्क पांच सौ रुपया देकर आंदोलन चलवा सकता है तो ये पागलपन है.

यासीन मलिक के साथ क्या किया हिंदुस्तान वालों ने. उसके साथ हिंदुस्तान की पूरी सिविल सोसाइटी चलती थी. उससे बंदूक भी छुड़वा दिया, पकिस्तान भी छुड़वा दिया. आज तो वह कहता है कि ज़लील कर दिया हिंदुस्तान वालों ने. जब यह स्थिति है, जो लीडरशिप दिल्ली की तरफ़ जाती है, आप उसे ज़लील कर देते हैं, तो फिर दूसरा क्यों जाएगा? 2014 के इलेक्शन के पहले इन्होंने कहा कि आरएसएस आ रहा है, बीजेपी आ रही है, इसलिए सब लोगों को वोट में पार्टिसिपेट करना चाहिए. लेकिन बाद में उन्हीं के साथ सरकार बना ली. इससे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक बदले की भावना सामने आ रही है. इस तरह कर के आप यहां के यूथ को, अगली पीढ़ी को क्या पैगाम दे रहे हैं. आप कब तक हमें जला कर उसपर हाथ सेंकते रहेंगे?

हिंदुस्तान हमें अपना ताज कहता है. लेकिन क्या ताज के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? ताज पर आप तीरों की बारिश करेंगे, ख़ून बहाएंगे, मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे? आपने तो यहां डेमोक्रेसी का पूरा चेहरा कुरूप कर दिया. हिंदुस्तानी हमें पाकिस्तानी एजेंट कहते हैं, तो वह हमें गाली लगता है. क़रीब 80 लाख लोग सड़कों पर हैं. इतना बड़ा आंदोलन है और पूरी कम्युनिटी को आप कहते हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं. ये हमें कट्टर और उग्रवादी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि कश्मीर जैसी टॉलरेंट सोसाइटी कहीं है ही नहीं. पूरा हिंदुस्तान जब जल रहा था, 1947 में या उसके बाद भी जब कम्युनल रायट्स हुए, तब भी यहां शांति थी. कश्मीर की तुलना में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह उग्रवाद तेजी से बढ़ रहा है. भले ही वो इस्लाम के नाम पर हो या हिंदुत्व के नाम पर. कश्मीर का सबसे बड़ा डैमेज जो किया, वो कश्मीरी पंडितों ने किया. लेकिन कश्मीर की बड़ी आबादी आज भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है. इससे बढ़कर टॉलरेंस क्या हो सकता है. उन्होंने दिल्ली, मुंबई और बाक़ी जगहों पर उस चीज़ के लिए हमें इतना बदनाम किया, जो कि हुआ ही नहीं था. हमने तब भी कहा था कि भले ही उनसे हमारा मदभेद हो सकता है, लेकिन वे हमारे समाज के अंग हैं. गिलानी साहब को हिंदुस्तान में इतना बदनाम करते हैं, लेकिन इस मामले में उनका स्पष्ट मानना है कि पंडित यहां आ जाएं और उनका हक़ भी है यहां रहने का. वे एक शहरी की तरह, एक नागरिक की तरह यहां रह सकते हैं.

एक शख्स की बात मानकर आप देश चला रहे हैं. संसद देश चला रही है या सुरक्षा सलाहकार देश चला रहा है? कश्मीरियों का और हुरियत का यह एक क्लियर स्टैंड है. इतने बड़े मोदी और इतने बड़े उनके सुरक्षा सचिव को हमने पांच महीने ताक़तवर आंदोलन चला कर यह संदेश दिया कि कश्मीर को अपने हिसाब से नहीं चला सकते. आप हकीकत को तस्लीम करें. ये सिर्फ़ बुरहान फैक्टर नहीं था. इससे पहले भी ये था कि सैनिक कॉलोनी बनाओ, पंडित कॉलोनी बनाओ, 370 को हटाओ. जम्मू से आपने जितेंद्र सिंह को लिया. इसलिए लिया क्योंकि उसने 2008 में कश्मीर के ख़िलाफ़ ख़ूब गालियां दी थीं, हमारे बच्चों को मरवाया, उन्हें गाड़ियों के अंदर जलाया. कश्मीरी क्या बेवकूफ़ हैं, हम नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति किस डगर पर है? आप कश्मीर को हैंडल करने के लिए उस शख्स को ला रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ कश्मीरियों में बहुत नफ़रत पहले से है. भाजपा ने राममाधव को अपना एक्सपर्ट बनाकर भेजा है. वे ऐसे लोगों को कश्मीर भेजते हैं, जिन्हें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं. वे किन लोगों से मिलते हैं ये तो देखिए और ये हिंदुस्तानियों और बीजेपी से कहते हैं कि हम कश्मीर को सेटल करेंगे. हम तो कहते हैं कि वे जितना सेटल करने की कोशिश करेंगे, उतना आंदोलन तेज़ होगा.

कश्मीर की हालत को डिमोनेटाइज़ेशन से जोड़ा जा रहा है. यहां तो हमने कोशिश की कि आहिस्ता-आहिस्ता माहौल ठीक हो. तब तो डिमोनेटाइज़ेशन हुआ भी नहीं था, जब स्थिति ठीक होने लगी थी. 90 के दशक में आर्मी के लोग यहां से गोल्ड चुराते थे, ज्वेलरी चुराते थे, पैसे चुराते थे. उसके बाद लोगों ने बचा-खुचा पैसा बैंकों में रखना शुरू कर दिया. उससे कश्मीर में बैंकिंग मज़बूत हुई. आज कह रहे हैं कि यहां ब्लैकमनी है. जबकि सबसे ज्यादा ब्लैकमनी अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है. बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स उनके साथ हैं और हमसे कहा जा रहा है कि कश्मीर में हवाला है. हिंदुस्तान में लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घरों में कैश रखते हैं. वहां का पॉलिटिशियन या वहां का कॉर्पोरेट ब्लैकमनी के खेल में शामिल है. अगर इतने बड़े आंदोलन को आप कहते हैं कि कोई मुल्क पांच सौ रुपया देकर आंदोलन चलवा सकता है तो ये पागलपन है. जब इतनी बड़ी आबादी आपके ख़िलाफ़ है, किसी मुल्क के एजेंट के तौर पर काम करने के लिए तैयार है तो फिर आप करते क्या हैं? आपकी 5-6 लाख फ़ौजें फिर कश्मीर में करती क्या हैं? अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है. सबको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ? इस तरह से मीडिया को टाइट किया हुआ है कि कोई सच बता नहीं सकता. आजकल सबकी हाथों में मोबाइल होता है, उन्होंने फोटो तो अपलोड की होती कि देखिए जी हिंदुस्तान ने हमारा क्या हाल कर दिया. लेकिन ये हुआ नहीं.

हम दोनों तरफ़ के कश्मीर के बारे में बात करते हैं

हिंदुस्तान से हमारे अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं. लेकिन अब तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हम कश्मीरियों के लिए वहां नो एंट्री जोन बन रहा है. मालवीय नगर में ज़िवालिक में हमारा ऑफिस हुआ करता था, अब तो हुरियत लीडर वहां जाना ही नहीं चाहते. क्योंकि हमें पता है कि वहां पर रिएक्शन होगा. हुरियत नेता दिल्ली जाते हैं तो उनपर पत्थरबाज़ी कराई जाती है, उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं. ये कैसा समाज बना रहे हैं आप? क्या यही वो समाज है जो दुनिया को अमन दे सकता है. आज हम संतोष भारतीय से बात करते हैं. वे सच बताते हैं. अगर हमें हिंदुत्व से नफरत होती तो इनसे भी होती. अभी जेएनयू में कोई बात करता है तो वहां पर रिएक्शन होता है. हैदराबाद में कोई बात करता है तो वहां पर रिएक्शन होता है. क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही जम्हूरियत का चेहरा हम दुनिया को दिखा रहे हैं. लखनपुर से आगे हिंदुस्तान भले ही डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन हमने तो इसका भयानक चेहरा ही देखा है, जहां काले क़ानून हैं. यहां तो ये हाल है कि जितने मारो उतने स्टार चढ़ते हैं. जितना टफ कमांडर हो उतना ही रिवार्ड मिलता है. त्रासदी तो ये है कि हिंदुस्तान की फ़ौजें अपने प्रोमेशन के लिए फेक फिल्में बनाती हैं. इस हालत में हम इनसे किस ख़ैर की उम्मीद करें.

कश्मीर 70 सालों से उलझा हुआ है. ज्यादतियां भी हुई हैं. मुझे लगता है कि इसपर दोनों मुल्क बकवास कर रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा कंप्लेक्स मसला है. दुनिया में कौन सा मसला कंप्लेक्स है अगर करने की चाहत हो. जनमत संग्रह करा लिया जाए, लोगों से पूछा जाए. उसमें हम नहीं कहते हैं कि इधर ही पूछा जाए, सभी लोगों की राय ली जाए. विश्वास की कमी को बहाल करने के लिए पहले तो संवैधानिक स्थिति को बहाल करना पड़ेगा. इसमें तो हम कोई असंवैधानिक बात नहीं कह रहे हैं. अगर ऐसा होगा तो फिर लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. फिर यहां से कोई बोलेगा तो लोग सुनेंगे. इसके बाद दूसरा क़दम यह होगा कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए. क्योंकि हम जब भी कश्मीर के बारे में बात करते हैं, दोनों तरफ़ के कश्मीर के बारे में बात करते हैं. यह हिंदुस्तान की नैतिकता के ऊपर है. अगर उन्हें इसकी समझ होगी कि पहले कश्मीर के संवैधानिक अधिकार को बहाल करें, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ बात करे, तो उस बातचीत में वजन होगी. फिर कश्मीरी नेता भी शायद बात करें. कश्मीरी आज समझ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की तरफ़ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हिंदुस्तान में गुस्सा बढ़ता है.■

– लेखक हुरियत कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं.

शेख़ अब्दुल्ला और इंदिरा होतीं तो ये हाल न होता

जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी थे, तब तक कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग देखा जाता था. अब तो कहां–कहां तुलना हो रही है. पीओके, बलूचिस्तान, गिलगिस्तान. इससे तो और कहानियां बनती हैं. बॉर्डर पर इतनी फायरिंग हो रही है. इतनी क्षति 1972 से लेकर 2014 तक नहीं हुई थी, जितनी 2014 से अब तक हो गई. आपने ही लोकसभा चुनावों के समय बड़े–बड़े वादे किये थे कि हम आएंगे तो सीमा पर ये कर देंगे, वो कर देंगे. आपने कहा था कि कांग्रेस वाले तो बिरयानी पास चलाते थे. आप मुझे वोट दो मैं एक के बदले 100 सर दूंगा. वोट लेने के लिए इतना आगे थोड़ी न जाया जाता है कि आप संभाल ही ना पाओ. आपने इनके साथ सरकार बनाई और सारे एलीमेंट्स को एक साथ नाराज़ कर दिया. मेरे जैसे छोटे सियासी कार्यकर्ता को उस वक्त यह पता था कि मुफ्ती साहब सब कुछ करेंगे, लेकिन यह नहीं करेंगे. वह इंगेज करेंगे, वह टेर्स्टिंग करेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र में भाजपा को सपोर्ट मिला है, लेकिन वह सीधे तौर पर नहीं बोलेंगे कि यह मैं नहीं करूंगा.

जी. ए. मीर

कश्मीर अब छुपा हुआ मामला नहीं रहा. हम भी वही जानते हैं, जो दिल्ली, मुंबई में रहने वाला एक नेशनलिस्ट जानता है. असल में हम कई बार ख़ुद ही सियासत के चक्कर में अपना केस ख़राब कर लेते हैं. कौन ऐसा शख्स होगा जो देशहित में नहीं सोचेगा. पिछले दो वर्षों से जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि पंडित नेहरू ने देश ख़राब कर दिया. पंडित नेहरू जैसा व्यक्तित्व नहीं होता, तो आज आप भारत अधिकृत कश्मीर में नहीं होते. हर वक्त कागज़ी घोड़े ही काम नहीं करते, कहीं दोस्ती काम करती है, कहीं मोहब्बत काम करता है, कहीं दहशत काम करती है. यह सारी चीज़ें चलानी पड़ती हैं. शेख़ अब्दुल्ला जैसा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं होता, तो शायद हालात कुछ और होते. ऐसा नहीं है कि वह कमअक्ल या मूर्ख थे. उनको कश्मीर के लोगों की आर्थिक हालात पता थी. उस समय हमारे आर्थिक हालात भी बहुत ख़राब थे, संसाधन नहीं थे. उस स्थिति में कश्मीर को कहां ले जाया जाए, हिन्दुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ या आज़ाद. इसे लेकर शेख़ अब्दुल्ला ने बहुत समझदारी वाला फैसला किया. कश्मीर आज़ाद रह नहीं सकता था क्योंकि संसाधन नहीं थे. मुख्य मुद्दा था लोगों को ज़िंदा रखना. उन्होंने पाकिस्तान की ओर नज़र डाली, तो वहां देखा कि वहां इंसान, इंसान को ही खा रहे थे, फिर वे हमारे अवाम को क्या देते. हिंदुस्तान की तरफ़ नज़र डाली तो यहां पंजाब को देखा, जहां भारी मात्रा में अनाज पैदा हो रहा था. अपने लोगों का गुज़ारा करने के लिए भारत का साथ जरूरी था. यह कहना कि यह 70 वर्षों में फलाने ने स्थिति ख़राब कर दी, पूरी तरह से ग़ैर–ज़िम्मेदाराना बात है.

आंदोलन में आम लोग पिस गए

आप कब तक पिछले 70 सालों के फ़ैसलों पर सवाल उठाएंगे. अभी तो भारत को आगे ले जाने की आवश्यकता है विश्व प्रतिस्पर्धा में. हम जम्मू से अलग हैं और देश के अन्य राज्यों से भी अलग हैं. वहां खुले राज्य हैं, वहां पंजाब का आदमी हरियाणा, हरियाणा का आदमी दिल्ली, दिल्ली का आदमी राजस्थान, राजस्थान का आदमी गुजरात, गुजरात का आदमी मुंबई में आराम से रहता हुआ मिल सकता है. लेकिन यहां तो पिछले 70 वर्षों से आदमी को कुएं का मेंढक बनाया हुआ है. पिछले 5–6 महीने के आंदोलन से हुर्रियत ने फ़ायदा उठाने की सोची, लेकिन इनको भी कुछ नहीं मिला. पांच महीने हुर्रियत वालों ने कैलेंडर इसलिए चलाया क्योंकि वे बुरहान वानी से उकता गये थे. उन्हें लग रहा था कि बुरहान के रूप में नई जनरेशन का एक लीडर आ गया है. जब वह आउट पोस्ट हुआ, तो इन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए कि कहीं हमें मार न दे, शाम को कैलेंडर निकालना शुरू कर दिया. यह मिलीभगत है डीजीपी के साथ इनकी. सुबह इनको कहीं निकलना होता है, तो वे डीजीपी को कहते हैं कि यार हमें हाउस अरेस्ट कर लो. पांच महीने से वे भारतीय आर्मी के साथ ख़ुद को हाउस अरेस्ट किए हुए हैं. वे ख़ुद बाहर नहीं निकलना चाहते. कैसे निकलें, लोग इनपर टूट पड़ेंगे. यह जो पांच महीने चला, उसकी तैयारी पहले से थी. हुर्रियत को समझना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से 10 वर्षों के बाद हमारा यह सीज़न आया है. हमारे बाल–बच्चे भूखे मर रहे हैं. पर्यटन तो बैठ गया. आप बन्दूक़ शो करेंगे, तो टूरिस्ट कैसे आएंगे? कोई मरने थोड़ी ही आयेगा. कश्मीरियों ने गुहार लगाई कि हमें बचा लो, सीज़न है. लेकिन जब उन्हें नहीं मना पाए, तो कहा कि ठीक है तुम चलाओ कितने कैलेंडर चलाना है, अब तो हमारा सीज़न डूब गया. बीच में एक महीने पहले हुर्रियत वालों ने बुलाया था लोगों को रिशेडयूलिंग के लिए कि आप बताओ कि आपकी क्या मंशा है. लोगों ने कहा कि अब तो हमारा सीज़न बैठ चुका है. अब हमारे पास इस वक़्त कौन आ रहा है. आप करो अगर आपको आज़ादी मिलती है, तो हम एक झटका और झेलेंगे.

कश्मीर में लोगों को सरकारी योजनाओं के फ़ायदों से भी दूर किया जा रहा है. नरेगा जिसे भारत सरकार ने शुरू किया था, वह तक बंद कर दिया गया और इसका नोबल कल्चर ही चेंज कर दिया. इसीलिए इस बार यह मूवमेंट रूरल कश्मीर में चली है. श्रीनगर, अनंतनाग या जो छोटे क़स्बे हैं, इन्होंने इसको एडॉप्ट नहीं किया. आंगनबाड़ी भारत सरकार का प्रोजेक्ट है. हमारे यहां क़रीब 30 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और इसमें 60 हज़ार कर्मचारी हैं. वे लोकतंत्र की दुहाई लेकर आते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि जनाब हमारी तनख्वाहें बढ़ाइये. उन लड़कियों के ऊपर इन्होंने मिर्ची पानी फिकवा दिया. वही लड़कियां बाद में दुख्तरान–ए–मिल्लत बनकर सड़कों पर उतर आईं. हम तो यही चाहते हैं कि यह राज्य अच्छे तरीके से फले–फूले. इसकी नई नस्ल का भविष्य संवरे और तमाम लोग मिल–जुलकर एक साथ रहें. इसी में सबकी भलाई है. यशवंत सिन्हा यहां आए और राज्य सरकार इनको तमाम जगह पर व्यवस्थाएं करके घुमा रही थी. 1993 में दिल्ली से एक ग्रेट सोशल वर्कर आया था. उसने एक पहली कोशिश की कि उसने देश भर से 180 अंडरटेकिंग पत्रकार व वकीलों को यहां के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करने के लिए बुलाया और मुझे भी उसने कहा कि आपको मेरे साथ आना होगा. मैं उसके कहने पर आ गया.

कश्मीर में उड़ी से लेकर, बारामूला, टीटवाल से लेकर केरंग, फिर केरंग से द्रास तक सभी क्षेत्र फलों की पैदावार में नंबर वन पर आते हैं. यहां के लोगों का जीवन इसी पर बसर होता है. हज़ारों लाखों टन फल पैदा होता है. ये लोग सेब के पेड़ों की उतनी ही देखभाल करते हैं, जितनी कि अपने बच्चों की करते हैं. ये सेब दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, पंजाब आदि जगहों पर भेजे जाते हैं. अब जब ट्रांस्पोर्ट ही नहीं है, तो वे फल पेटियों में रखे–रखे सड़ जा रहे हैं. मंडी में उन्हें स्टोरेज के लिए जगह भी नहीं मिलती है. ये लोग हज़ार रुपये पेटी की अपेक्षा के साथ मंडी जाते हैं लेकिन इन्हें वह भाव नहीं मिल पाता और इनके तमाम सपने चकनाचूर हो जाते हैं. जिसके बाद वे सीधे हिन्दुस्तान को बुरा भला कहते हैं.

31 अक्टूबर को हमने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया. उन्होंने कह रखा था कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन राज्य सरकार कहां मानती है. हालात बहुत ख़राब थे उस समय. इन्होंने सुरक्षा दी और हमें होटल लाया गया. इत्तेफ़ाक़ से उस दिन 31 अक्टूबर था. इंदिरा गांधी की बरसी थी. इसमें एक–दो लोग कांग्रेस के रहे होंगे, जो इंदिरा जी को श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए. शाम को खाना खाने के बाद किसी ने टेबल पर फोटो लगाई और बोला जो सुबह श्रद्धांजलि नहीं दे पाए वह अब दे सकते हैं.

कश्मीर में उड़ी से लेकर, बारामूला, टीटवाल से लेकर केरंग, फिर केरंग से द्रास तक सभी क्षेत्र फलों की पैदावार में नंबर वन पर आते हैं. यहां के लोगों का जीवन इसी पर बसर होता है. हज़ारों लाखों टन फल पैदा होता है. यह लोग सेब के पेड़ों की उतनी ही देखभाल करते हैं जितनी कि अपने बच्चों की करते हैं. ये सेब दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, पंजाब आदि जगहों पर भेजे जाते हैं. अब जब ट्रांस्पोर्ट ही नहीं है, तो वे फल पेटियों में रखे–रखे सड़ जा रहे हैं. मंडी में उन्हें स्टोरेज के लिए जगह भी नहीं मिलती है. ये लोग हज़ार रुपये पेटी की अपेक्षा के साथ मंडी जाते हैं लेकिन इन्हें वह भाव नहीं मिल पाता और इनके तमाम सपने चकनाचूर हो जाते हैं. जिसके बाद वे सीधे हिन्दुस्तान को बुरा भला कहते हैं. हमने कई बार भारत सरकार से अपील की कि आपकी जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनमें कम से कम 5 प्रतिशत तक कश्मीरियों को जगह दीजिए, जिससे वे अपना भविष्य संवार सकें. इसको देखते हुए हमारी सरकार ने एक ओवरसीज़ डिपार्टमेंट भी बनाया था. यहां इसके नाम पर फ्रॉड बहुत होते हैं. यहां से बड़े–बड़े ठेकेदार लालच देकर लड़कों को ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर इन्हें कुछ नहीं मिलता और इन्हें रो धोकर वापस आना पड़ता है.

भाजपा ने वादे पूरे नहीं किए

जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी थे, तब तक कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग देखा जाता था. अब तो कहां–कहां तुलना हो रही है. पीओके, बलूचिस्तान, गिलगिस्तान. इससे तो और कहानियां बनती हैं. बॉर्डर पर इतनी फायरिंग हो रही है. इतनी क्षति 1972 से लेकर 2014 तक नहीं हुई थी, जितनी 2014 से अब तक हो गई. आपने ही लोकसभा चुनावों के समय बड़े–बड़े वादे किये थे कि हम आएंगे तो सीमा पर ये कर देंगे, वो कर देंगे. आपने कहा था कि कांग्रेस वाले तो बिरयानी पास चलाते थे. आप मुझे वोट दो मैं एक के बदले 100 सर दूंगा. वोट लेने के लिए इतना आगे थोड़ी न जाया जाता है कि आप संभाल ही ना पाओ. आपने इनके साथ सरकार बनाई और सारे एलीमेंट्स को एक साथ नाराज़ कर दिया. मेरे जैसे छोटे सियासी कार्यकर्ता को उस वक्त यह पता था कि मुफ्ती साहब सब कुछ करेंगे, लेकिन यह नहीं करेंगे. वह इंगेज करेंगे, वह टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि एक क्षेत्र में भाजपा को सपोर्ट मिला है, लेकिन वह सीधे तौर पर नहीं बोलेंगे कि यह मैं नहीं करूंगा. आख़िरकार इनको अपनी ज़मीन का अहसास रहेगा कि यह मुझे सूट नहीं करेगा, कोई और बहाना लेंगे. एनसी कांग्रेस भी इनको सूट नहीं करती, ना करना चाहिए. अब ज़ाकिर नाईक के मुद्दे को ले लीजिए, वह वाहबी है. ज़ाकिर नाईक का यहां कोई तबक़ा नहीं है. मेरे ख्याल से कश्मीर में 2 प्रतिशत भी ऐसे लोग नहीं हैं. लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते जो आक्रामक रुख़ इस पर अपनाया गया, इसका प्रभाव यहां भी नज़र आया. पीडीपी और भाजपा ने लोगों को सरकार के गठबंधन पर कई दिनों तक लोगों को तनाव में रखा. मैंने नरेन्द्र मोदी से दिल्ली में कहा कि मोदी साहब मुझे दो चीज़ें स्पष्ट कर दीजिए कि बुरहान वानी क्या था. उसके मरने के आठ दिन बाद महबूबा मुफ्ती बयान देती हैं कि मुझे पुलिस और एजेंसियों से जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार हमारी एजेंसियों और सुरक्षा बलों को यह जानकारी नहीं थी कि वहां एनकाउंटर हो रहा है. यही बयान भाजपा के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह दूसरे दिन जम्मू में दे रहे थे.

वाजपेयी जी के समय में क्या हुआ था. उन्होंने सुरक्षा बलों से कह दिया था कि हमारी ओर से पहली गोली नहीं चलनी चाहिए. बक़रीद का दिन क़ुर्बानी का एक महान दिन होता है. हम 6 महीने के लिए बहुत अपमानित हुए और बहुत तबाही हो चुकी थी. कहा गया कि हम भी अपील करेंगे. दो वर्षों के अन्दर कोई न कोई तरीका निकालकर इस मिशन को आगे लेकर जाया जाएगा. हमने कहा कि यह अवसर है कि आप अपील करें, कुछ जानें बच जाएंगी. हमारे जवान भी बच जाएंगे, जिन बेचारों को रात दिन पता नहीं होता है कि कब कहां दौड़ना है. आप इतना कर लेंगे तो क्या फ़र्क़ पड़ता है. इतना बड़ा मुल्क है, यह आपके अपने लोग हैं. मैंने कहा कि कश्मीर के लोग भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन बहुत जीनियस हैं. ग़रीब ज़रूर हैं लेकिन सियासी तौर पर बहुत होशियार हैं. वे अच्छी तरह जानते हैं कि कब क्या करना है. हमने कहा कि आप इधर से ही पहलवान की तरह कुश्ती करने आते हो कश्मीर के लोगों के साथ. आप यह तो अहसास दे दो कि ये मेरे अपने लोग हैं. ज़बान से तो साफ़ रहो. फिर अगर एक्शन में कहीं आपको लोहा टकराना है, तो वह अलग बात है लेकिन ज़बान पर तो अटल रहो. हमने कई बार कहा कि ये जो आप कहते हो कि कश्मीर के साथ हमारा विलय है. यह कागज़ी सबूत नहीं है. यह नेहरू परिवार के द्वारा इस सोसायटी को दिया हुआ है.

अगर एक सिंगल लीडर शेख़ अब्दुल्ला जैसा होता और भारत में इंदिरा गांधी जैसी लीडर होतीं, तो आज आपको यह स्थिति न देखनी पड़ती. समस्या न तो आज़ादी है, न पाकिस्तान है और न हिन्दुस्तान. अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कश्मीर के एक करोड़ लोगों से पूछे, तो पता चलेगा कि वे भारत के पक्ष में जाएंगे. कश्मीर के लोग तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं. अगर 2002 में यह पीडीपी न बनी होती, नेशनल कांफ्रेंस आ गई थी धीरे–धीरे ट्रेंड में. पीडीपी आडवाणी की देन थी. आप शेख़ अब्दुल्ला को मिलिटेंसी से लाए और सरकार दे दी. क्या फ़र्क़ पड़ता है. अगर आपको मैंडेट मिलता है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं. चुनाव के द्वारा आप मैदान में आएं. 370 हमें प्रोटेक्शन के रूप में मिला था. इसके लिए आरोप भी अधिकतर कांग्रेस पर ही लगते हैं. लेकिन इसे अगर आप देखेंगे कि यही प्वाइंट शेख़ अब्दुल्ला ने उठाया था, जब नेहरू ने स्पेशल स्टेटस के तहत इनको एक सेफ्टी दी थी. जब 75 का एग्रीमेंट हुआ, इस समय भी यह स्थिति सामने आई कि इसका यह वैल्यु नहीं रहा, जो तब था.■

–लेखक जम्मू–कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं.

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीरी नेताओं ने भी कश्मीर को कुछ नहीं दिया

मैं छह-सात बार पाकिस्तान गया. वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आपस में सुलह हो जाए. रास्ते खुल जाएं. कश्मीर कार्ड, पाकिस्तान का ट्रंप कार्ड है. वहां का कोई प्रधानमंत्री कश्मीर की बात न करे तो अगले दिन ही बाहर हो जाएगा. हमारे अलगाववादी ग्रुप के जो लड़के हैं, वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं. पीओके का झंडा लहराते हैं. आईएसआईएस का झंडा फहराते हैं. उसका मतलब भी उन्हें नहीं मालूम होगा. इतना ही नहीं, चाईना का झंडा भी लहरा रहे हैं. बेचारों को पता नहीं है कुछ. मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको कोई पैसा देता है या नहीं देता है. लेकिन इस वक्त जो सूरतेहाल है, आजकल के जो लड़के हैं, वे पैसों के बग़ैर ये करते हैं. लेकिन इन लड़कों ने अपने क्लास के दोस्तों को घायल होते, मरते देखा है. आंख की रोशनी खोते देखा है. अब अगर हमें कश्मीर का समाधान चाहिए, तो कैसे मिलेगा? भारत-पाकिस्तान अगर दोनों एक्स्ट्रीम पोजीशन पर हों, तो क्या होगा? अगर ऐसे ही ख़ून बहता रहेगा तो कश्मीर का समाधान (सॉल्यूशन) कैसे निकलेगा?

गुलाम नबी ख्याल

कश्मीर वाक़ई एक समस्या है. ये यूनाइटेड नेशन्स के एजेंडे पर भी है. अगर समस्या नहीं होती तो यूनाइटेड नेशन्स की मिलिट्री ऑब्जर्वर्स नहीं होती. यहां भी स्थायी स्टेशन और उस पार भी. उनका मुख्य मक़सद है सीजफायर पर निगरानी रखना. भारत ये कभी नहीं बोलता कि ये समस्या नहीं है. लेकिन बदक़िस्मती से दोनों ने एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया है. अब भारत कहता है कि पीओके हमें वापस मिलना चाहिए. मैं कहता हूं कि जबतक आप ज़िंदा हैं, हम भी हैं इतिहास में, ऐसा कभी नहीं होगा. पिछले 26-27 साल से पाकिस्तान ने हमें क्या दिया. हथियार दिए, लाखों की तादाद में एके राइफल्स दिए और यहां लोग मारे गए. मैं आम आदमी के बारे में बात कर रहा हूं न कि सैनिकों की. अगर यहां से गन नहीं आता, यहां ये लोग नहीं मारे जाते. कितना इतिहास दोहराऊं. शेख़ अब्दुल्ला के साथ कश्मीर एकॉर्ड हुआ था 1975 में. फिर मीर क़ासिम को क्यों हटा दिया. यह डेमोक्रेसी नहीं है. एक को बिठाओ, दूसरे को हटाओ. सप्रेशन की बात है. लोगों को पेलेट गन से मारा. अगर हम तुलना करें अफग़ानिस्तान का, वहां दस लाख लोग मरे. इराक में अभी तक दस लाख मरे हैं. सीरिया में इससे ज्यादा मरे हैं. लेकिन भारत कभी ईमानदारी से कोशिश नहीं करता. पाकिस्तान को भी कश्मीरी अवाम के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं छह-सात बार पाकिस्तान गया. वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आपस में सुलह हो जाए. रास्ते खुल जाएं. कश्मीर कार्ड, पाकिस्तान का ट्रंपकार्ड है. वहां का कोई प्रधानमंत्री कश्मीर की बात न करे तो अगले दिन ही बाहर हो जाएगा. हमारे अलगाववादी ग्रुप के जो लड़के हैं, वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं. पीओके का झंडा लहराते हैं. आईएसआईएस का झंडा फहराते हैं. उसका मतलब भी उन्हें नहीं मालूम होगा. इतना ही नहीं चाईना का झंडा भी लहरा रहे हैं. बेचारों को पता नहीं है कुछ. मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको कोई पैसा देता है या नहीं देता है. लेकिन इस वक्त जो सूरतेहाल है, आजकल के जो लड़के हैं, वे पैसों के बग़ैर ये करते हैं. लेकिन इन लड़कों ने अपने क्लास के दोस्तों को घायल होते, मरते देखा है. आंख की रोशनी खोते देखा है. अब अगर हमें कश्मीर का समाधान चाहिए तो कैसे मिलेगा? भारत-पाकिस्तान अगर दोनों एक्स्ट्रीम पोजीशन पर हों तो क्या होगा? अगर ऐसे ही ख़ून बहता रहेगा तो कश्मीर का समाधान (सॉल्यूशन) कैसे निकलेगा?

कश्मीर का मतलब कश्मीर घाटी है

दुर्भाग्य से इस रियासत में जो तीन हिस्से हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों में किसी भी तरह की कोई समानता है ही नहीं. ये तो डोगरों ने अपने राज्य का विस्तार किया, अन्यथा कश्मीर का मतलब है सिर्फ कश्मीर घाटी. हरि सिंह, जो अंतिम डोगरा राजा थे, उनकी कार का नंबर था, कश्मीर-1. तो, इस पूरे मसले का केंद्र बिन्दु कश्मीर है. मैं कहूंगा कि कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए. जम्मू वाले एक अलग स्टेट मांग रहे हैं. मैं इसका समर्थन करता हूं. यह एक सही मांग है. जवाहर टनेल से उरी तक कश्मीर घाटी है. इसे एक ऑटोनोमस स्टेट बनाना चाहिए. जाहिर है, भारत के भीतर ही, लेकिन भारत का सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफयर्स और कन्युनिकेशंस पर अधिकार हो (जैसा कि डॉक्टर कर्ण सिंह ने भी राज्यसभा में कहा है) और हमारा अलग संविधान और झंडा बना रहे.

अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस बात को मानेगा? वो तो इसी कश्मीर को चाहते हैं. मेरी व्यक्तिगत समझ है कि अगर उनको ये यक़ीन दिलाया जाए कि पीओके तुम रखो, हम कश्मीर को ऑटोनोमी देंगे. अब, कश्मीर में जब दिल्ली से लोग आते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आप आप इंडिया से आए हैं. इसका मतलब है कि लोग कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानते. कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि कश्मीर कैसे सर्वाइव करेगा? मैंने इसपर थोड़ा काम किया है. कश्मीर की आर्थिक स्थिति अच्छी है. 1947 के बाद से कश्मीर दूध, सब्ज़ी, पॉल्ट्री एक्सपोर्ट करता रहा है. हमारे टूरिज्म को विकसित किया जाना चाहिए. हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और हैंडिक्राफ्ट तो दुनिया में मशहूर है.

हमारे पास लीडर्स रहे ही नहीं

पिछले चार महीने में क्या हुआ? कितने लोग मरे? 7000 से ज्यादा जेल में हैं. इस सब का नतीजा क्या है? हुर्रियत के

मोदी सरकार का जो इंप्रेशन है कश्मीर पर वह बहुत बुरा है. कश्मीर का सबसे कुरूप चेहरा आज भी हम देख रहे हैं. दुर्भाग्य ये है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है. गिलानी के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलेगा. मैं गिलानी साहब से पूछूंगा कि 26 साल से आप लीड कर रहे हैं एक मूवमेंट को, आप बताइए क्या पॉजिटिव नतीजा निकला है? ये सवाल करने का मुझे हक़ है. ये मैं पूछूंगा उनसे. कश्मीर में बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है. राजनीतिक विश्लेषक बहुत हैं, उनमें वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेखक भी हैं, लेकिन बोलता नहीं है कोई.

लेखक के साथ जा रहा था. हाथ में पत्थर लिए एक आदमी ने एक बड़ा पत्थर उठाकर मेरी गाड़ी को मारा और शीशा टूट गया. मैंने गाड़ी रोक दी. गाड़ी से उतरा तो वो लोग भाग गए. लेकिन एक लड़का वहीं खड़ा रहा. मैंने उसे बुलाया, उससे कहा कि भाई क्यों तोड़ा? कहा, इसलिए तोड़ा कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया. यही जवाब था उसका. मैं क्या कहता उससे. अब अगर मैं उससे पूछता कि अमेरिका कहां है, इराक कहां है तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता. ऐसी हमारी तहरीक चल रही है. इंडिया इसी का फ़ायदा उठा रहा है. हमारी बात को समझिए, हमारे पास लीडर्स रहे ही नहीं. सीएम रहते हुए एक बार डॉ. फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत को इजरायल की तरह पीओके पर बमबारी करनी चाहिए.

एक पुराने चेयरमैन प्रो. अब्दुल ग़नी बट ने कहा था कि ये मूवमेंट ऐसे हैं, जैसे कोई लंगड़ा घोड़ा और उसपर एक अंधा सवार है. वही हो रहा है इस वक्त. अब धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं. ट्रांसपोर्ट चल रहा है. मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी मंज़िल क्या है? यासीन मलिक हों, उमर फ़ारूक़ हों, गिलानी हों, कोई डिफाइन नहीं करता कि हम क्या चाहते हैं. कश्मीर का क्या होना चाहिए. क्या राजनीतिक भविष्य हो? कोई नहीं कहता. उनके ख़िलाफ़ जो बोलेगा वो ग़द्दार है, वो आईबी एजेंट है, वो इंडियन एजेंट है. यहां फ्री वॉयस को सबसे ज्यादा नुक़सान शेख़ अब्दुल्ला ने पहुंचाया. दो बार वे सीएम रहे. एक बार भी बात करने की इज़ाज़त नहीं दी. इसी वजह से आज लोगों की अलग-अलग आवाज़ें सुनते हैं. एक क़िस्सा बताता हूं. साल 2000 में मैं अपनी गाड़ी में बहुत बड़े एक अभी वे सीएम नहीं हैं. अभी कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है. अब कैसे आप जज करेंगे उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर. कश्मीरियों का दोहन किया गया है.

अलबत्ता ये है कि अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का कोई मक़सद है भी या नहीं. बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं. लीबिया या सीरिया में लोग किसी मकसद के लिए अपनी जानें दे रहे हैं. लेकिन एक शख्स जो पत्थर मारते-मारते गोली खाता है, मुझे नहीं मालूम कि मैं उनलोगों को कैसे पुकारूं? वे शहीद हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम. हमारे मज़हब में शहीद की एक परिभाषा है. बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है. उस परिभाषा के मुताबिक़, इनमें से कोई शहीद नहीं है. किसी को पत्थर मारो, सीआरपीएफ वाले को पत्थर मारो, ये क्या है? ये नहीं भूलना चाहिए कि सेना का कोई आदमी आपको नहीं छेड़ेगा, जबतक आप उसे पत्थर नहीं मारेंगे. उसके पास गन है, तो वे उसका इस्तेमाल करेंगे. इस वक्त हमलोग उस स्टेज पर खड़े हैं कि हम इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकते कि आगे क्या होगा? हम अंधेरे में, हवा में तीर चला रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या होगा. दिल्ली में हमारे कुछ दोस्त हैं. उनमें से कइयों की राय है कि इंडिया भी इस पर सहमत होगा कि जम्मू को स्टेट बनाओ, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, कश्मीर को ऑटोनोमी दो. सरकार क्या इस पर सोचती है, मुझे नहीं मालूम. मोदी सरकार का जो इंप्रेशन है कश्मीर पर, वह बहुत बुरा है. कश्मीर का सबसे कुरूप चेहरा आज भी हम देख रहे हैं. दुर्भाग्य ये है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है. गिलानी के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलेगा. मैं गिलानी साहब से पूछूंगा कि 26 साल से आप लीड कर रहे हैं एक मूवमेंट को, आप बताइए क्या पॉजिटिव नतीजा निकला है? ये सवाल करने का मुझे हक़ है. ये मैं पूछूंगा उनसे. कश्मीर में बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है. राजनीतिक विश्लेषक बहुत हैं, उनमें वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेखक भी हैं, लेकिन बोलता नहीं है कोई.

95 फ़ीसदी आज़ाद कश्मीर के लिए वोट करेंगे

एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अगर 1989 में पाकिस्तान से हज़ारों लोग बंदूक़ ले कर आ गए तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया था? ख़ैर, जो लोग वहां से बंदूक़ ले कर आए उन्होंने एक आकर्षक नारा दिया, हम क्या चाहते, आज़ादी. इस आज़ादी से हर शख्स ने ये मतलब निकाला कि कश्मीर की आज़ादी. इसमें जम्मू वगैरह का नाम नहीं आया. लेकिन जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला कि ये तो हमने शुरू किया था, पैसे दिए, हथियार दिए, अब ये अलग हो रहे हमसे. कश्मीर को अलग कर रहे हैं. तो उन्होंने इसको हाइजेक किया. हाइजेक करवाया हिज्बुल मुजाहिदीन के द्वारा. पहले हम जैसे पढ़े-लिखे लोग हैरान रह गए कि हिज्ब क्या होता है? मैंने कभी नहीं सुना था हिज्ब का मतलब. फिर पता चला, पार्टी. उन्होंने इसको हाइजेक किया. इससे फिर यासीन मलिक दब के रह गए. उसी ख़ौफ़ से यासीन मलिक ने कहा कि मैंने गन छोड़ दिया. अब मैं गांधी के रास्ते पर चलूंगा. कश्मीर त्रासदी की कहानी है. इसमें आपको कहीं भी कॉमेडी नज़र नहीं आएगी. मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझता हूं कि इंडिया के मुस्लिम प्रेस को जो रोल कश्मीर के मामले में अदा करना चाहिए वो कभी नहीं किया. इतना डरा हुआ भी नहीं होना चाहिए.

आज अगर कश्मीर में जनमत संग्रह करेंगे तो 95 फ़ीसदी आज़ाद कश्मीर के लिए वोट करेंगे. कश्मीर से मेरा मतलब कश्मीर है, जम्मू और लद्दाख नहीं है. बाकि के 8 या 10 फीसदी हैं उसमें से जमात के कुछ लोग शायद पाकिस्तान को वोट दें. मैं इसे लेकर निश्चित नहीं हूं. कुछ लोग ऐसे हैं, जिनका सारा रिश्ता ही हिन्दुस्तान से है. चाहे वे सीएम रहे हों या ब्यूरोक्रेट्स रहे हों, वे हिन्दुस्तान को वोट देंगे. गिलानी साहब कहते हैं कि रायशुमारी कराओ. ठीक है. ये तो तीनों क्षेत्र में होगी, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख. यदि इस रायशुमारी में भारत जीतता है तो गिलानी साहब क्या कहेंगे? सारा जम्मू, इंडिया को वोट देगा. सारा लद्दाख इंडिया को वोट देगा. यहां के भी कुछ लोग देंगे. इस हिसाब से अगर भारत बहुमत पा लेता है तो गिलानी साहब के पास क्या रास्ता है? हमें कश्मीर को आज की हालात से देखना है. भारत अगर सोचता है कि वो आम आदमी के साथ जोर ज़बरदस्ती कर कश्मीर को थाम कर रख पाएगा, मैं ऐसा भी नहीं मानता. जितना ज़ुल्म होगा, उतना आप उभरेंगे. ये हमारी बदक़िस्मती है.■

लेखक कश्मीर के मशहूर लेखक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

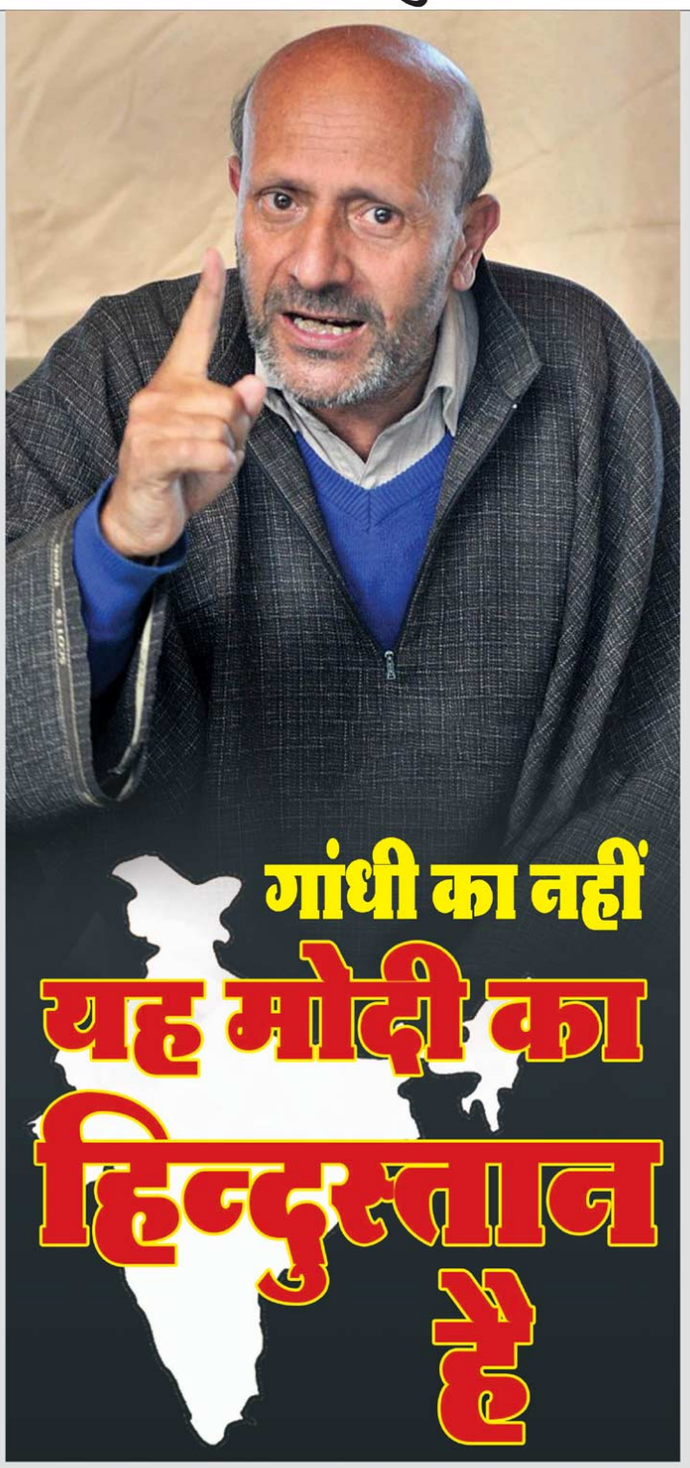

गांधी का नहीं यह मोदी का हिन्दुस्तान है

> मुझ पर इल्ज़ाम लगाया वो बीफ पार्टी का. क्या हुआ मेरे साथ? असेंबली में छह-सात एमएलए मेरी छाती पर चढ़े, पिटाई की. एक ज़ुल्म की सज़ा कितनी बार मिलती है, मैं आपसे पूछता हूं. एक ही बार मिलती है न. मैंने बीफ ही खाया. किसी का ख़ून नहीं किया था. किसी का घर नहीं जलाया था. किसी की इज्जत नहीं लूटी थी. अब एक गुनाह की सजा, एक बार. पहले एफआईआर हुई थी मेरे ख़िलाफ़. फिर अटैक किया, गाड़ी तोड़ डाली, फिर रजौरी में अटैक किया. दिल्ली में मेरे ऊपर स्याही डाली गई.

इंजीनियर रशीद

श्री श्री रविशंकर जिनकी हिन्दुस्तान में क्रेडिबिलिटी है, एक धार्मिक नेता हैं, उनका कहना है कि बुरहान वानी का पिता दो दिन उनके पास रहा. एक ऐसे मौक़े पर जब यहां आग लगी हुई थी. जब हालात थोड़े ठीक हुए तो जम्मू में उन्होंने हुर्रियत को गालियां दीं. उन्होंने इस हद तक कहा कि उनके (कश्मीरियों के) डीएनए ठीक करने पड़ेंगे. इससे लोगों को तक़लीफ़ पहुंचती है. इसलिए वो अपना एतबार खो चुके हैं. हमें भारत के लोगों से पूछना चाहिए कि आप हमारे पास क्यों आते हैं? कश्मीर का मसला तो पूरी दुनिया को पता है. दुनिया को मालूम है कि हमारा मसला क्या है? हमारा झगड़ा क्या है? जब भी कोई हिन्दुस्तान से यहां पर आता है, चाहे भारतीय साहब हों, मोदी साहब हों या सोनिया जी हों, मुझे ये कहते हुए अफ़सोस हो रहा है और माफ़ी के साथ ये कहता हूं कि हमें लगता है कि ये हमारी क़ुर्बानियों का अपमान करने आते हैं.

इंसानों की तरह से पेश आइए

मैं एमएलए हूं. कश्मीर के सवाल से अलग मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं. अगर मैं एमएलए बना तो मैंने भारत के संविधान की शपथ ली. तो क्या वजह है कि हिन्दुस्तान मुझे भी अपना नहीं समझता. मैं नही चाहता हूं कि मुझे पावर मिले, रुपया मिले, ऐशो-आराम मिले. मैं ये चाहता हूं कि मेरे दिल का जो दर्द है वो कोई समझे. इसलिए ख़ुदा के लिए कुछ कीजिए. इस मुसीबत से हमें बाहर निकालिए. कोई लॉलीपॉप देकर नहीं, कोई टॉफी देकर नहीं. धोखे से नहीं, जो 47 से आजतक आपने किया है. मैं सीधा स्टेट फॉरवर्ड आदमी हूं. बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि कोई हिन्दुस्तानी कश्मीरी के पास आने लायक़ ही नहीं है. यहां वादों के तोड़ने का लंबा इतिहास है. 47 से लेकर आज तक दुनिया का कोई झूठ नहीं होगा जो भारतीयों ने हमसे नहीं बोला होगा. चाहे कोई हो. अर्णब गोस्वामी हों, प्रेमशंकर झा हों, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभभाई पटेल हों. हमारे साथ इंसानों की तरह से पेश आइए. हमारा मामला साफ़ है. हमारे ज़ेहन में उलझन नहीं है. जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब हम एक संप्रभु राज्य थे. यहां पर अंग्रेज़ों का क़ब्ज़ा नहीं था. जब आपको आज़ादी मिली तो आप अपने मुल्क को इकट्ठा न रख सके (उसके तीन हिस्से कर दिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया) और हमारे दो हिस्से कर दिए. कुछ पाकिस्तान में कुछ भारत में. कुछ तो होना चाहिए. ऐसे काम नहीं चलेगा कि यहां कुछ होगा, तो भारत से लोग आएंगे डल झील की सैर हो जाएगी, गिलानी के साथ चाय का एक कप हो जाएगा, इंजीनियर रशीद से दो बातें हो जाएंगी, आम आदमी से मिलेंगे. भारत दरअसल अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है.

कश्मीर को हिन्दुस्तान की एजेंसियां चला रही हैं

कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, हम प्लेबिसाइट (जनमत संग्रह) चाहते हैं. यह एक अंतरराष्ट्रीय सतह पर स्वीकार की हुई बात है. अब अगर कोई यहां कश्मीर से आता है तो वो क्या देगा? वह यह पूछने आता है कि यहां का मसला क्या है. जबकि यहां मसला बताते-बताते थक गए हैं. यहां झूठ, ख़ून, सेल्फ रेस्पेक्ट का मसला है. गिलानी को मैं चोर लग रहा हूं, वो मुझे चोर लग रहे हैं. यह भारत ने हमें दिया. एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ाकर दिया. हम सांप्रदायिक लाइन पर समस्या का समाधान नहीं चाहते. कश्मीरी पंडित हमारे रूह और ख़ून में शामिल हैं. पता नहीं हिन्दुस्तान क्या समझता है. एक दिन आपका भी आएगा. याद रखना, ज़िंदगी रही तो देखेंगे, नहीं रही तो इतिहास में भी लिखा जाएगा. मोदी जी हिन्दुस्तान का मैटेरियल हैं, वो कौन होते हैं कहने वाले. इलेक्शन जब लड़ते हैं तो कहते हैं सड़क, पानी, बिजली के लिए है. मसला हल करेंगे. आई डोंट नो, आपका मैंडेट क्या है? आप कुरान लाओ, गीता लाओ, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कश्मीर को हिन्दुस्तान की एजेंसियां चला रही हैं.

मुझ पर इल्ज़ाम लगाया वो बीफ पार्टी का. क्या हुआ मेरे साथ? असेंबली में छह-सात एमएलए मेरी छाती पर चढ़े, पिटाई की. एक ज़ुल्म की सज़ा कितनी बार मिलती है, मैं आपसे पूछता हूं. एक ही बार मिलती है न. मैंने बीफ ही खाया. किसी का ख़ून नहीं किया था. किसी का घर नहीं जलाया था. किसी की इज़्ज़त नहीं लूटी थी. अब एक गुनाह की सज़ा, एक बार. पहले एफआईआर हुई थी मेरे ख़िलाफ़. फिर अटैक किया, गाड़ी तोड़ डाली, फिर रजौरी में अटैक किया. दिल्ली में मेरे ऊपर स्याही डाली गई.

मेरा कहना है कि जब आप जम्मू में 15 हज़ार लोगों को हथियार देते हो, सो-कॉल्ड विलेज डिफेंस कमिटीज को तो कश्मीर में विलेज स्कूल कमिटीज बनाओ, हमको हथियार दो, हम स्कूल की हिफ़ाज़त करेंगे. बट यू डॉन्ट ट्रस्ट अस. आप हमें हथियार नहीं दोगे. जम्मू में आपने सभी शराबियों, बदमाशों को हथियार दिए हैं. आरएसएस वाले ख़ुद ही ये काम कर रहे हैं. लानत है उस शख़्स पर जो इस तरह की सोच रखता है. इस तरह से आपने कश्मीर को खो दिया है. यू हैव लॉस्ट कश्मीर. बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है. आज पर्यटक भी कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं. कुछ करो, नहीं तो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है. ये कॉस्मेटिक देने से, पेन किलर देने से कुछ नहीं होने वाला है.

हमारा अपमान हो रहा है

सरकार कहानी बनाने में व्यस्त है. आपने क्या स्टोरी बनाई सर्जिकल स्ट्राइक पर. 98 प्रतिशत लोगों ने एग्ज़ाम दिया. फिर भी आप हमारे ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं. पॉलिटिक्स मत करो. हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप कम से कम हमारे दुख-दर्द को बांटने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मसला क्या है? श्रीश्री रविशंकर कहते हैं कि कश्मीरियों को मालूम नहीं है कि आज़ादी क्या होती है. हमको मालूम नहीं है कि आज़ादी क्या है? हमने अफ़गानों को भगाया, पठानों को भगाया. फिर भी 47 से लगातार हम लड़ते आ रहे हैं. गिलगित-बलतिस्तान के लोगों ने, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने मुझे दस बार बोला कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. तो हम भी यही कहते हैं कि जब गिलगित-बलतिस्तान के लोग हैं आपके साथ, आज़ाद कश्मीर के लोग आपके साथ हैं. जम्मू तो सारा आपका है. लद्दाख तो आपका है. कश्मीर में महबूबा मुफ्ती कहती है कि सब लोग आज़ादी ढूंढते हैं. तो ठीक है, एक प्लेबिसाइट हो जाए. तो डर किस बात का है. आप रायशुमारी करवाओ.

सिर्फ़ ताक़त के बल पर आप हमें दबा रहे हैं. हमने हिन्दुस्तान का क्या बिगाड़ा है? मैं जिस इलाक़े में रहता हूं, वहां पर मेरे साथ बदतमीज़ी हुई थी. मेरे सारे कपड़े निकाल दिए गए थे. तभी मैंने नौकरी छोड़ दी. हम आपसे बिहार, असम, पंजाब नहीं मांगते. हम आपसे जम्मू-कश्मीर मांगते हैं, जो हमारा हक़ है. सिविल सोसाइटी को यहां पर काम करने की ज़रूरत नहीं है. दिल्ली में काम करने की ज़रूरत है. आप लेफ्ट पार्टी से लेकर बाक़ी दलों को कह दीजिए कि हम लोग जनमत संग्रह चाहते हैं.

सिर्फ़ ताक़त के बल पर आप हमें दबा रहे हैं. हमने हिन्दुस्तान का क्या बिगाड़ा है? मैं जिस इलाक़े में रहता हूं, वहां पर मेरे साथ बदतमीज़ी हुई थी. मेरे सारे कपड़े निकाल दिए गए थे. तभी मैंने नौकरी छोड़ दी. हम आपसे बिहार, असम, पंजाब नहीं मांगते. हम आपसे जम्मू-कश्मीर मांगते हैं, जो हमारा हक है. सिविल सोसाइटी को यहां पर काम करने की ज़रूरत नहीं है. दिल्ली में काम करने की ज़रूरत है. आप लेफ्ट पार्टी से लेकर बाक़ी दलों को कह दीजिए कि हम लोग जनमत संग्रह चाहते हैं.

लेबनान में किसने किया. इज़राइल में किसने किया. इराक़ और इरान को किसने लड़ाया. पाकिस्तान को गालियां देने वालों से पूछना चाहूंगा कि अमेरिका की क्या भूमिका है इस सब में? पाकिस्तान को देश क्यों बनवाया. उसको तोड़ने के लिए कुरान का तर्जुमा किया जाता था. वाशिंगटन में इंटरप्रेटेशन की जाती थी. वी आर नोट टेररिस्ट्स. अख़लाक़ को मारा हिन्दुस्तान ने. सवाल ये नहीं है कि अख़लाक़ को क्यों मारा गया? उसके जड़ में भी बीफ था. आज ट्रिपल तलाक़ का मसला है, इस पर भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? इट इज नॉट सो इज़ी. आप इसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं. हम इसे क्या समझें. यह मोदी जी का हिन्दुस्तान है. गांधी का हिन्दुस्तान नहीं है.

आज जो हिन्दुस्तान की जम्हूरियत है, उसकी क्या हालत है. हाल में एक तक़रीर में एंथम गाया गया तो एक विकलांग की पिटाई की गई. जब एंथम पढ़ा गया तो वह उठ नहीं पाया बेचारा. कहा गया कि तुम उठे क्यों नहीं? मैं कहता हूं कि यदि यही सिलसिला रहा तो दस साल के बाद जिस तरह से आज पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों की हालत हुई है, वही हालत हिन्दुओं का पूरे इंडिया में होगा. मुसलमानों का ये हश्र हो गया है कि शाहरुख़ ख़ान को भी एयरपोर्ट पर जांच के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं. ये जानते हुए भी कि शाहरुख़ ख़ान का मज़हब से कोई दूर का वास्ता नहीं है. यही सोच और हालात आपकी होगी एक दिन.

जब राजनाथ सिंह जी आए थे और बाक़ी लोग. मैं एमएलए था, मैं मिला. मैंने उनसे कहा, ठीक है, अगर आपके पास कोई अच्छा हल है तो दीजिए. बट यू आर कन्फ्यूज्ड. अगर आप कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, हमारा घर तो जला ही है, उससे आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे. नाइन्टीज में मिलिटेंट्स थे. अब आज का जो लड़का है, वो पढ़ता है, उसके बाद मिलिटेंट बनता है. यक़ीन मानिए कि यासीन साहब का बयान बड़ा ज़बरदस्त था. उन्होंने कहा कि आप शुक्र करें कि पाकिस्तान अभी हथियार नहीं भेज रहा है. अगर दो मिनट के लिए वो हथियार का रास्ता खुल जाए तो आज तो दस हज़ार लड़के तैयार हैं बंदूक उठाने के लिए. ■

लेखक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्य हैं.

feedback@chauthiduniya.com

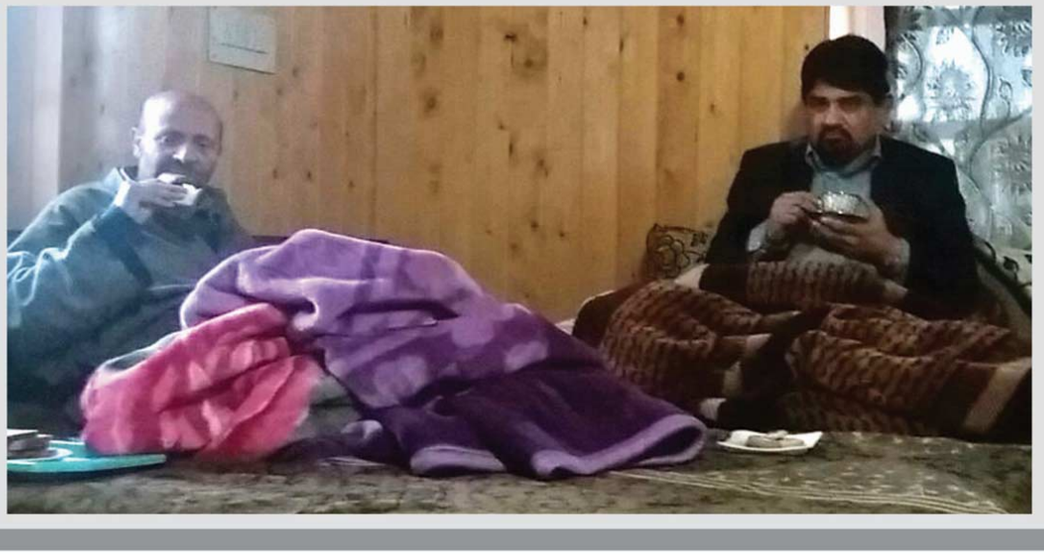

हमसे हमारी राय पूछ ली जाए

शब्बीर शाह

दुनिया में हर कोई कुछ भी बना सकता है, लेकिन कोई आज तक इंसान नहीं बना पाया है, पर इस इंसान को मारने के लिए क्या-क्या नहीं बन रहे हैं. ज़िन्दगी बड़ी मुख्तसर है. पता नहीं कब वापसी का बुलावा आ जाए. क्योंकि यह कैलेंडर नहीं है कि 10-20 वर्ष और. कुछ लोग अगर कुछ करके जाते हैं, तो वो हमेशा अमर रहते हैं और हमेशा ज़िंदा रहते हैं. हालांकि जिनका नकारात्मक किरदार रहता है, उन्हें भी लोग याद करते हैं लेकिन दूसरे तरीक़े से. अपने-अपने धर्म के लिहाज़ से हम समझते हैं कि जन्नत है, जहन्नुम है और सोचते हैं कि हमसे हमारे कामों का हिसाब लिया जाएगा.

साहिर लुधियानवी का एक शेर मुझे याद आता है:-

ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है
ख़ून फिर ख़ून है, टपकेगा तो जम जाएगा...

मैं उन जवान बच्चों का दर्द कैसे बयां करूं जिनकी दुनिया ही बेरंग हो गई, जिनकी आंखें चली गईं. इसमें एक बच्ची इंशा भी घायल हुई. उसे शाह साहब ने एडॉप्ट किया, उसको ढाई महीने एम्स में रखा गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने कहा कि कुछ पहले अगर वह यहां आई होती, तो एक आंख बच जाती, क्योंकि उसका सिर भी फटा हुआ है और उसके दांत भी टूट गए हैं और अभी 300-400 पैलेटगन उसके चेहरे में मौजूद हैं. डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम इन पैलेट्स को निकालेंगे तो इंफेक्शन हो सकता है. अभी बहुत सारी समस्याएं हैं उसे. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जिनकी दुनिया बेरंग हो गई. अब आप दुनिया भी उनकी झोली में डाल दो, तो इसका तो औचित्य ही नहीं बनता. इसके बाद तो महबूबा मुफ्ती का मतलब ही नहीं बनता था सत्ता में रहने का. इसके ऊपर उस प्रकार से आवाज़ उठी ही नहीं, जैसी उठनी चाहिए थी. हर घर में मातम है, मासूम बच्चों की दुनिया बेरंग हो गई है. हमने हर दरवाज़ा खटखटाया और कोशिश की कि इस मसले पर बातचीत की जानी चाहिए. कश्मीर के मसले पर इस्लामाबाद को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते. मेरी आधी ज़िन्दगी तो जेल में गुजरी है. मैं 64वें वर्ष में चल रहा हूं.

मैं यहां एक-दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा. यहां हाईवे हैं, यहां अपराइजिंग बहुत थी. पैलेट गन से हमारे 100 जवान मारे गए. यहां एक आर्मी ट्रक चल रही थी और चलते-चलते वह खाई में गिर गई. उस समय तो लोगों का जुलूस था, वे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन सेना के जवानों को वहां से निकाला. अमरनाथ यात्रा से यात्री वापस आ रहे थे, यात्री जब वहां फंस गए थे, तो यहां के लोगों ने कर्फ्यू को तोड़कर उन्हें वहां से निकाला. एक बार सैलाब यहां आ गया, तो हमने यहां कैंप्स लगाए और अपने घरों में इन्हें रखा. खुद उन्हें रिसीव किया और कहा कि आप जब तक चाहें हमारे घर में रहें.

आपने सुना होगा कि यहां जो बसने वाले लोग उन्हें मुक़ामी ज़ुबान में मकीन कहते हैं. मकीनों को भी मारा और मकानों को भी तोड़ा गया. बाथरूम यहां तक कि वॉशबेसिन तक को तोड़ दिया गया. अगर आपको किसी बच्चे की गिरफ्तारी करनी है तो आप करिए, लेकिन आप उसके घर तक को तबाह कर दें, तो यह कहां का क़ानून है. मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली कभी आऊं. भारत में मैं कई जगहों पर गया हूं. मदर टेरेसा के अंतिम संस्कार में भी गया हूं. हमने कहा कि अगर आपकी बातों में लॉजिक होगा तो हम आपकी बात मानेंगे, अगर हमारी बातों में लॉजिक होगा तो आपको हमारी बात मान लेनी चाहिए. मेरा मानना है कि माइट इज नेवर राइट. जैसे हम बचपन में पढ़ते थे माइट इज राइट. मेरा मानना है कि माइट इज नेवर राइट. बन्दूक़ से लैस साढ़े सात लाख फ़ौजी लेकर आप यहां बैठेंगे, हमारे सर पर हुकूमत करेंगे,

अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री बनने से पहले मुझसे दो ढाई घंटे तक बातचीत की थी. हमने उनसे भी कहा था कि यह जो सब हो रहा उसकी वजह से भी दूरियां बढ़ रही हैं. आप देखिए डिफेंस पर अरबों और ख़रबों रुपये का ख़र्चा किया जाता है. इस मसले की चाबी तो मोदी जी के पास है, क्योंकि उनके पास बहुमत है. मुझे नहीं लगता कि वह यहां के हालात से अच्छी तरह वाक़िफ़ नहीं हैं. हम लोग कोई ग़लत बात नहीं कह रहे हैं.

आख़िर कब तक? हमारे दिल में हिन्दुस्तान के लोगों के लिए इज़्ज़त है. क्योंकि वे भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं. 17 करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान में भी बसते हैं. कभी-कभी हम समझते हैं कि शायद क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्टैंड था, वह बड़ा सही था. यहां जो हम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमने यहां फ्लैक्सिबिलिटी भी दिखाई.

अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री बनने से पहले मुझसे दो-ढाई घंटे तक बातचीत की थी. हमने उनसे भी कहा था कि यह जो सब हो रहा उसकी वजह से भी दूरियां बढ़ रही हैं. आप देखिए डिफेंस पर अरबों-खरबों रुपये का ख़र्चा किया जाता है. इस मसले की चाबी तो मोदी जी के पास है. क्योंकि उनके पास बहुमत है. मुझे नहीं लगता कि वह यहां के हालात से अच्छी तरह वाक़िफ़ नहीं हैं. हम लोग कोई ग़लत बात नहीं कह रहे हैं. हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है. आपने 1994 में करार पास किया, सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया. आपने इतने फ़ैसले करवाए, लेकिन तब भी यह मसला वहीं का वहीं है. यह वाक़ई एक मसला है और जब तक आप एड्रेस न करें, तब तक उपमहाद्वीप में अनिश्चितता रहेगी. दुनिया को भी देखना चाहिए कि दोनों देश परमाणु शक्ति से लैस हैं और दोनों आमने-सामने खड़े हैं. आपको बैठकर बात करनी चाहिए. सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में भी है और यहां मोदी भी बहुमत में हैं, तो वह कोई भी भारत के लिए निर्णय ले सकते हैं.

गांधी जी ने एक भूमिका निभाई, गांधी जी हमेशा के लिए अमर हैं. नेहरू ने एक भूमिका की, उसके बाद भी बहुत सारे प्रधानमंत्री आए. हालांकि हमारा मसला उन्हीं की वजह से लटका हुआ है. यहां पास में ही नीलम चौक है, वहां टेबल पर खड़े होकर नेहरू जी ने वादा किया था कि आपके लोगों से राय ली जाएगी. संसद के अन्दर भी और बाहर भी. हम चाहते हैं कि वही राय हमसे पूछ ली जाए. अगर वाक़ई यह अटूट है तो यह आपके लिए अवसर है, यह सुनहरा मौक़ा है आपके लिए. ■

-लेखक डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन हैं. उन्हें सरकार ने पिछले 29 साल से बार-बार और पिछले 40 महीने से लगातार जेल के भीतर रखा गया है. इस वजह से उन्हें कश्मीर का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है.

feedback@chauthiduniya.com

तीनों पक्षों के बीच बातचीत ज़रूरी

यह आर्टिकल कमल मोरारका के नेतृत्व में दिल्ली से गई सिविल सोसायटी की टीम और कश्मीर की सिविल सोसाएटी के कुछ सदस्यों के बीच हुई बातचीत पर आधारित है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

दिल्ली में सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं है. सरकार कश्मीर की समस्या को केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मानती है. सिन्हा साहब (यशवंत सिन्हा) जैसे लोग यहां आते हैं, बातचीत करते हैं और बयान देकर चले जाते हैं. इससे कुछ नहीं होने वाला है. इनकी बात भी समझने वाला कोई नहीं है. इंटरलोक्यूटर्स (वार्ताकारों जैसे राधा कुमार, एमएम अंसारी और स्वर्गीय दिलीप पडगांवकर) के साथ भी यही हुआ. उन्हें बड़ा अपमानित किया गया, जबकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके रिपोर्ट तैयार की. यह वक्त गुज़ारने वाली बात है. दरअसल यह हम लोगों को थकाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं. यह धारणा कि सिविल सोसाइटी की बात भी कोई समझने और सुनने वाला नहीं है, बड़ा ख़राब संदेश देता है. भारत के बाक़ी लोग कितना समझते हैं कि कश्मीर की समस्या क्यों है. अगर समझते भी हैं तो आप (संतोष भारतीय जी) की वजह से. आपकी तरह और भी पत्रकार हैं, जिन्होंने कॉलम लिखे. इससे और भी लोग समस्या को समझ जाएंगे. मेरा मानना है कि जनता को भी समस्या को गंभीरता से समझना चाहिए. सरकार को बात को इस प्रकार लेना चाहिए कि हमने कुछ वादे किये हैं, जिन्हें निभाना है. नई मुसीबत आई है, वह यह है कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों में कश्मीर को सामने रखकर निर्णय किया जा रहा है. नए आर्मी चीफ़ जो आए हैं वह कश्मीर के एक्सपर्ट कहलाते हैं. इसी प्रकार इंटेलीजेंस चीफ़ हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं. ये भी कश्मीर एक्सपर्ट के तौर पर ही मशहूर हैं. नेवी चीफ़ भी कश्मीर एक्सपर्ट कहलाते हैं. कश्मीर के सिलसिले में मिलिट्री माइंड सेट बनाया है और इसे सिर्फ़ उनकी नज़र से देखा जाता है. आज ही मैं एक अख़बार में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक बाप अपने बेटे को अब रेडीक्लाइज होने से नहीं रोकता है. स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि जो लोग कल तक अपने बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाये रखने के लिए हिदायतें दिया करते थे, आज वे भी उन्हें नहीं रोकते हैं और कहते हैं कि जाओ, जहां जाना चाहते हो, जाओ. जबकि उन्हें मालूम है कि वे अपने बच्चों को खो देंगे. यह कैसा समय आ गया है कि एक बाप अपनी बेटी को कहता है कि जाओ बेटा, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे और न ही तुम पर किसी तरह की बंदिशें लगाएंगे. ठीक है हमारा बच्चा मारा जायेगा, हमारा नुक़सान होगा और हमारी दुकान भी प्रभावित होगी, शायद बंद भी हो जाए. लेकिन जब यह स्थिति जहन में आ जाती है, तो यह ठीक नहीं है क्योंकि फिर तो ख़ुदानाख़्वास्ता ख़ून-ख़राबा ही होगा.

यह समस्या 1947 से ही चली आ रही है और अब तक ज्यों की त्यों है. आज तक कितनी हिंसाएं हुईं, कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, कितनी माओं ने अपने लाल खोए, कितनी महिलाएं बेवा हुईं, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा. 1947 में शांति के साथ रहे. फिर 1953 से 1964 या 1965 तक भी हम शांति के साथ जिए. फिर हमने थोड़े से आर्म्स (हथियार) उठा लिए. इसके बाद हम फिर शांतिप्रिय होने की ओर आए और शांति को तलाश करने लगे. 1990, 1991 और 1992 में आप जैसे कुछ दोस्त आ गए. उन्होंने हमसे कहा कि हम सिविल सोसाइटी की ओर से कुछ करना चाहते हैं, आप लोग हथियार छोड़ दीजिए. हमने यासीन मलिक से कहा कि लेट पीस बी गिवन ए चांस (अमन को एक अवसर दीजिए). उन्होंने हथियार डाल दिए. ये तमाम चीजें रिकॉर्ड में हैं, लेकिन इतना कुछ घटित होकर भी समस्या का कोई हल नहीं निकलता है और समस्या किसी अंजाम तक नहीं पहुंचती है. अगर वह इस भ्रम में हैं कि कश्मीरियों को क्रश करने से यह समस्या हल हो जाएगी तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी ग़लतफहमी है. आज से लगभग 900 वर्ष पूर्व (12वीं सदी में) पंडित कल्हण ने अपनी ऐतिहासिक किताब राजतरंगिनी (बादशाहों की

आज से लगभग 900 वर्ष पूर्व (12वीं सदी में) पंडित कल्हण ने अपनी ऐतिहासिक किताब राजतरंगिनी (बादशाहों की नदी) में लिखा था कि कश्मीरियों को जीत सकते हो तो प्यार और मोहब्बत से जीतो. लिहाज़ा अगर इस समस्या को हम अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और इसका अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होगा.

नदी) में लिखा था कि कश्मीरियों को जीत सकते हो तो प्यार और मोहब्बत से जीतो. लिहाज़ा अगर इस समस्या को हम अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और इसका अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होगा.

दूसरी चीज़ जो मैं अख़बारों में देखता हूं कि हो गया जी हो गया, मसला हल हो गया और अब तो वहां बाज़ार भी खुल रहे हैं. मान लीजिए कि हुर्रियत की ओर से दो दिन या पांच दिन कश्मीर बंद नहीं हुआ, तो इसपर तो इंडियन सिविल सोसाइटी की ओर सकारात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए. लेकिन इसे तो आप हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि अब सब ठीक है. होना तो यह चाहिए कि चार क़दम आप चलें, तो दो क़दम या एक क़दम हम चलें, लेकिन हम यह नहीं देख रहे हैं. सिन्हा साहब या सिविल सोसाइटी के दल के आने से महज़ यह होता है कि आए, बैठे, बात की और चले गए.

यह हक़ीक़त है कि शेख़ अब्दुल्ला चुने गए जनप्रतिनिधि नहीं थे. आप कहते हैं कि हुर्रियत चुनी हुई जनप्रतिनिधि नहीं है. इस पर सवाल यह है कि फिर शेख़ अब्दुल्ला कहां से चुने हुए जनप्रतिनिधि हो गए? उन्होंने किसी चुनाव में भी हिस्सा नहीं लिया. फिर जब विधायिका बनी, जिसने अक्सेशन (विलय) को रेटीफाई किया तो आपने शेख़ अब्दुल्ला को जेल में बिठा दिया. ख़ुलासा यह है कि यहां यही राजनीति चली आ रही है.

कश्मीर में सबसे ख़ास बात यह है कि 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद यहां बैंकों में कोई भी लाइन नहीं लगी. बैंक के अन्दर जाकर लोग लेन-देन करते रहे. यहां कोई टेर मनी नहीं है, कोई ब्लैक मनी नहीं है. जबकि कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए निरर्थक बातें की जाती हैं. अगर किसी के दिमाग में यह है कि यह सब कुछ (आन्दोलन) ख़त्म हो जाएगा तो यह ख्याल सही नहीं है. चलना तो है ही और मंज़िल तक तो पहुंचना ही है. जब तक हम मंज़िल तक पहुंच न जाएं, चलते जाएंगे.

जहां तक यह सवाल है कि क्या जनमत संग्रह इच्छानुसार या आवश्यकतानुसार है, तो मेरा ख्याल है कि जनमत संग्रह ज़रूरी चीज़ है? एक चीज़ जो साबित की जाती है, वह दूसरी चीज़ों को ख़ारिज करके की जाती है. अतीत में कई प्रयास किए गए. शिमला समझौता हुआ, नेहरू-बोगरा एग्रीमेंट हुआ, ताशकंद पैक्ट हुआ, फिर आपके और हमारे (कश्मीरियों) बीच इस मसले पर बात हुई. 1975 में भी एग्रीमेंट हुआ लेकिन मसला हल नहीं हुआ. राजीव-फ़ारूक़ एकॉर्ड हुआ, फिर भी मसला हल नहीं हुआ. हमें इन तमाम अनुभवों से एक सीख लेनी चाहिए और वह यह कि जब तक इस मसले पर तीनों पक्ष एक साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, मसले का हल नहीं होगा. अगर आप कहें कि चलिए देखते हैं, यानि कुछ ले-देकर कुछ कर लें तो हम लोग (कश्मीरी जनता) इस की अनुमति नहीं देंगे.

अब रही जनमत संग्रह की बात, तो आप कहते हैं कि जम्मू के लोग तो इसे नहीं चाहते, वह भारत के साथ हैं. आप कहते हैं कि 90 प्रतिशत हिन्दू भाई नहीं चाहते, तो यह उनका हक़ है. आप कहते हैं कि लेह (लद्दाख) में बुद्धिस्ट हैं, जबकि वहां उनकी आबादी केवल एक लाख 65 हज़ार है.

सबसे अच्छा हल यह है कि आप बैठें, हम बैठें टेबल पर, उनको भी बुलाएं और देखें कि हल क्या निकलता है? संयुक्त राष्ट्र के समझौते के अनुसार जनमत संग्रह को देखना चाहिए. यह एप्रोच सही नहीं है कि जम्मू नहीं चाहता, लेह नहीं चाहता, शिया नहीं चाहता या फलां नहीं चाहता. संयुक्त राष्ट्र में जो पेटीशन भारत की ओर से है, उसमें यही कहा गया है कि हम जनमत संग्रह करवाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

पहचान का संकट ही कश्मीर की समस्या है

यह आर्टिकल कमल मोरारका के नेतृत्व में दिल्ली से गई सिविल सोसाइटी की टीम और कश्मीर के व्यापरियों के बीच हुई बातचीत पर आधारित है. इसमें विभिन्न व्यापारियों द्वारा बताई गई बातों को शामिल किया गया है.

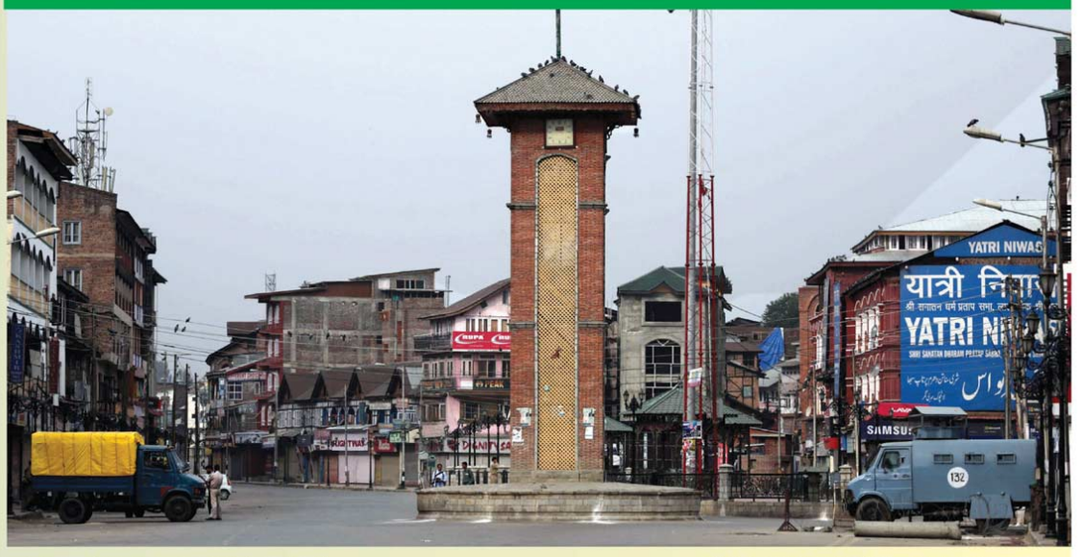

आज कश्मीरियों को इस बात की शिकायत है कि भारत में शायद ही किसी को यह पता हो कि कश्मीर का असल मसला क्या है. भारत का मीडिया जिसे कश्मीर का मसला बताता है, वह कश्मीर का असल मसला है ही नहीं. आमतौर पर बताया जाता है कि कश्मीर का असल मसला आतंकवाद है और कश्मीरियों को पाकिस्तान से पैसा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है. मीडिया को चाहिए कि वह भारतीय नागरिकों को यहां की असल समस्याओं से अवगत कराए और यह बताए कि कश्मीर में उथल-पुथल का असली कारण क्या है. जहां तक कश्मीर की असल समस्या की बात है, तो यहां का असल मसला है आइडेंटिटी क्राइसिस.

कश्मीरी और उनकी समस्याएं क्या हैं

सवाल यह है कि कश्मीरी अपने आपको क्या मानें. भारतीय, ग़ुलाम या डिसप्यूटेड. हम आज भी फ़ख़्र के साथ ख़ुद को भारतीय नहीं कह सकते और कश्मीरी नहीं कह सके, यही है हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस. हालांकि यह छोटा सा मसला है, लेकिन आज तक इस छोटे से मसले का हल नहीं हुआ. आख़िर फ्रीडम का मतलब क्या होता है. दुनिया में हम फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन जब बेसिक लिबर्टी, मूल मानवाधिकार ही ख़त्म हैं, तो इसके बाद सबकुछ ख़त्म हो जाता है. कश्मीरियों के पास अपना कोई अवसर तो है नहीं. अगर पाकिस्तान के इमरान ख़ान क्रिकेटर हैं, तो इस पर कश्मीरी फ़ख़्र करें, इंडिया का कोई प्लेयर है तो उस पर कश्मीरी फ़ख़्र करें, लेकिन कश्मीरियों के पास अपने ऊपर फ़ख़्र करने के लिए कोई मौक़ा नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, जिस पर वे फ़ख़्र कर सकें. इसकी वजह यह है कि कश्मीरियों की अपनी कोई शिनाख़्त नहीं है. कश्मीर की जो समस्याएं हैं, उनको चिन्हित करके हल करने की दिशा में कोशिश होनी चाहिए. अगर घर में कोई मसला होता है, तो घर के बड़े लोग उन ग़लतियों को चिन्हित करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कश्मीर के मसले को कोई आइडेंटीफाई नहीं कर रहा है. बल्कि यह कहा जा रहा है कि कश्मीर का असल मसला मिलिटेंसी है. 1947 में कश्मीरियों ने पाकिस्तान के मुक़ाबले इंडियन आर्मी पर विश्वास किया और पाकिस्तान को भगाने के लिए भारतीय सेना का साथ दिया और कुछ मुद्दों पर शर्तों के साथ भारत सरकार की बात मानी. अगर उन शर्तों पर अमल होता, तो आज जो हम देख रहे हैं वह हमें न देखना पड़ता. कश्मीरियों ने भरोसा करके यह क़ुर्बानी दी थी.

हालांकि 1990 के बाद हालात थोड़े ठीक हुए तो टूरिस्ट्स आने लगे. टूरिस्ट कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. भारत के कोने-कोने से लोग यहां आते हैं. इसके बाद यहां फिल्में बनीं, त्योहारों के मौक़े पर यहां हर धर्म के लोग आते हैं. इनमें हिन्दू, क्रिश्चियन और सिख सभी होते हैं. ये सभी विभिन्न जगहों से आते हैं, लेकिन उनके साथ यहां किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होती. इसके उलट जब कोई क़श्मीरी भारत के किसी हिस्से में जाता है, तो उनके साथ असहनीय व्यवहार किया जाता है. कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की जाती है. आख़िर यह माहौल कैसे बन गया?

कश्मीर को एक मुजरिम बनाकर पेश कर दिया

अतीत में किसी भी कश्मीरी को भारत के किसी भी कोने में कोई दुश्वारी नहीं होती थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं. दरअसल जिन लोगों को मसले के हल के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुना गया, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों, भाजपा के हों या कोई और, इन्हीं लोगों ने कश्मीर मसले को इस हाल तक पहुंचा दिया. आज कश्मीर में आर्मी का रवैया बदल गया है. यह सब कुछ इन चार-पांच सौ लोगों ने ही किया है, जो भारत के सदन तक पहुंचे हैं. ऐसी स्थिति के बनने में आम लोगों की कोई भूमिका नहीं है. इन सियासी लोगों ने अपने सियासी फ़ायदों के लिए, अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए, जो अच्छा लगा वह किया और कश्मीर को एक मुजरिम बनाकर पेश कर दिया. कल तक जो आर्मी हमारी लिबर्टी बर्दाश्त करती थी, वे आज हमारी दो बातें बर्दाश्त नहीं करते हैं. ये तमाम बदलाव इन सियासी लोगों की वजह से हुये हैं. वरना हमारी सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई नहीं है. ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को बताया गया है कि कश्मीरियों से कश्मीर नहीं, उनकी शिनाख़्त मांगो. 1987 से पहले आर्मी किसी कश्मीरी से शिनाख़्त नहीं मांगती थी, लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ कि पंजाब का रहने वाला एक आर्मी मैन कश्मीर में आकर कश्मीरी नागरिकों से उनकी पहचान का सबूत मांगने लगे. यक़ीनन यह मानवीय संकट है. अब सवाल यह है कि आख़िर यह किस प्रकार से ख़त्म होगा. यह सवाल परेशान करने वाला है. क्या यह ऑटोनोमी देने से ख़त्म होगा या आज़ादी देने से ख़त्म होगा?

2008 में हमने देखा है, 30-35 वर्ष के जवान जुलूस में बिल्कुल आगे होते थे. फिर 2010 में कॉलेजों में पढ़ने वाले 22-25 वर्ष के युवा जुलूस में शामिल होने लगे. अब 2016 में यह दिख रहा कि 10-12 साल के बच्चे भी जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं. तो नस्ल दर नस्ल ये चीजें हस्तांतरित होती जा रही हैं. यह तो एक्सपोजर की बात है, जो यहां के बच्चों को मिला है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने असंवेदनशील हो गये हैं कि वे रियलिटी देखना और हक़ीकत सुनना ही नहीं चाहते. भारत के 31 प्रतिशत लोगों ने मोदी को वोट दिया है. यानी देश के 31 प्रतिशत लोग मोदी के समर्थक हैं. कुछ भक्त भी हैं, जो कहते हैं कि नोटबंदी की वजह से यहां की हड़ताल ख़त्म हुई है.

यह भी कहा जाता है कि हम लोग भारत के लोगों को एड्रेस करने में तेज़ी नहीं दिखाते हैं. यह तो बिल्कुल ग़लत है. आख़िर आप लोग (कमल मोरारका जी और संतोष भारतीय जी) यहां आए हैं हमारी बात सुनने के लिए, तो हम आपसे बात कर रहे हैं. ताकि हमारा संदेश आपके ज़रिये भारत के आम लोगों तक पहुंचे और वे सच्चाई को समझ सकें. हम अपने भारतीय भाइयों को यह बताना चाहते हैं कि हमारा असल मसला क्या है. यहां की जो मूल पार्टी है वह इस स्थिति को रोक सकती है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि किसी भी पार्टी से संबंध रखने वाले लोग सियासत कर के यहां पर भारत सरकार का एजेंडा चलाने की कोशिश करने लगते हैं. यह सब वह अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं. आज जो पार्टी सत्ता में है, उस पर से लोगों का भरोसा इतना उठ गया है कि उनमें से किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह लोगों को सड़कों पर आने से रोक सके.

यहां की सियासत दिल्ली तक सही बात नहीं पहुंचाती

हम यह कहते हैं कि आप कश्मीर की समस्या को भारतीय या क़श्मीरी की हैसियत से मत देखिए. आप इस मसले को इंसानी नज़रिए से देखिए. आज से 60 वर्ष पूर्व एक पाकिस्तानी भी ख़ुद को इंडियन कहता था और एक बांग्लादेशी भी ख़ुद को इंडियन कहता था. क्योंकि सबने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी. यह इतिहास की एक कड़वी सच्चाई है कि अब्दुल गफ्फ़ार या सीताराम एक साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, लेकिन बाद के दिनों में धर्म के नाम पर बंट गए कि आप मुसलमान हैं और हम हिन्दू. जब पंजाब का विभाजन हुआ उस समय गुरदासपुर में काफ़ी मुसलमान रहते थे, उनको तो पाकिस्तान में चला जाना चाहिए था, लेकिन वे नहीं गए. उस वक्त किसी ने भी यह नहीं कहा कि कराची में सिंधी हिन्दू रहते हैं या राजस्थान में क्रिश्चियन या गुजरात में हिन्दू भी रहते हैं. तब केवल एक चीज देखी गई कि मेजोरिटी किसकी है. वहां माइनोरिटी को एक विकल्प दे दिया गया कि आप माइग्रेट कर सकते हैं.

कश्मीरी लड़कों को पाकिस्तान का समर्थक कहा जाता है. हम यह दावा नहीं करते हैं कि यहां पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं, लेकिन वे बहुत थोड़ी संख्या में हैं. यहां बहुलता पाकिस्तान समर्थकों की नहीं है. बहुलता की आवाज़ क़श्मीर के हक़ के लिए है. यहां धर्म को बुनियाद नहीं बनाया जाता है. 1947 में यहां बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में पंडित थे. इन पंडितों के साथ क्या कभी बदसलूकी हुई? लेकिन यहां जो भारतीय सेना है, वह ये समझती है कि वह मुसलमानों से लड़ रही है. इसीलिए कश्मीरियों के साथ उनका रवैया ग़लत होता है. उन्हें ऐसा करने की ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन जब यही स्थिति भारत के अन्य राज्यों में होती है, तो वहां यह रवैया नहीं अपनाया जाता है. पंजाब में ऐसा नहीं किया जाता है, जबकि वहां कई अस्पतालों को जला दिया गया. ख़ालिस्तान की मांग में जो भी मरा, उसे मिलिटेंट ने मारा, लेकिन यहां पाकिस्तान समर्थक होने के कारण बुरहान वानी को मारा गया. हम मानते हैं कि वह नौजवान पाकिस्तान की बात करता था,

लेकिन ज़रा सोचिए कि जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, वे आख़िर किस कारण करते हैं, इस बात को देखना चाहिए. भारत यहां लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है. इस कारण कश्मीरी पाकिस्तान की बात करते हैं. यहां हिन्दूओं को सिखाया जाता है कि आप जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों से लड़ो. 2008 में तो इन्होंने हमारी नाकेबंदी तक कर दी थी. यहां बौद्धों को हमारे ख़िलाफ़ उकसाया जाता है. यह आरोप लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर में पांच-पांच सौ रुपये देता है. यहां फ़र्ज़ी एनकाउंटर पर पुलिस को तरक्क़ी मिलती है. ऐसे किरदार की वजह से ही भारत ने कश्मीर में अपना विश्वास खोया है. यहां की सियासत दिल्ली तक सही बात पहुंचाती, तो शायद कभी कोई ऐसी सरकार केंद्र में आती जो कश्मीर के मसले के लिए गंभीर होती और कोई हल निकल आता. लेकिन यहां की सियासत अपने फ़ायदे के लिए दिल्ली को असली हालात से अवगत ही नहीं कराती है.

बिजली, पानी और सड़क सभी की मूल आवश्यकता होती है. इसी बुनियाद पर यहां की पार्टियों को कुछ वोट मिले, लेकिन आज ये उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं. ये इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और कहते हैं कि हमें बिजली, पानी और सड़क के नाम पर 60 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सच्चाई यह है कि इनके पास जनता का कोई मैंडेट है ही नहीं. कश्मीर में इस समय जो हालात हैं, उसे बदलने के लिए भारत के लोगों में, सिविल सोसाइटी में जागरूकता पैदा करनी होगी. इससे हमारा रास्ता आसान हो सकता है. इस सिलसिले में मीडिया सकारात्मक भूमिका निभाकर इस स्थिति का ख़ात्मा कर सकता है. कश्मीर मसले पर बिना शर्त बातचीत होनी चाहिए. यही एक रास्ता है कश्मीरियों को इस दलदल से निकालने का. आप आइए, हमारी लीडरशिप से बात कीजिए. इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो सेमिनार भी किया जा सकता है, लेकिन अब तक तो देखा गया है कि जो भी बातचीत हुई है, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया. इस सिलसिले में निष्पक्ष नेता, सिविल सोसाइटीज़ के लोगों जिनमें देवगौड़ा, येचुरी और ओवैसी जैसे लोग शामिल हैं को बुलाकर सेमिनार कराया जा सकता है.■

कश्मीरी लड़कों को पाकिस्तान का समर्थक कहा जाता है. हम यह दावा नहीं करते हैं कि यहां पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं, लेकिन वे बहुत थोड़ी संख्या में हैं. यहां बहुलता पाकिस्तान समर्थकों की नहीं है. बहुलता की आवाज़ कश्मीर के हक़ के लिए है. यहां धर्म को बुनियाद नहीं बनाया जाता है. 1947 में यहां बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में पंडित थे. इन पंडितों के साथ क्या कभी बदसलूकी हुई? लेकिन यहां जो भारतीय सेना है, वह ये समझती है कि वह मुसलमानों से लड़ रही है. इसीलिए उनका रवैया कश्मीरियों के साथ गलत होता है. उन्हें ऐसा करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि यही स्थिति भारत के अन्य राज्यों में होती है, तो वहां यह रवैया नहीं अपनाया जाता है.

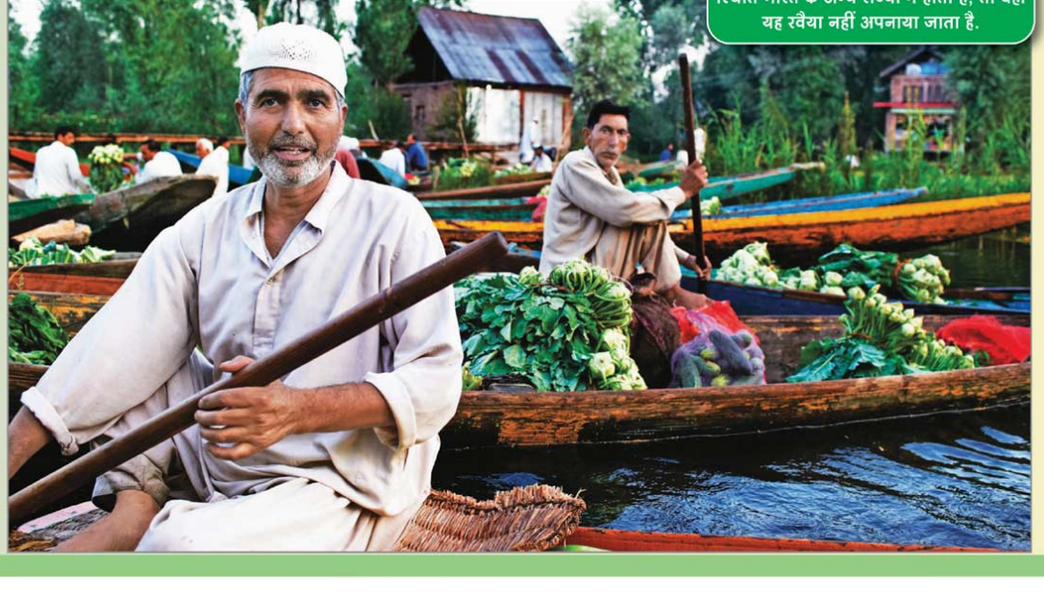

feedback@chauthiduniya.com

हमें हमारा कश्मीर वापस लौटा दें

यह आर्टिकल कमल मोरारका के नेतृत्व में दिल्ली से गई सिविल सोसाइटी की टीम और कश्मीर के छात्रों के बीच हुई बातचीत पर आधारित है.

दरअसल, हमें शिकवा है दोस्तों से और दुश्मनों से भी. हमें अपनों ने भी लूटा और ग़ैरों ने भी लूटा. कश्मीर के लोग बेचारे इनोसेंट पीपल हैं. इनको अभी आप कहेंगे कि कल आप हड़ताल छोड़ दो, हम ये करेंगे आपकी आज़ादी के लिए, तो ये पांव छुएंगे आपके. उन दिनों नेहरू जी डल झील की सैर कर रहे थे. लोगों ने उनका विरोध किया. एक ने अपना कपड़ा उठा कर पेट दिखाया, कहा हमें आपका चावल नहीं, आजादी चाहिए. शेख़ अब्दुल्ला ने मिसगाइड किया नेहरू जी को. शेख़ अब्दुल्ला ने कहा कि ये कह रहे हैं कि हमें चावल चाहिए, भूखे पेट हैं, तभी पेट दिखा रहे हैं. असल में बुनियादी तौर पर कश्मीर के प्रॉब्लम क्रिएटर मिस्टर अब्दुल्ला ही हैं. 1989 से हमने कितनी मौतें देखी. कितनों की इज़्ज़त लूटीं. कश्मीर का समाधान यह है कि टेबल पर आना चाहिए, बातचीत के लिए. कश्मीर के दो-तीन स्टेक होल्डर्स है, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी. ये सब एक टेबल पर आएं. बैठे, बातचीत करें.

गरीबी हमारी पहली समस्या है

हम तो कहते हैं कि इंडिया भी आए यहां पर, हमें अपनाए और पाकिस्तान भी अपनाए. कश्मीर को संवारे सजाए. हम अफ़गानिस्तान के लोग नहीं हैं, चेचेन्या वाले नहीं हैं, ये कश्मीर है, ये जन्नत है. इस जन्नत को आग लगा दी गई. कोई बच्ची अंधी हो गई. किसी ने बाप खोया, किसी ने बेटा. बेटे की अर्थी बाप को ही उठानी पड़ती है. 10 लाख आर्मी यहां पर बैठी हुई है. जैसे

> यहां बहुत दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने क़लम से जंग लड़ी, जिन्होंने आइडियोलॉजी से लड़ाई लड़ी, ख्यालात से लड़ाई लड़ी, किसी ने हथियार से भी लड़ाई लड़ी. लेकिन जो लड़के हथियार उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? क्योंकि, वो मजबूरी में ऐसा करते हैं. हालात से मजबूर हो कर फिर इस बात पर डट जाते हैं कि अब तो मर के जाना है या मार के जाना है.

कोई वर्ल्ड वार चल रहा हो. अगर, 10 लाख आर्मी के बदले एक लाख आर्मी रखते तो नौ लाख आर्मी पर जितना ख़र्च आता है, वो यहां के यूथ पर ख़र्च होता. इससे बेरोजगारी ख़त्म होती. हमारे फ़ारूक़ अब्दुल्ला साहब हैं, इन्होंने कश्मीर को क्या दिया है. उनको क्या है? दुख-दर्द तो हम लोगों को है. शाम के वक्त अंधेरा उनके घर में नहीं होता, कश्मीरियों के घर में अंधेरा होता है. बिजली फीस तो गरीबों को देना पड़ता है, फ़ारूक़ अब्दुल्ला को नहीं. यहां की पहली क्राइसिस गरीबी है.

साढ़े तीन लाख ग्रेजुएट युवा यहां पर बेक़ार बैठे हुए हैं. यहां पर 75 हज़ार पोस्टग्रेजुएट हैं, जो बेक़ार बैठे हुए हैं. ये प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं. हम इंडिया की बात नहीं, कश्मीर की बात कर रहे हैं. अगर यहां पर तीन हज़ार करोड़ का बजट आता है, तो कोई पूछने वाला नहीं है. कोई क्यों नहीं पूछता है? अगर मैं फ़ारूक़ अब्दुल्ला का क्लास लूं, तो कल को वे कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाने वाले लोग हैं. यही हमारी दुखती रग है. मुफ्ती से सवाल करेंगे तो हमें कहेंगे कि हमें आज़ादी चाहिए. कल तक महबूबा मुफ्ती कह रहीं थी कि ये हमारे बच्चे हैं. जब गोली चली तो उसने भाषा बदल ली.

हमारे साथ ज्यादती होती है

यहां पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. यहां पर रॉ भी स्टेक होल्डर है, अपनी मर्ज़ी से किसी को कुर्सी पर बिठाते हैं. कहने का मतलब कि जो उनकी गुलामी करे. यहां की गवर्नेंस देखिए. क्या ये डेमोक्रेसी है? एक बूढ़ा आदमी है, बीमार है, पेसमेकर लगा हुआ है, गिलानी साहब से इंडियन गवर्नमेंट क्यों इतना डरती है? वो कौन सा रिवॉल्यूशन ले आएंगे. अरे, भाई छोड़ दो उनको, नमाज़ पढ़ने दो. एक बंदे को आज़ादी नहीं दे सकते, तो हज़ार बंदों को कहां से आज़ादी देंगे? आज उनको दस वर्ष हो गए घर में नज़रबंद हुए और आज उनकी मकान को ही छावनी बना दिया गया है.

आसिया अंद्राबी, उसका बेटा हॉस्पिटल में है. ख़ुद कोर्ट ने कहा कि उसको छोड़ दो. अभी वो जेल से बाहर ही था कि फिर से उसको अरेस्ट कर लिया गया. यहां ये हालात हैं. ये एक दर्द नहीं है यहां पर, दर्द का अंबार है. आप सिटी में देखते हैं, आप गांव में जाइए, देखिए, कई ऐसे लोग हैं, जिनके बेटों को आज से बीस साल पहले ग़ायब कर दिया गया. 10 साल की बच्चियों का रेप हुआ. दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले अपनाना पड़ता है. गुलामी और आज़ादी को छोड़ दीजिए, पहले मानवता की बात कीजिए. बाद में देखेंगे की गुलाम कौन है, आज़ाद कौन है. यहां का सीएम भी आज़ाद नहीं है, वो भी गुलाम है. उसको डिक्टेशन लेनी पड़ती है पहले. सौ बार फोन उठाना पड़ता है.

यहां जो स्टेटस दिया गया था, उसको ख़त्म कैसे किया गया? इंसान को लगता है कि हमारे साथ ज्यादती तो पहले से ही करते आए हैं. किसी की भी सरकार हो, सबका दख़ल रहता है. ज्यादा से ज्यादा दख़ल इंटेलिजेंस की रहती है. किसको क्या करना है, किससे क्या कराना है, सब में दख़ल होता है. आर्मी वाला मुझे बोलेगा कि यहां वोट डालने जाओगे, किसको डालोगे, फलाने को डालना. एक इंसान को कैसा फील होगा तब? अगर हमारे साथ सेना वाले कोई ज्यादती करते हैं और अगर हम एफआईआर दर्ज कराने जाए तो वह भी नहीं दर्ज किया जाता. छोटे-छोटे बच्चों को भी ज़लील किया जाता है. यदि मैं छोटे बच्चे के साथ बाज़ार निकलता हूं, तो मिलिट्री वाला गंदी-गंदी बातें बोलता है. ऐसे में, अगर मुझे मौक़ा मिले, तो मैं भी मिलीटेंट बनूंगा. गन उठाऊंगा, मारूंगा या मरूंगा, ख़त्म कहानी.

यासिर क़ादरी जैसे यहां पर कितने लोग होंगे. सोफिया, निलोफर, आसिया का गैंग रेप केस

> यहां पर लोग लीडर बनते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर और आज़ादी के नाम पर. लेकिन जब वो गद्दी पर बैठते हैं, तब फिर राजनाथ सिंह को गले लगाते हैं. हमारी कमज़ोरी यही आज़ादी है. शेख़ अब्दुल्ला ने राज किया, फिर फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने राज किया, उमर अब्दुल्ला ने राज किया, सिर्फ इसी चीज़ पर. वाजपेयी जी ही एक लीडर हैं जिन्होंने कश्मीर का दर्द समझा.

का इंटरनेशनलाइज़ेशन हो गया. लेकिन कुछ नहीं हुआ. आर्मी वाला आएगा, आपको दो-तीन थप्पड़ मारेगा, डंडा मारेगा और चला जाएगा. कश्मीर को विक्टिमाइज़ किया जाता है, बर्बरिज़्म चल रहा है. यदि पुलिस स्टेशन वाला किसी को ऐसे उठा कर लाया तो वो चार हज़ार, पांच हज़ार, दस हज़ार, तीस हज़ार की बोली लगा कर उनको छोड़ते हैं. क्या इस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई स्ट्रिक्टनेस दिखा सकते हैं? यहां पर जो पुलिस है, वो यहां क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है. पुलिस लड़कों को उठा कर लाती है, पीटती है, दो-तीन बाद फिर 10-20-30 हजार दो तो छोड़ देती है. अब जिस बंदे को तीस हज़ार के लिए विक्टिमाइज किया गया, उसी का नाम बुरहान था.

यहां बहुत दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने क़लम से जंग लड़ी, जिन्होंने आइडियोलॉजी से लड़ाई लड़ी, ख्यालात से लड़ाई लड़ी, किसी ने हथियार से भी लड़ाई लड़ी. लेकिन जो लड़के हथियार उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? क्योंकि, वो मजबूरी में ऐसा करते है. हालात से मजबूर हो कर फिर इस बात पर डट जाते हैं कि अब तो मर के जाना है या मार कर जाना है. कुछ लोगों ने कहा कि गिलानी साहब के घर गये, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला. एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक लीडर दरवाज़ा खोले तो उसको भी ख़तरा है. गिलानी साहब ने हड़ताल के समय एक स्टेटमेंट दिया था कि एंबुलेंस पर पत्थर मत फेंको, लड़के उनके घर चले गए. उन्होंने सारे न्यूज़ चैनलों को वापस फोन करके बोला कि ये वाली लाइन हटा दो. क्योंकि उनकी भी जान ख़तरे में पड़ गयी. लड़कों ने बोला कि हम मरते हैं और आप बोलते हैं कि मत मारो. ये पुलिस वालों ने एंबुलेंस के साथ क्या किया. किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं. कोई सस्पेंड नहीं हुआ आज तक. कोई टर्मिनेट नहीं हुआ आज तक. पुलिस यहां पर लोगों को विक्टमाइज़ करती है, लोगों से पैसा लेते हैं, टॉर्चर करते हैं. यही सब बातें लोगों को एक्स्ट्रीमिज्म की ओर ले जाता है. यहां पर सबसे ज्यादा मिलिट्री जोन है, गवर्नेंस यहां पर तो बिल्कुल ज़ीरो है. दो दिन से हमारे घर में बिजली नहीं है. वैसे गवर्नेंस चलाएं भी क्या? महबूबा जी भी क्या बोलेंगी? उनके पास अथॉरिटी ही क्या है?

एक बुरहान के मरने से 1000 बुरहान पैदा हो गए

मस्जिद में नमाज़ होती है. नमाज़ पढ़ के लोग निकलते हैं. 50-60 हज़ार लोग होते हैं, उनमें से दस हज़ार लोग बोल देते है कि हमें चाहिए आज़ादी, कोई कहता है कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद. यहां पर जब शेख़ अब्दुल्ला एलेक्शन लड़ते थे, तो उनके हाथ में पाकिस्तान का नमकीन होता था. वो लोगों को दिखाते थे. लोग उनको वोट डालते थे. जब कोई मिलिटेंट मरता था, तो महबूबा मुफ्ती उसकी मां को आंख के आंसू पोंछती थीं. यहां पर लोग लीडर बनते हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान के नाम पर और आज़ादी के नाम पर. जब वो गद्दी पर बैठते हैं, तब फिर राजनाथ सिंह को गले लगाते हैं. हमारी कमज़ोरी यही आज़ादी है. शेख़ अब्दुल्ला ने राज किया, फिर फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने राज किया, उमर अब्दुल्ला ने राज किया, सिर्फ़ इसी चीज़ पर. वाजपेयी जी ही एक लीडर हैं जिन्होंने कश्मीर का दर्द समझा. कुछ हद तक समझा कि कश्मीरियों की बीमारी क्या है? ये कोई छोटी बीमारी नहीं है. 1931 से ही ये बीमारी है. 1931 में इंडिया भी आज़ाद नहीं था, वो भी गुलाम था. लेकिन, हम आज़ाद लोग थे.

मरना तो यहां पर हर किसी को है. यहां पर कोई जवान नहीं बचेगा. मैं देखता हूं कि जो हमारे यूथ हैं, वे कमप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जब तक कि कोई स्टेबल फ़ैसला न हो. एक बुरहान के मरने से 1000 बुरहान पैदा हो गए यहां पर. आपने देखा कि एक बुरहान के पीछे तीन लाख का जुलूस जनाज़ा पढ़ने के लिए निकला. अब कम्पिटिशन इसी फील्ड में है. अब सब गिलानी बनना चाहते हैं यहां. एक इंसान की चाहत क्या होती है? जब मरो तो लोग अच्छा बोले.

यहां के पत्रकारों से पूछिए कि वो बेचारा लिख नहीं सकता है, उसका क़लम बेक़ार पड़ा है. उसको पता है कि अगर मेरे क़लम ने कुछ ज़हर उगला तो सज़ा-ए-मौत होगी. किसी के क़लम में इतनी ताक़त नहीं है कि वो सच लिखे. इनको पहले पूछना पड़ता है कि क्या मुझे इजाज़त है?

आपको जितने भी कश्मीरी मिलेंगे, वो यही कहेंगे कि हमें न हिंदुस्तान चाहिए, न पाकिस्तान चाहिए, हमें हमारा कश्मीर वापस लौटा दें. ये ज़ख्मी कश्मीर हमें वापस दे दो. हमारे साथ हमदर्दी करो. हमारे बच्चे बंद हैं, हमारे बच्चों को गोलियां लगी हैं, हम और कुछ नहीं मांगते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

टीम इंडियाः जूनियर विश्व कप हॉकी का सरताज

फाइनल में बेल्जियम को हरा कर भारत बना सिरमौर

सैयद मोहम्मद अब्बास

बेहद शानदार खेल के लिए राष्ट्रीय खेल हॉकी एक बार फिर सुर्खियों में है. भारत की जूनियर टीम ने विश्व कप में गजब की हॉकी का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है. देश में एक बार फिर हॉकी का परचम बुलंद हो रहा है. लगातार नाकामी और विवाद की भेंट चढ़ने वाली भारतीय हॉकी एक बार फिर विश्व खेल पटल पर छा गई है. सीनियर भले ही अभी जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हों, लेकिन जूनियरों की तूती बोल रही है. मैदान पर एक बार फिर भारतीय हॉकी की हनक स्थापित हो रही है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनउ में हॉकी का जुनून चरम पर था. भारतीय टीम ने जूनियर विश्व कप में यूरोप की सबसे ताकतवर टीम माने जाने वाली बेल्जियम को 2-1 से पराजित कर 15 साल बाद इस खिताब को अपने नाम किया है. इतिहास के पन्नों के सहारे भारतीय हॉकी अपनी सुनहरी यादों के बल जी रही थी, लेकिन 18 दिसम्बर 2016 को लखनऊ के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुई जीत ने एक बार फिर भारतीय हॉकी में नई जान फुंक दी है. यह जीत भारतीय हॉकी की तस्वीर बदल सकती है.

टीम के कई युवा खिलाड़ियों ने अपने जोरदार प्रदर्शन की बदौलत सीनियर टीम में अपना मजबूत दावा ठोक दिया है. उनमें हरमनप्रीत, मनदीप, अरमान जैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों के नाम प्रमुख हैं, जो आने वाले दिनों में भारतीय हॉकी को नई पहचान दिला सकते हैं. पूरे विश्व कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने गजब की हॉकी का प्रदर्शन किया. आलम तो यह रहा कि विदेशी टीमें भारत के कहर से बचने की फिराक में दिखीं. भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी बेहतरीन हॉकी की बदौलत हर जंग को बेहद आसान फतह में बदल दिया. टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस का भी कोई जवाब नहीं था. दूसरी ओर मैदान पर खिलाड़ियों का आपसी तालमेल भी गजब का देखा गया. बेल्जियम जैसी मजबूत टीम को आसानी से काबू करना भी एक बड़ी बात है.

भारतीय खिलाड़ियों का विरोधी टीमों पर शुरुआती समय में ही धावा बोल देना, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला. 70 और 80 के दशक की बात कुछ और थी, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा बहुत कम देखा गया, जब भारतीय खिलाड़ी लगातार मैदान पर फुर्तीले और पासिंग के मामले में अव्वल दिखते रहे. हरमनप्रीत जैसे खिलाड़ी इसका सटीक उदाहरण हैं. यह जीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि भारत ने इससे पूर्व साल 2001 में होबार्ट में विश्व कप जीता था.

टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत और बेल्जियम दोनों ही टीमों को मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन भारत ने अपने पराक्रमी खेल की बदौलत बेल्जियम के सपनों पर ग्रहण लगा दिया. लखनऊ का मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम मैच शुरू होने से पहले ही खचाखच भर गया था. पूरा स्टेडियम भारतीय तिरंगे से लहरा रहा था. हर खेल प्रेमी की जुबान पर भारत माता की जय का नारा गूंज रहा था. मैच के पहले हाफ में ही टीम इंडिया ने बेल्जियम पर हमला करना शुरू कर दिया. मैदान पर तेजी से भारतीय खिलाड़ी बेल्जियम को खुली चुनौती देते दिखे. शुरुआती पांच मिनट के खेल में ही यह दिखने लगा कि भारत इस मुकाबले को एकतरफा करने की फिराक में है. भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती मिनटों में दो शानदार अटैक किए लेकिन गोल करने में कामयाबी नहीं मिली. मैच के आठवें मिनट में मिडफील्ड की बदौलत संता सिंह ने स्कूब के सहारे गेंद को आगे बढ़ाया जिसे गुरजंत सिंह ने अपनी शानदार रिवर्स हिट के सहारे गोल में बदलने में कामयाबी पाई. इस तरह से भारत ने पहला गोल दागकर बेल्जियम का मनोबल हिला दिया. पहले ही हाफ के 22वें मिनट में भारतीय टीम के नीलकांता सिंह ने बेहद चतुराई से गेंद सिमरजीत सिंह की तरफ बढ़ाई और इसके बाद सिमरजीत सिंह ने रिवर्स हिट से गोल दागकर भारतीय टीम को 2-0 की अहम बढ़त दिला दी. इस गोल के बाद तो पूरे स्टेडियम में भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे. इसके बाद बेल्जियम की टीम ने भारत पर दबाव बनाने का अथक प्रयास किया, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी बेहतरीन रक्षात्मक रणनीति का भी परिचय दिया. आखिरी वक्त पर जब मैच समाप्त होने में महज कुछ पल शेष रह गए थे, तभी बेल्जियम को एक पेनाल्टी कार्नर मिला, लेकिन उसे वे चूक गए. तभी उन्हें दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर भी मिल गया. समय के मुताबिक मैच तब तक खत्म हो चुका था, लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर का फरमान रेफरी जारी कर चुके थे. वही फरमान बेल्जियम टीम की इज्जत बचा गया. पेनाल्टी कॉर्नर से बेल्जियम एक गोल करने में कामयाब रहा. बेल्जियम के फेब्रिस वान बोकरिज ने पेनाल्टी कॉर्नर का गोल किया. इस तरह भारत 2-0 के बजाय 2-1 से विजयी घोषित हुआ.

भारतीय टीम ने क्वार्टरफाइनल में स्पेन जैसी टीम को भी इसी तरह चित किया था.

> टीम के कई युवा खिलाड़ियों ने अपने जोरदार प्रदर्शन की बदौलत सीनियर टीम में अपना मजबूत दावा ठोक दिया है. उनमें हरमनप्रीत, मनदीप, अरमान जैसे प्रतिभावान खिलाड़ियों के नाम प्रमुख हैं, जो आने वाले दिनों में भारतीय हॉकी को नई पहचान दिला सकते हैं. पूरे विश्व कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने गजब की हॉकी का प्रदर्शन किया. आलम तो यह रहा कि विदेशी टीमें भारत के कहर से बचने की फिराक में दिखीं. भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी बेहतरीन हॉकी की बदौलत हर जंग को बेहद आसान फतह में बदल दिया.

सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई कंगारुओं को बेहाल करते हुए पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 के अंतर से पटका. इतना ही नहीं लीग मैचों में भी टीम इंडिया का प्रदर्शन तारीफ के काबिल रहा. लीग मैचों में भारत ने कनाडा को 4-0 से हराया. इसके बाद उसने इंग्लैंड को 5-3 और दक्षिण अफ्रीक को 2-1 से हराकर अपनी

दावेदारी मजबूत की. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम की चुनौती को भी आसानी से निपटा दिया. जबकि सेमीफाइनल का मुकाबला आसान नहीं था. दोनों टीमों के खेल में एक बात सामान्य तौर पर दिख रही थी, वह थी जीत की भूख. निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 के बराबर रहा लेकिन पेनाल्टी शूट आउट में भारत ने कंगारुओं को 4-2 से पछाड़ते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया. पेनाल्टीशूट आउट में गोलची दहिया का खास योगदान रहा. दहिया ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू बर्ड और शार्प लैचलान के गोल के प्रयासों को नाकाम कर दिया. फिर तो फाइनल की राह आसान हो गई. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया. दरअसल 1997 में विश्व कप खिताबी जंग में भारत को कंगारुओं से ही हार मिली थी.

भारतीय जूनियर हॉकी टीम को विश्व विजेता बनाने में कोच हरेंद्र सिंह का खास योगदान रहा. यह भी एक संयोग ही है कि साल 2005 में स्पेन से हार कर चौथे नंबर पर रहने वाली भारतीय टीम के कोच हरेंद्र सिंह ही थे, लेकिन इस बार उन्होंने चक दे इंडिया के शाहरुख की तरह टीम को नई पहचान दिला दी. कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय हॉकी के लिए यह जीत बेहद खास है, क्योंकि यह जीत हॉकी के शानदार भविष्य के प्रति उम्मीदें दिखा रही है.■

यूपी में दोबारा मिल रही हॉकी को पहचान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जूनियर विश्व कप हॉकी को लेकर प्रशंसकों में गजब का उत्साह दिखा. खुद विदेशी टीमों ने भी कहा कि हॉकी के प्रति ऐसा उत्साह उन्हें कहीं और देखने को नहीं मिलता. विदेश से आई हॉकी टीमों के साथ-साथ भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का कहना था कि क्रिकेट मैच में दिखने वाली भीड़ का मिथक भी लखनऊ के हॉकी प्रेमियों ने तोड़ दिया. यह हॉकी के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है. खिताबी जंग के लिए भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्टेडियम में मौजूद थे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम पहुंच गए थे और राष्ट्रगान से पहले दोनों टीम के खिलाड़ियों से मैदान पर जाकर मिले. उनके अलावा एफआईएच अध्यक्ष लिएंड्रो नेग्रे, भावी अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह भी वीआईपी गैलरी में मौजूद थे. अखिलेश ने इस मौके पर कहा कि यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजित हुआ. अखिलेश ने दर्शकों की भी सराहना की और कहा कि जितना

- लखनऊ की मेजबानी में हुआ विश्व कप
- हॉकी के प्रति बढ़ रहा दर्शकों का रुझान

जोश खिलाड़ियों में है उतना ही लखनउ के दर्शकों में भी है. भारतीय टीम के ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को फैंस च्वाइस प्लेयर पुरस्कार से नवाजा गया. हरमनप्रीत ने लीग चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करके भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. न्यूजीलैंड टीम को फेयरप्ले पुरस्कार मिला. विश्व कप में भाग लेने वाली 16 टीमों में से न्यूजीलैंड को खेलभावना के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार मिला.

एक जमाने में लखनऊ हॉकी का गढ़ माना जाता था. भारतीय हॉकी का डंका पूरे विश्व में बोलता था और उसमें यूपी के कई सितारे दुनिया में चमकते दिखते थे. हॉकी के जनक मेजर ध्यानचंद ने पूरे विश्व के खेल पटल पर भारतीय हॉकी को भारतीय पहचान और प्रतिष्ठा दी. केडी सिंह बाबू से लेकर मोहम्मद शाहिद जैसे खिलाड़ियों ने अपनी जादुई हॉकी से देश का झंडा बुलंद किया. लखनऊ के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में विश्व कप देखने के लिए जुटे अपार जनसमूह को देख कर यही समझा गया कि हॉकी की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से स्थापित करने की छटपटाहट उनमें कितनी है. भारत और बेल्जियम के बीच खेले गये फाइनल मैच को देखने के लिए सडकों से लेकर स्टेडियम तक लगी लोगों की भारी भीड़ अजीबोगरीब जुनून की अभिव्यक्ति दे रही थी. आखिरी तक टिकटों को लेकर मारामारी देखी गई. यह हॉकी के लिए बेहद सुखद पल था, क्योंकि अक्सर क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग ऐसे लालायित होते दिखते हैं. आमतौर पर क्रिकेट के मैचों को लेकर टिकटों की लम्बी लाइन देखी जाती है. लेकिन हॉकी मैच के टिकट काउंटर बेहद कम समय में ही सारे टिकट बेच कर बंद हो चुके थे, इसने एक रिकॉर्ड ही कायम किया. गुड़गांव में नौकरी करने वाले अभिषेक मैच देखने ही लखनऊ आए थे, जिन्हें टिकट हासिल करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी. स्टेडियम समय के पहले ही पूरी तरह भर चुका था. जगह बनाने के लिए दर्शक दीर्घा में पीछे की सीढ़ियों पर लगी एफआईएच की होर्डिंग को भी हटाना पड़ा. भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए लोग सीढ़ियों पर खड़े हो गए थे. यहां तक कि दर्शक स्टेडियम के चारों कोनों पर लगे विशालकाय स्कोर बोर्ड पर भी सवार दिख रहे थे. महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर भी सर्द मौसम का कोई असर नहीं था. बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी अपने हाथों में तिरंगा लिए भारतीय टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे. अनगिनत लोग अपने चेहरे के दोनों तरफ तिरंगे के स्टिकर चिपकाए थे, या चेहरे पर तिरंगे की पेंटिंग करा रखी थी. मैच देखने के लिए लोगों ने अपने कारोबार तक बंद कर दिए थे. हॉकी के कई शौकीन अलग तरह की पोशाकों में भी नजर आए. मैच शुरू होने से पहले ही पूरा स्टेडियम दूधिया रौशनी में नहा गया था. लोग लगातार मोबाइल पर सेल्फी लेने में जुटे रहे. डीजे संगीत पर पूरा स्टेडियम थिरक रहा था. स्टेडियम में यूपी वाला ठुमका लगाकर गाने पर लोग खूब झूमे और भोजपुरी गाना लगाबे लू जब लिपस्टिक पर खूब मस्ती की. खचाखच भरे स्टेडियम में जर्मनी की टीम भी मौजूद थी. खासतौर पर जर्मन टीम भारत का मैच देखने पहुंची थी. भारतीय टीम का जोश देखकर स्टार खिलाड़ी मैक्स ने भी भारत की जीत की खुशी में तिरंगा लहराया. लखनऊ के दर्शकों ने न केवल भारतीय टीम बल्कि विदेशी टीमों के साथ खूब सौहार्द का प्रदर्शन किया और उनका उत्साह बढ़ाया. खेल की शुरुआत में लखनऊ के दर्शक न केवल भारतीय राष्ट्र गान पर बल्कि विदेशी टीमों के सम्बद्ध राष्ट्र गान पर भी खड़े होकर अपना सम्मान ज्ञापित करते थे. इसे विदेशी टीमों ने काफी सराहा.■

feedback@chauthiduniya.com

बॉलीवुड के लिए कैसा रहा 2016

सलमान-अक्षय का रहा जलवा

नीरजा और पिंक अवॉर्ड शो में छाई

सिर्फ सात फिल्में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकीं

सलमान की फिल्म सुल्तान ने 2016 में कमाई के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया, वहीं इस साल अक्षय कुमार सभी अभिनेताओं पर भारी पड़े. अक्षय ने 2016 में लगातार तीन फिल्में 100 करोड़ के ऊपर की दी हैं. 2016 में अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट, हाउसफुल-3 और रुस्तम तीनों ने 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार किया. यह पूरा साल अक्षय कुमार और सलमान के नाम ही रहा.

प्रवीण कुमार
feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2016 ख़त्म हो चुका है और बॉलीवुड के नज़रिए से इसमें कई उतार-चढ़ाव भी देखने को मिले. ऐसे में अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो यह साल बॉक्स ऑफिस के लिए ठीकठाक ही रहा. ख़ासकर छोटे बजट की फिल्मों का बोलबाला ज्यादा रहा. जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया. बड़े बजट की फिल्मों में *सुल्तान* ही एकमात्र ऐसी फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की और 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई. इसके अलावा कुछ बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जहां सलमान की फिल्म सुल्तान ने 2016 में कमाई के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया, वहीं इस साल अक्षय कुमार सभी अभिनेताओं पर भारी पड़े. अक्षय ने 2016 में लगातार तीन फिल्में 100 करोड़ के ऊपर की दी हैं. 2016 में अक्षय कुमार की *एयरलिफ्ट, हाउसफुल-3* और *रुस्तम* तीनों ने 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार किया. यह पूरा साल अक्षय कुमार और सलमान के नाम ही रहा. वहीं सबसे चौंकाने वाली बात शाहरूख खान की फिल्म फैन को लेकर रही. अक्सर फिल्म को हिट कराने के लिए शाहरूख खान का नाम ही काफी होता है, लेकिन फैन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और फ्लॉप साबित हुई. इसका एहसास शाहरूख खान को आज भी है और अब उनकी उम्मीदें जनवरी 2017 में आने वाली फिल्म *रईस* से काफी बढ़ चुकी है.

इसके अलावा साल 2016 में दो फिल्मों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. पहली, अगस्त माह में अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन के बीच *रूस्तम* और *मोहन जोदाड़ो* में देखने को मिली. जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म रूस्तम ने बाज़ी मार ली और ऋतिक की मोहन जोदाड़ो उनके करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई.

वहीं दूसरी ओर अजय देवगन की मोस्ट अवेटिंग फिल्म *शिवाय* और *ऐ दिल है मुश्किल* में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली. इन दोनों फिल्मों में आखिरी समय तक जंग चली, जिसमें ऐ दिल है मुश्किल कमाई के मामले में अजय की शिवाय से आगे रही. लेकिन शिवाय को दर्शकों ने काफी पसंद किया और अजय के शानदार निर्देशन के लिए दर्शकों ने उनको बधाई भी दी. इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का बिजनेस किया.

साल 2016 कुछ फिल्मों के लिए रूलाने वाला भी साबित हुआ. इस साल कई फिल्में सिनेमाघरों में आने से पहले ही लीक हो गईं, जिसका ख़ामियाजा बॉक्स ऑफिस और फिल्म के निर्माताओं को भुगतना पड़ा. फिल्म *उड़ता पंजाब* और *द ग्रेट ग्रांड मस्ती* इसका उदाहरण हैं. फिल्मों का लगातार लीक होना अब आम बात हो चुकी है. इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अब कई वेबसाईट्स को बंद कर दिया है, जिनके जरिए फिल्मों को लीक किया जाता था. लीक करने वालों के लिए भारत सरकार ने कड़े कानून भी बनाए हैं. आइए जानते है साल 2016 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड. क्या रहा सुर्खियों में और कौन रहा हिट और फ्लॉप?

अक्षय कुमार– साल 2016 की शुरुआत जनवरी में आई फिल्म *वज़ीर* और *क्या कूल है हम-3* से हुई, पर दर्शकों ने इसे नकार दिया और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा सकीं. इसके बाद आई अक्षय कुमार की फिल्म *एयरलिफ्ट*. यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसका निर्देशन राजा कृष्ण मेनन ने किया था. रंजीत कटियाल की प्रेरणा, मैथ्युज और वेदी नामक दो भारतीयों से ली गई है, जिन्होंने 1990 में कुवैत में फंसे एक लाख सत्तर हजार भारतीयों की वापसी में अहम भूमिका निभाई थी, जब वहां पर सद्दाम हुसैन की इराकी सेना ने हमला बोल दिया था. यह ऐसी घटना है जिसमें कई गुमनाम हीरो ने बहादुरी दिखाई और उनकी चर्चा भी नहीं हुई. यह फिल्म सुपरहिट रही और इसके जरिए बॉलीवुड को 2016 की पहली सुपरहिट फिल्म मिली. एयरलिफ्ट में रंजीत कटियल की भूमिका में अक्षय का रोल शानदार था. एयरलिफ्ट के अलावा खिलाड़ी अक्षय कुमार ने रुस्तम और हाउसफुल-3 जैसी फिल्में भी की हैं, जो हिट रहीं.

सोनम कपूर– अभिनेत्रियों में सोनम कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर पहली सुपरहिट फिल्म का आगाज़ *नीरजा* से किया. फरवरी माह में सोनम कपूर की फिल्म नीरजा आई, जिसे राम माधवानी ने निर्देशित किया था. यह फिल्म भी एक सच्ची घटना पर बेस्ड फिल्म थी. 1986 में भारत से अमेरिका जा रहे विमान का चार आतंकवादियों ने अपहरण करके जब कराची (पाकिस्तान) में उतारा, तो उसमें 360 से अधिक यात्री थे. मात्र 23 वर्ष की नीरजा विमान की मुख्य परिचारिका थीं. निर्देशक राम माधवानी ने नीरजा के जीवन के आखिरी दो दिनों, विमान अपहरण और यात्रियों को बचाने के घटनाक्रम को विश्वनीय ढंग से पर्दे पर उतारा. फिल्म नीरजा बहुत शानदार तरीके से बनाई गई और सोनम कपूर ने इसमें शानदार अभिनय किया. नीरजा में शानदार अभिनय के लिए सोनम कपूर को कई अवॉर्ड भी मिल चुके हैं. कहना गलत नहीं होगा कि नीरजा सोनम कपूर के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है.

अनुष्का शर्मा– 2016 अनुष्का शर्मा के लिए बेहतरीन रहा. ईद के मौक पर आई फिल्म *सुल्तान* में अनुष्का शर्मा ने रेसलर का एक अहम किरदार निभाया, जिसमें उनका साथ सालमान खान ने दिया. फिल्म ब्लॉकबस्टर रही. इसके बाद दीवाली पर आई *ऐ दिल है मुश्किल* ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और फिल्म ने 100 करोड़ के पार का बिजनेस किया. आज के समय में अभिनेत्रियों की लिस्ट में अनुष्का शर्मा नंबर एक अभिनेत्री मानी जाती हैं. कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा लगता है कि वह जिस फिल्म में काम करती हैं, उस फिल्म को हिट होने से कोई रोक नहीं सकता. वैसे अनुष्का शर्मा किस्मत की धनी हैं, जिन्हें तीनों खानों के साथ काम करने का मौका मिला.

सलमान खान– ये तो मानना ही पड़ेगा कि सलमान की फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर आती हैं, तो तूफ़ान मचा देती है. किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह सलमान से टक्कर ले सके. ईद हमेशा से खान्स बंधुओं के नाम ही रहती है और सलमान खान से अच्छी ईदी भारतवासियों को शायद ही कोई दे. ईद के मौके पर आई सालमान खान की साल की सबसे बड़ी फिल्म *सुल्तान* ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया. सुल्तान अली खान के रूप में सलमान का ऐसा तूफ़ान आया कि बस सब देखते ही रह गए और फिल्म ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्डवाइड लगभग 584 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया. सुल्तान 2016 की ब्लॉकबस्टर फिल्म की लिस्ट में शामिल है.

श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ– बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की आई एक्शन फिल्म *बाग़ी* को दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म में वो सब कुछ था, जिसे देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खिंचे चले आए. अच्छी स्क्रिप्ट शानदार एक्शन और गाने फिल्म बाग़ी को हिट कराने के लिए काफी थे. श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया. फिल्म हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ का व्यवसाय किया.

अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू– फिल्म *पिंक* का निर्देशन अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने किया है. यह फिल्म उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा जड़ती है, जो लड़कियों के जींस या स्कर्ट पहनने पर सवाल उठाते हैं. अदालत में अमिताभ बच्चन व्यंग्य करते हैं कि हमें *सेव गर्ल* नहीं बल्कि *सेव बॉय* पर काम करना चाहिए क्योंकि जींस पहनी लड़कियों को देख लड़के उत्तेजित हो जाते हैं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं. फिल्म में इस सीन को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है. यह सीधे तौर पर दर्शकों के दिमाग पर छाप छोड़ता है. यह फिल्म रूढ़िवादी परंपरा पर सीधी चोट करती है. फिल्म में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू का अभिनय शानदार था.

उड़ता पंजाब और द ग्रेट ग्रांड मस्ती– 2016 में पाइरेटेड फिल्मों को लेकर भी बहुत बवाल हुआ. वैसे किसी फिल्म की पाइरेटेड सीडी का मार्केट में आना नई बात नहीं है, पर इस साल पाइरेटेड फिल्मों का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा. जिसके कारण बहुत सी फिल्में रिलीज से पहले ही वेबसाईट्स पर लीक हो गईं. जिसका नुकसान फिल्म के निर्देशकों को उठाना पड़ा. फिल्म *उड़ता पंजाब* तो एचडी प्रिंट के साथ लीक हो गई. फिल्म ने जैसे तैसे 60 करोड़ तक का कारोबार कर अपनी लागत तो वसूल कर ली पर फिल्म को काफी नुकसान उठाना पड़ा. फिल्म नशाखोरी और गाली-गलौच को लेकर पहले से ही सुर्खियों में थी जिसे लेकर फिल्म को पहले ही कई राज्यों में बैन करने की मांग की गई थी.

वहीं दूसरी ओर द ग्रेट ग्रांड मस्ती का हाल तो ऐसा हुआ कि फिल्म के सभी कलाकारों को रोना आ गया. फिल्म अपनी रिलीज डेट से लगभग 15 दिन पहले ही लीक हो गई, जिसका पता फिल्म के निर्देशक और बाकी कलाकारों को भी नहीं चला. एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान फिल्म की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला तो पत्रकारों से बातचीत करते वक्त ही रो पड़ी थी. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर की लिस्ट में डालना पड़ा.

सुशांत की पहली 100 करोड़ की फिल्म– एमएस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी में दमदार अभिनय करने वाले सुशांत राजपूत अब बड़े स्टार्स की लिस्ट में आ चुके है. फिल्म देखने के बाद लगभग सभी का यही कहना था कि सुशांत जैसा अभिनय शायद ही इस फिल्म में कोई कर पाता. निश्चित तौर पर फिल्म में धोनी के किरदार में सुशांत एकदम फिट दिखाई दिए हैं. फिल्म भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी के जीवन पर आधारित थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 134 करोड़ रुपये का बिजनेस किया और यह सुशांत के करियर की यह पहली 100 करोड़ी फिल्म बनी. बताया जाता है कि फिल्म हिट होने के बाद से सुशांत ने अपनी फीस भी बढ़ा दी है.

अजय और करण जौहर में कड़ी जंग– 2016 में बॉक्स ऑफिस पर असली जंग देखने को मिली है तो सिर्फ *शिवाय और ऐ दिल है मुश्किल* को लेकर अजय व करण जौहर के बीच. दीवाली के अवसर पर इन दोनों बड़ी बजट की फिल्मों में आखिरी तक कड़ी टक्कर देखने को मिली. करण जौहर की इस फिल्म ने विदेशों में अच्छी कमाई कर शिवाय को पीछे कर दिया पर भारत में दोनों ही फिल्मों का जबरदस्त रिकॉर्ड रहा. दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से ऊपर का बिजनेस किया. अजय देवगन की फिल्म शिवाय साल की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटिंग फिल्म रही. शिवाय अजय की ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म थी, जिसका निर्देशन भी खुद अजय देवगन ने ही किया है. दर्शकों को शिवाय इतनी पंसद आई कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अजय से शिवाय का सीक्वल बनाने को लेकर भी रिक्वेस्ट किया.

जॉन अब्राहम– इस साल जॉन की आई तीन फिल्में रॉकी हैंडसम (26.41 करोड़), दिशूम (70 करोड़) और फोर्स-2 (37.50) बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा सकीं. दिशूम ने थोड़ी बहुत कमाई की, पर फिल्म में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि दर्शक फिल्म को आगे प्रमोट कर पाते. इन तीनों फिल्मों की कमाई जोड़ कर जॉन अब्राहम ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर कुल 135 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया, जो उनकी लोकप्रियता के हिसाब से बहुत बुरा रिकॉर्ड है.

साल के अंत में नवंबर माह के दौरान भारत सरकार द्वारा नोटबंदी के बाद से बॉक्स ऑफिस पर आई सभी फिल्में औंधे मुंह गिरीं और बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस को काफी नुकसान उठाना पड़ा. *डियर जिंदगी* के अलावा किसी भी अन्य फिल्म ने कमाई नहीं की और जितनी भी फिल्में आई लगातार फ्लॉप होती चली गईं. वहीं पूरे साल आईं कुछ छोटे बजट की फिल्मों ने बाज़ी मारी, जिनमें सनम रे, जय गंगाजल, सरबजीत, कपूर एंड सन्स, हैप्पी भाग जाएगी आदि फिल्में शामिल हैं.

साल के अंत में आमिर खान की फिल्म दंगल रिलीज हुई. फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई कर ली है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है. देखते हैं, आने वाले दिनों में दंगल कमाई को लेकर कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाती है.■

सिर्फ सात फिल्में 100 करोड़ क्लब में

साल 2016 में एक तरफ जहां *सुल्तान* 300 करोड़ क्लब में शामिल हुई, वहीं दूसरी ओर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों की भी भरमार रहीं. इस साल कई बड़ी फिल्में आईं, लेकिन सिर्फ 7 फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकीं. आइए जानते हैं, किन-किन फिल्मों की 100 करोड़ क्लब में एंट्री हुई.

1. **सुल्तान–** सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने 300.45 करोड़ की कमाई की है.
2. **एम एस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी–** सुशांत सिंह राजपूत स्टार फिल्म एम एस धोनी ने 132.85 करोड़ का कलेक्शन किया है.
3. **एयरलिफ्ट–** अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट ने 129 करोड़ का कलेक्शन किया है.
4. **रूस्तम–** अक्षय की ही दूसरी फिल्म रूस्तम ने 127.42 करोड़ की कमाई की है.
5. **ऐ दिल है मुश्किल–** करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल ने 112.14 करोड़ का कारोबार किया है.
6. **हाउसफुल 3 –** फिल्म हाउसफुल 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 107.70 करोड़ का कलेक्शन किया.
7. **शिवाय–** अजय देवगन की शिवाय सातवीं ऐसी फिल्म रही, जो इस लिस्ट में शामिल हुई. फिल्म ने 100.30 करोड़ का कलेक्शन किया.